अमर उजाला
प्रवाह
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948
नई दिल्ली ■ शुक्रवार, 20 दिसंबर 2024

अपने दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने की क्षमता ही असली नेतृत्व है। -वारेन बेनिस

डॉ. आंबेडकर के मूल्यों की परवाह न कर महज प्रतीकों की राजनीति मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश ही ज्यादा लगती है। चयनात्मक ढंग से केवल सुविधाजनक तथ्यों को स्वीकारने में किसी का फायदा नहीं है। बातें व मुद्दाएं बनाने से बेहतर तो यही होगा कि सब मिलकर जन-कल्याण के रास्ते तलाशें।

प्रतीकों की लड़ाई

संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूर्ण हुए अभी एक महीना भी नहीं गुजरा था कि गृह मंत्री के राज्यसभा में भाषण के दौरान संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर से जुड़ी उनकी टिप्पणी पर संसद के दोनों सदनों में जिस तरह से भारी विवाद और हंगामा देखने को मिला, वह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार हंगामों के चलते शीतकालीन सत्र का काफी समय पहले ही बर्बाद हो चुका है और अब इस मुद्दे को लेकर दोनों सदनों के पूरे दिन के लिए स्थगित होने से यही जाहिर होता है कि संसद, जो नीति निर्माण और जनता की समस्याओं के समाधान का मंच है, अब विवाद और आरोप-प्रत्यारोप का अखाड़ा बनती जा रही है। भारतीय संविधान के शिल्पकार के योगदान को किसी विचारधारा या दल विशेष तक सीमित नहीं किया जा सकता। उनका जीवन और कर्म तो हर भारतीय के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। लेकिन संसद में जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं, वे न केवल संसदीय गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले हैं, बल्कि ये आंबेडकर की विरासत के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े करते हैं। वर्तमान दौर में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए विभिन्न दलों में आंबेडकर को अपनाने और उनके नाम के इस्तेमाल की होड़ समझी जा सकती है। लेकिन उनके बुनियादी मूल्य क्या हैं, इसे लेकर चयनात्मक दृष्टि रखते हुए वोट बैंक की राजनीति करना वांछित नहीं और इस लिहाज से फिलहाल चल रही पंचायत मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश ही ज्यादा लगती है। दलितों और बहुजन की राजनीति जब केंद्र में आई, तब आंबेडकर को पर्याप्त चर्चा में लाया गया। आंबेडकर को देर से मिले भारत रत्न के आलोक में भी इसे समझा जा सकता है। आज प्रतीकों व पहचान की लड़ाई लड़ते हुए दलितों व अल्पसंख्यकों की बात उठाने वाले राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि असुविधाजनक तथ्यों से बचते हुए सुविधाजनक सत्यों को स्वीकारने में किसी का फायदा नहीं है। आंबेडकर का सम्मान केवल शब्दों में नहीं, आचरण में भी दिखना चाहिए। संसदीय कार्यवाही के बार-बार बाधित होने से महत्वपूर्ण विधेयक लंबित रह जाते हैं, नीतिगत चर्चाएं ठप हो जाती हैं और करदाताओं के धन का भी अपव्यय होता है। संसद को हंगामे का नहीं, बल्कि संवाद व सहमति का मंच होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को निर्बाध ढंग से चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन विपक्ष को भी अपनी बात रखने के व्यवस्थित व रचनात्मक तरीके अपनाने चाहिए। बातें व मुद्दाएं बनाने से कुछ नहीं होगा। राजनेता सुविधा और परिस्थितियों के अनुसार काम करते हैं। लेकिन इससे जनता का कोई फायदा नहीं होता। अलबत्ता होना तो यह चाहिए कि पक्ष व विपक्ष मिलकर जनता के कल्याण के रास्ते तलाशें।

जीवन धारा

धीरेंद्र वर्मा

बचपन और बड़ी उम्र में भेद यह होता है कि पहले हर बात कहानियों के अनुभव से जांची जाती है। बाद में संसार के प्रत्यक्ष और कठिन अनुभव से। अंत में एक ही बात समझ आती है, अजब दुरंगी दुनिया है।

अजब दुरंगी दुनिया है

सत्य क्या है, अथवा सबसे उत्तम मार्ग कौन-सा है, इसका निरपय करना बहुत दुष्कर है। संसार में इतने धर्म हैं, इससे यही प्रकट होता है कि सत्य को जानना कितना कठिन है। एक ओर एक बूढ़ा मनुष्य जनेऊ पहने, माथे पर चंदन लगाए, स्नान करके, कुश के आसन पर बैठा गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है। दूसरी ओर जूते और कपड़े पहने, गिरजाघर में खड़ा हुआ एक मनुष्य आंखें मूंदकर ईसा मसीह से पापों को दूर करने की प्रार्थना कर रहा है। तीसरी जगह मुल्ला साहब मस्जिद में घुटनों के बल बैठे हुए 'या मुहम्मद रसूल अल्लाह' को श्रद्धापूर्वक पढ़ रहे हैं। इसमें कौन ठीक है? ऐसा मालूम होता है कि दुनिया में सत्य और झूठ कुछ भी नहीं है, अथवा एक ही बात सच्ची और झूठी, दोनों हैं।

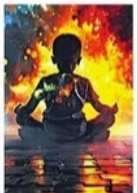

जिन बातों को बचपन से सत्य और उत्तम कहकर बताया जाता है, उन्हें लोग अच्छा समझते हैं, और जिनको झूठ और खराब बताया जाता है, उन्हें बुरा समझते हैं। एक आदमी कच्चे मांस को देखकर घृणा के कारण मुंह फेर लेता है, और दूसरा मुंह में पानी भरकर टकटकी लगाकर उसी को देखता है। क्या यह शिक्षा का प्रभाव नहीं है। इनमें कौन ठीक है? कुछ विद्वानों ने सत्य और असत्य को जानने के लिए बहुत परिश्रम के बाद कुछ सिद्धांत रचे हैं। किंतु यह भी अलग-अलग हैं। एक कहता है कि जो आंखों से दिखाई दे, वह अवश्य है। किंतु दूसरी ओर एक धुरंधर विद्वानों की मंडली कहती है कि जो कुछ दिखाई पड़ता है, वह भ्रम मात्र है। हद हो गई! कैसे पता चले कि इनमें कौन ठीक है? एक आदमी ईश्वर को मानता है, दूसरा इस विचार की हंसी उड़ाता है। यह नहीं है कि देश अथवा काल के कारण यह कठिनाई पड़ती हो। एक ही घर में चार आदमी बिल्कुल अलग-अलग ख्याल के मिलेंगे। फिर पता कैसे चले कि इनमें ठीक कौन है? बचपन और बड़ी उम्र में सब से बड़ा भेद यह होता है कि पहली अवस्था में प्रत्येक बात कहानियों के अनुभव से जांची जाती है, तथा दूसरी अवस्था में संसार के प्रत्यक्ष और कठिन अनुभव से। एक ऐसा समय आता है, जब पुराने सुख नए सुखों में धीरे-धीरे बदल जाते हैं। पढ़ने में एक विशेष आनंद आने लगता है। इसका कारण पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों के विषय नहीं होते, किंतु दर्जे में सबसे आगे बैठने या परीक्षाओं में सबसे अधिक नंबर फटकाने का शौक होता है। इस समय स्कूल जाने, और स्कूल से लौटकर स्कूल का ही काम करने में सब समय लग जाता है। कभी-कभी घर के बड़े लोगों को देश की दुर्दशा का वर्णन करते सुन दुख अवश्य होता है। यह भी विचार उठते हैं कि मैं ही क्यों न देश का उद्धारकर्ता होऊं? स्कूल से निकलते ही एक नवीन संसार में प्रवेश करना होता है। प्रारंभ में यह संसार आशापूर्ण दिखाई पड़ता है, किंतु धीरे-धीरे ज्यों ही समय बीतता जाता है, संसार के असली स्वरूप का दर्शन होने लगता है। संसार की कठिन उलझनें व प्रत्यक्ष अनुभव कभी-कभी एक प्रकार की निराशा उत्पन्न कर देते हैं। किंतु यह शीघ्र ही दूर हो जाती है और फिर मनुष्य इस चक्र में खुशी-खुशी पड़ने को उद्यत हो जाता है। अंत में एक ही बात समझ आती है, अजब दुरंगी दुनिया है।

क्या दुनिया ट्रंप के लिए तैयार है

ओसाका से लेकर मुंबई और न्यूयॉर्क तक के बाजारों में निवेशक ट्रंप द्वारा शपथ लेने के बाद के परिदृश्यों को समझने के लिए जूझ रहे हैं। वैश्विक सम्मेलनों में ट्रंप की अदृश्य मौजूदगी है। मुमकिन है कि टैरिफ की धमकी बातचीत का एक साधन हो। लेकिन यह तय है कि ट्रंप के युग में जुड़ाव की शर्तें और समझौते फिर से तय होंगे।

'शक्ति कोई साधन नहीं है, यह साध्य है। शक्ति का उद्देश्य शक्ति ही है।' डोनाल्ड जे ट्रंप ने जॉर्ज ऑरवेल के अमर वाक्य को आत्मसात किया है और इसे अक्षरशः एवं भावना के स्तर पर मूर्त रूप दिया है। लगभग एक महीने बाद यानी 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। उनकी 1927 में बनी, 20 एकड़ में फैली 128 से अधिक कमरों वाली 'मार-ए-लागो' प्राचीन वस्तुओं से सजी हवेली, जिसके ऊपर 70 फुट ऊंचा अमेरिकी झंडा लहराता है, राजनीतिक तीर्थस्थल है।

तीर्थयात्रियों में कीर स्टार्मर, वोलोदिमीर जेलेंस्की, जेवियर माइली और जस्टिन ट्रूदो शामिल हैं, जबकि मेक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम जैसे अन्य लोग उन्हें फोन करते हैं। उनकी वापसी पर संदेह करने वाले मेटा के मार्क जुकरबर्ग और एपल के टिम कुक जैसे कॉरपोरेट दिग्गजों ने भी आकर उनका अभिवादन किया। अमेजन के जेफ बेजोस अगले हफ्ते ट्रंप से मिलने वाले हैं। और सभी शपथ ग्रहण समारोह के लिए लाखों डॉलर का योगदान दे रहे हैं। उनके दर्शनार्थ आने वाले महानुभावों के मद्देनजर प्रयुक्त रूपकों में 18वीं और 19वीं शताब्दी के शाही दरबारों में देखी गई मुद्राएं शामिल हैं यह फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की द गॉडफादर फिल्म में छोटे डॉन द्वारा वफादारी दिखाने के लिए अंगूठी चूमने का सिनेमाई चित्रण।

शंकर अय्यर
वरिष्ठ पत्रकार

ट्रंप खुद को न केवल कमांडर इन चीफ के रूप में देखते हैं, बल्कि मुख्य राजनयिक, मुख्य व्यापार वार्ताकार और भू-राजनीति और महत्वपूर्ण मुद्दों के मध्यस्थ के रूप में भी देखते हैं। ट्रंप के पास प्रोटोकॉल की बारीकियों के लिए समय नहीं है। उनकी घोषणाएं ट्रुथ सोशल पर स्ट्रीम करती हैं और एक्स (पूर्व ट्विटर) पर फिर से पोस्ट की जाती हैं। चीन पहले ही उनके निशाने पर है, जिसे 50 फीसदी से ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है। हाल में, उन्होंने अवैध प्रवासन और ड्रग्स के मुद्दे पर मेक्सिको और कनाडा को धमकी दी है। उन्होंने ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है कि वे 'शक्तिशाली अमेरिकी डॉलर को बदलने की कोशिश न करें अन्यथा उन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया जाएगा।' ट्रंप की वापसी ने अमेरिकी बाजारों को चुनाव के बाद की शानदार ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। हालांकि, दुनिया भर में घबराहट है। वैश्विक स्तर पर रुपया सहित सभी मुद्राएं गिर रही हैं। ओसाका से लेकर मुंबई और न्यूयॉर्क तक के बाजारों में निवेशक 20 जनवरी के बाद के परिदृश्यों को समझने के लिए जूझ रहे हैं। सम्मेलनों में ट्रंप की अदृश्य मौजूदगी है और वैश्विक बैठकों, सरकारों और कंपनी सी-सूट्स में उनका नाम चर्चा में रहता है। हालांकि बाइडन प्रशासन अब भी सत्ता में है, लेकिन ट्रंप अपने नाम और काम की ताकत को पेश करने में लगे हैं। बस दो मनोनयन पर विचार कीजिए। मनोनीत विदेश मंत्री मार्को रुबियो जाने-माने कट्टर चीन विरोधी हैं और पैट्रियोटिक इन्वेस्टमेंट एक्ट के लेखक हैं, जिसका उद्देश्य अमेरिकी कर संहिता को चीन में निवेश को प्रोत्साहित करने से रोकना है।

रुबियो यह भी चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियां चीन से बाहर निकल जाएं। वाणिज्य सचिव पद के लिए चुने गए हॉवर्ड लुटनिक को सभी क्षेत्रों में उच्च टैरिफ के समर्थक के रूप में जाना जाता है। लक्ष्य के प्रति निष्ठा सर्वोपरि है। इरादा यह है कि बाहर से आने वाली सभी चीजों के मार्ग को कठिन बनाया जाए-खासतौर पर वस्तुओं और प्रवासियों को और केवल एफडीआई को अनुमति दी जाए। बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा करने का साधन है टैरिफ, इसके साथ ही एलन मस्क के नेतृत्व वाले प्रस्तावित सरकारी दक्षता विभाग द्वारा हल्के विनियमन और छोटी सरकार का वादा, और अमेरिका में निवेश के लिए कर छूट। ट्रंप पहले से कहीं ज्यादा तैयार दिखते हैं। उनकी शक्ति अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आकार और 'अमेरिका को फिर से महान बनाने' के वादे से उपजी है। ट्रंप अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर से संगठित करना चाहते हैं। 1970 के दशक के बाद अमेरिकी कंपनियों ने एक त्रिपक्षीय मॉडल विकसित किया, जहां उन्होंने उत्पाद डिजाइन किए, टेक्नोलॉजी का पेटेंट अपने पास रखा और विनिर्माण एवं श्रम आउटसोर्स किया। नीति पर नियंत्रण से निवेश, विनिर्माण नौकरियों, आय और विकास का निर्वात हुआ। इसने समाज में एक उच्च आय का क्षेत्र बनाया और अमेरिकी अर्थव्यवस्था से निवेश और रोजगार खत्म कर दिया, जिससे आम जनता आय और उपभोग के दायरे से बाहर हो गई। ट्रंप को इसका एहसास है कि उन्हें भारी बहुमत मिला है और वह अपने मतदाताओं की भावनाओं के प्रति संवेदनशील हैं। ट्रंपोनॉमिक्स, मूलतः अतीत के गौरव को बहाल करने और मौजूदा व्यवस्थाओं को खत्म करने का वादा है।

हालांकि विशेषज्ञ उच्च टैरिफ दीवार और आप्रवासियों के जबरन निर्वासन के खिलाफ तर्क दे रहे हैं कि दोनों ही मुद्रास्फीति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ट्रंप दृढ़ हैं। ट्रंप की योजना चीन से आने वाले सामान और अन्य देशों द्वारा माल के उत्पादन के लिए आयात किए जाने वाले घटकों को लक्षित करने की है। इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा-डॉलर के मजबूत होने से पैसे की लागत बढ़ सकती है, टैरिफ से इनपुट महंगे हो जाएंगे और अमेरिकी सामानों के लिए बाजार खोलने से स्थानीय उत्पादकों पर असर पड़ेगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था और सहयोगियों के साथ संबंधों को होने वाले संभावित नुकसान को कोई खास महत्व नहीं दिया जा रहा है। आशावादी लोग मानते हैं कि ट्रंप व्यापारी हैं और टैरिफ की धमकी बातचीत का एक साधन है। यह कुछ हद तक सच हो सकता है। लेकिन एक असमान दुनिया में-डॉलर सबसे बड़ी आरक्षित मुद्रा है और अमेरिका सबसे बड़ा आयातक है-जुड़ाव की शर्तें फिर से तय होंगी और समझौते करने होंगे।

ऐसा लगता है कि धमकियों का असर हो रहा है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने यूरोपीय संघ को अमेरिकी (हथियार और तरल प्राकृतिक गैस) खरीदने और ट्रंप के व्यापार युद्ध से बचने की सलाह दी। नाटो सदस्य, जो पहले अपने रक्षा खर्च को जीडीपी के दो प्रतिशत तक नहीं बढ़ाते थे, अब इसे तीन प्रतिशत तक बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप की जीत ने सदमे और विस्मय की लहर पैदा कर दी, क्योंकि उनकी पार्टी ने राष्ट्रपति पद, दोनों सदनों और विचारधारा से जुड़ी न्यायपालिका के चतुर्भुज पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। सत्ता में उनके उदय ने दुनिया को अनिश्चितता के गर्त में छोड़ दिया है। ट्रंप जोखिम भरा दांव खेल रहे हैं। मगर सवाल है कि परस्पर निर्भरता की दुनिया में क्या यह दांव कारगर होगा और क्या दुनिया इसके लिए तैयार है?

edit@amarujala.com

सही-गलत के फेर में न पड़ें

सूत्र

सही-गलत की परिभाषा के पीछे न भागें। जब तक जीवन है, तब तक सब के साथ प्रेम, स्नेह से रहें। अंत में, आपके जीवन के वर्ष मायने नहीं रखते, बल्कि आपका वर्षों में बिताया गया जीवन मायने रखता है। सर्दियों की गहराई में, आपके भीतर एक अजेय ग्रीष्म ऋतु छिपी हुई है। याद रखें, भविष्य उनका है, जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं।

दूसरा पहलू

दवाएं हमारी आंत में मौजूद विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं पर कहर बरपा सकती हैं, इसलिए आहार पर ध्यान देना जरूरी है।

एंटीबायोटिक्स से आंत को बचाना है, तो लें फाइबर

वर्ष 1928 में जब पेनिसिलिन की खोज की गई थी, तब यह जीवन के लिए घातक संक्रमण के इलाज में वरदान साबित हुआ था। लेकिन अब यह एंटीबायोटिक हमारे खराब जीवाणुओं (बैक्टीरिया) के साथ ही अच्छे बैक्टीरिया को भी खत्म कर रहा है। चिकित्सक जब किसी मरीज को एंटीबायोटिक्स लेने की सलाह देते हैं, तो उसके मन में कई सवाल उठते हैं। एक मरीज का कहना है कि उसे एंटीबायोटिक्स की सलाह दी गई है, लेकिन उसे इस बात की चिंता है कि यह उसकी आंत के अच्छे बैक्टीरिया को भी नष्ट कर सकता है। क्या इस नुकसान को कम करने का कोई उपाय है?

इसोबेल रिहटकॉम्ब

यूसीएलए जिल्ट के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. टीएन डोंग कहते हैं कि ज्यादातर लोगों में एंटीबायोटिक्स आंत के माइक्रोबायोम (सूक्ष्म जीवाणु) पर अस्थायी असर डालते हैं। यदि आपकी सेहत अच्छी है, तो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। डॉ. डोंग के अनुसार, एंटीबायोटिक्स हमारे पेट में मौजूद सूक्ष्म जीवाणुओं पर उसी तरह असर डालते हैं, जैसे जंगल की आग वृक्षों और जानवरों को प्रभावित करती है। आग में खरपतवार के जलने पर अच्छे पौधे फिर उग आते हैं, ऐसे ही रोग ठीक होने पर अच्छे बैक्टीरिया भी फिर से सक्रिय हो जाते हैं। माइक्रोबियल जीनोमिस्ट डॉ. एमी लैंगडन का कहना है कि अच्छी बात यह है कि मुख से लिए जाने वाले एंटीबायोटिक्स संपूर्ण मूल बैक्टीरिया को नहीं मारते हैं। सवाल यह है कि एंटीबायोटिक्स लेने के बाद क्या खाना चाहिए? यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना कैंसर सेंटर के इम्युनोबायोलॉजिस्ट डॉ. पावेल कोला के अनुसार, एंटीबायोटिक्स लेने के बाद हमारा आहार 'अच्छे' जीवाणुओं की वृद्धि में मदद और 'बुरे' जीवाणुओं को हतोत्साहित करता है। डॉ. कोला बताते हैं कि आंत के स्वस्थ बैक्टीरिया फाइबर पसंद करते हैं।

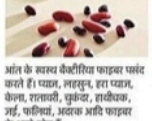

आंत के स्वस्थ बैक्टीरिया फाइबर पसंद करते हैं। प्याज, लहसुन, हरा प्याज, केला, शतावरी, फुकेंदा, हाथीचक, जई, फलियां, अदाक आदि फाइबर के अच्छे स्रोत हैं

वर्ष 2021 में चूहों पर हुए शोध के मुताबिक एंटीबायोटिक्स देने के बाद वे चूहे जल्द स्वस्थ हुए, जिन्हें फाइबर युक्त आहार दिया गया था। संयोग स्वास्थ्य अधिकारी सलाह देते हैं कि अपनी उम्र और लिंग के आधार पर प्रतिदिन कम से कम 21 से 38 ग्राम फाइबर का सेवन करना चाहिए। डॉ. कोला के मुताबिक, प्याज, लहसुन, हरा प्याज, केला, शतावरी, फुकेंदा, हाथीचक, जई, फलियां आदि फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। डॉ. लैंगडन अदरक को अच्छे से कुटकर सेवन करने की सलाह देते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि बीमार पड़ने पर जब भी एंटीबायोटिक्स की सलाह दी जाती है, तो हमें अपने आहार पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि इससे जिन अच्छे बैक्टीरिया को हानि होती है, उनकी जल्द रिकवरी हो सके। ©The New York Times 2024

आंकड़े

डाटा उपयोग

बीते दस वर्षों में वायरलेस डाटा का प्रतिमाह उपयोग करीब सात गुना बढ़ गया है। यह भारत की डिजिटल क्रांति का ही असर है।

2014	3.2
2018	7.69
2019	11.2
2022	17.11
2024	22.24

आंकड़े प्रतिव्यक्ति के प्रतिमाह डाटा औसत उपयोग के, जीबी में | स्रोत : TRAI DoT

भक्त सखूबाई पंढरीनाथ के दर्शन करने के लिए जा रही थीं, लेकिन उनकी सास ने उन्हें रस्सी से बांध दिया। भगवान स्त्री के रूप में आए और उन्हें बंधन से मुक्त किया।

भक्त सखूबाई

अंतर्यात्रा
संकलित

महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तट पर चार लोग रहते थे। एक ब्राह्मण, उनकी पत्नी, उनका पुत्र और पुत्रवधू, जिनका नाम सखूबाई था। सखूबाई जितनी अधिक भगवान की भक्त और विनय थीं, उनके परिजन उतने ही दुष्ट, कर्कश, अभिमानी, कुटिल और कठोर थे। सुबह से लेकर रात तक मशीन की भांति बिना आराम किए काम करने पर भी सास उसे भरपेट खाना नहीं देती थी। लेकिन फिर भी सखूबाई इसे भगवान की दया समझकर अपने कर्तव्य के अनुसार अस्वस्थ हो जाने पर भी काम करती रहतीं।

सखू कुछ नहीं बोलतीं, लहू का घूंट पीकर रह जातीं। वह इन दारुण दुखों को अपने कर्मों का भोग और भगवान का आशीर्वाद समझकर उन्हें सुख रूप में परिणत कर सदा प्रसन्न रहतीं। एक दिन सखू कृष्णा नदी पर जल भरने गईं। श्रीपंढरीनाथ के दर्शन करने जा रहे लोगों को देखकर सखू को भी दर्शन की प्रबल इच्छा हुई। वह उसी मंडली के साथ जाने लगीं। यह बात सास को पता चली, तो उन्होंने घर बुलाकर सखू को रस्सी से बांध दिया और खाना-पीना न देने का फैसला किया। बंधन में पड़ी सखू भगवान से प्रार्थना करने लगीं-हे नाथ! मेरी यही इच्छा थी कि यदि एक बार भी इन नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर लेती, तो सुखपूर्वक प्राण निकलते। सखू की पुकार से भगवान ने स्त्री का रूप धारण कर उनके बंधन खोल दिए। इसी के साथ उनके सारे बंधन सदा के लिए खुल गए और वह मुक्त हो गईं।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 14 नवंबर,1962

परीक्षण बंद करने की अस्थायी संधि को ब्रिटेन तैयार

परीक्षण बंद करने की अस्थायी संधि को ब्रिटेन तैयार

रूस में कृषि उत्पादन बढ़ा

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैरल्ड मैकमिलन ने घोषणा की कि ब्रिटेन पूर्ण रूप से परमाणु परीक्षण बंद करने की बातें जारी रखते हुए भी अस्थायी तौर से परीक्षण बंद करने की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है।

अदृश्य समुदायों का संविधान

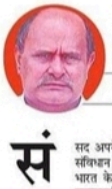

संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर शीतकालीन सत्र में चर्चा हो रही है, लेकिन चिंतन उन लोगों पर भी होना चाहिए, जो आज हाशिए पर हैं।

केसी त्यागी, भूतपूर्व सांसद — मुद्दा

संसद अपने शीतकालीन सत्र के दौरान संविधान पर चर्चा कर रही है। यह भारत के नागरिकों के लिए गर्व का महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि यह उन्हें उस ऐतिहासिक प्रक्रिया की याद दिलाता है, जिसके माध्यम से उनके लिए एक नए और समावेशी भविष्य की नींव रखी गई थी। साथ ही, यह एक अवसर है यह विश्लेषण करने का कि संविधान निर्माण के समय जो उद्देश्य और आदर्श निर्धारित किए गए थे, वे आज कितने साकार हुए हैं। 26 नवंबर, 1949 को 'भारत का संविधान' अपनाया गया था, जिसके कारण देश इस महत्वपूर्ण घटना की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। संविधान सभा के करीब 300 सदस्यों ने मिलकर भारत के भविष्य की आधारशिला रखी थी।

यह उन समुदायों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिनके हितों को ध्यान में रखते हुए संविधान ने 'हम भारत के लोग' की परिकल्पना की थी। अब, यह विचार करने का समय है कि क्या 75 वर्षों के बाद भारतीय समाज वास्तव में 'हम भारत के लोग' की भावना को अपनाने में सक्षम हुआ है? संविधान ने प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार प्रदान किया, जिससे उन्हें राजनीतिक लोकतंत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने और अपने अधिकारों का उचित लाभ उठाने का अवसर मिला। इस प्रक्रिया के माध्यम से नागरिकों को समानता और न्याय का लाभ प्राप्त होने की संभावना पैदा होती है। यह न्याय संविधान द्वारा परिभाषित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधारों पर संरचित है, जो प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकारों और अवसरों की गारंटी देता है।

बीते 75 वर्षों में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। इस समग्र विकास में विभिन्न वर्गों, धर्मों और पंथों का समान योगदान रहा है। विशेष रूप से, कई ऐसे समुदाय, जो पहले सामाजिक संरचना में निचले पायदान पर स्थित थे, अब उन्होंने महत्वपूर्ण उन्नति की है, चाहे वह शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो या आर्थिक स्थिति के संदर्भ में हो। इसके बावजूद, आज भी कुछ ऐसे समुदाय हैं, जो अपनी सामाजिक-राजनीतिक स्थिति में अपेक्षित बदलाव नहीं कर पाए हैं। ये समुदाय आज भी संविधान से अपेक्षाएं लगाए बैठे हैं कि संविधान उनके लिए निर्धारित किए गए समान अवसरों और न्याय के वादे को पूरा करेगा। डॉ. आंबेडकर ने 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में कहा था-'राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं हो सकता, जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो'।

75 वर्षों की अवधि में, कई वंचित समुदायों के लिए अदृश्यता से दृश्यता की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हालांकि, आज भी कई छोटी-छोटी अदृश्य और बिखरी हुई जातियां ऐसी हैं, जो 75 वर्षों के बाद भी अदृश्य बनी हुई हैं। इन्हें अब तक लोकतंत्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लाभों से वंचित रखा गया है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक पहलू यह भी है कि यह कुछ समूहों को सशक्त बनाती है, जबकि अन्य समूहों को हाशिए पर धकेल देती है। इसका प्रमुख कारण राज्य की शासन व्यवस्था की भाषा और राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई गई वोट बैंक की रणनीतियां हैं। हाशिए पर पड़ी ये अदृश्य जातियां प्रायः आवाजहीन होती हैं। ये समुदाय न केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाते हैं, बल्कि राज्य के संसाधनों और विकास प्रक्रियाओं तक उनकी पहुंच भी सीमित हो जाती है। परिणामस्वरूप, लोकतांत्रिक ढांचे में इनके हितों की लगातार अनदेखी होती है, और ये समुदाय सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से हाशिए पर बने रहते हैं। यह स्थिति संविधान की उस मूल परिकल्पना के विपरीत है, जो सभी समुदायों को समान अवसर और न्याय प्रदान करने का वादा करती है।

भारतीय लोकतंत्र से यह आशा की गई थी कि वह सभी की आवाज सुनेगा और उसकी संरचना में सभी वर्गों की भागीदारी होगी। हालांकि, आजादी के सात दशकों बाद भी यह अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकी हैं। इन अदृश्य समुदायों को 75 वर्षों के बाद भी भारत की चुनावी राजनीति और विकास कार्यक्रमों में लगातार उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। यह स्थिति एक गंभीर सवाल उठाती है कि क्या संविधान द्वारा प्रस्तावित समावेशी समाज का आदर्श सभी वर्गों तक पहुंच पाया है? यह संसद का ऐसा सत्र है, जिसमें संविधान पर चर्चा हो रही है। ऐसे में हमें उन समुदायों और समूहों की स्थिति पर भी चिंतन करना चाहिए, जो 75 वर्षों की इस यात्रा में राजनीतिक जागरूकता, शिक्षा और नेतृत्व की कमी, साथ ही उनके सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार के कारण पीछे छूट गए हैं। यह वही अदृश्य समुदाय है, जिनके सपनों को पूरा करने के उद्देश्य से हमारे संविधान निर्माताओं ने एक नए लोकतंत्र की स्थापना की थी। उन्होंने पारंपरिक समाज की नींव पर एक आधुनिक, समतामूलक और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया था। -साथ में पंकज चौरसिया

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शुक्रवार • 20 दिसम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है
-मार्क ट्वेन

हे राम!

आखिर यह हो क्या रहा है? जो कुछ हो रहा है क्या वह सचमुच दुनिया के विशालतम लोकतंत्र की संसद में ही हो रहा है? गली-मोहल्लों में खेल-खेल में लड़-भीड़ जाने वाले, तू -तू-मैं-मैं पर उतर जाने वाले, एक-दूसरे के साथ धक्का-मुक्की करने और पहले तूने गाली दी, तूने धक्का दिया, तूने बेईमानी की, तूने झूठ बोला जैसे गली छाप वातालाप में लिप्त हो जाने वाले निठल्ले, आवारा लड़कों की याद दिला रही है संसद। संसदीय व्यवहार इतना उथला, अभद्र और अशोभनीय हो चला है कि इस पर कोई गंभीर या विचारपरक टिप्पणी करना भी कठिन होता जा रहा है। आखिर गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया था कि आसमान गिरता हुआ लगे या धरती फटती हुई दिखे।

अमित शाह ने यही तो कहा था कि आप हर समय अंबेडकर-अंबेडकर करते रहते हैं। अगर इतनी रटन भगवान को लेकर की गई होती तो स्वर्ग मिल जाता। अब इसमें कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान देख लिया। कैसे देख लिया, कहां से देख लिया यह कांग्रेस ही देखा-देखी विपक्षी इंडिया गठबंधन के हर घटक ने इस कथित अपमान को लपक लिया और अब इनमें से कोई अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है तो कोई मोदी से अमित शाह को बर्खास्त करने की गुहार लगा रहा है तो कोई भाजपा के कथित अंबेडकर के अपमान पर आंदोलन चलाने पर उतर आया है। उधर भाजपा ने कांग्रेस और अंबेडकर के रिश्ते का इतिहास उड़ेल कर रख दिया है जो बताता है कि अंबेडकर की उपेक्षा, अवहेलना या अपमान अगर सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। शायद कांग्रेस को यह अच्छा नहीं लगा कि अंबेडकर के साथ भगवान को रखा जाए। उसे स्पष्ट कहना चाहिए था कि अंबेडकर के साथ भगवान को बिठाना अंबेडकर का अपमान है क्योंकि वह अंबेडकर को ही अपना भगवान मानने लगी है। शायद अमित शाह से भी चूक हो गई। उन्हें भी समझना चाहिए कि विपक्षी दलों को भगवान का नाम लेने से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा बल्कि अंबेडकर के नाम की माला जपने से दलित सधेंगे, उसके पक्ष में वोट करेंगे और अंततः सत्ता रूपी स्वर्ग तक पहुंचाएंगे। इस समय भगवान नहीं बल्कि अंबेडकर ही जपने के लिए भगवान हैं; भले भीतर कितना भी कपट क्यों न भरा हो। अंत में प्रार्थना ही की जा सकती है कि हे भगवान इन्हें सद्बुद्धि दें?

दिखानी होगी समझदारी

नूतनम समर्थन मूल्य सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों के रेलमार्गों पर बैठने से पंजाब की ट्रेनें प्रभावित हुईं। दोपहर बारह से तीन बजे तक वे पटरियों पर बैठे रहे, जिससे दस से अधिक जिलों का रेल यातायात प्रभावित रहा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के सुझावों व मांगों के लिए अदालत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। किसानों के इस आंदोलन को हरियाणा की खाप पंचायतों ने भी समर्थन देने का फैसला किया है। हरियाणा सकरार की निंदा करते हुए वे शंभू व खरौनी बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारियों का साथ देने को राजी हैं। सरकार की तरफ से आंदोलनकारी किसानों को लेकर जिस तरह की उपेक्षा

बरती जा रही है, वह हैरान करने वाली है। प्रदर्शन करना या विरोध जताना उनका अधिकार है मगर ट्रेनों को रोकने या सड़कें जाम करने से असल में जनता को ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों की चेतावनी के बावजूद सरकार ने उन्हें रोकने के कोई बंदोबस्त नहीं किए। यह तरीका जताता है कि जनता को होने वाली दिक्कतों को लेकर सरकारी महकमा लापरवाह होता जा रहा है। आमरण अनशन पर बैठे किसानों के प्रति भी घोर उपेक्षा बरती जा रही है। नाराज किसानों का आरोप है कि विपक्ष भी उनकी आवाज उठाने में कोताही बरती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी से बात करने को भी किसान राजी नहीं हैं। उनका मानना है कमेटियां खानापूर्ति के लिए बनाई जाती हैं। हालांकि विभिन्न गुटों में बढ़ रही फूट को मौका मानकर सरकार इस आंदोलन के ठंडा पड़ने का इंतजार करती प्रतीत हो रही है। देश में किसान आंदोलन हमेशा होते रहे हैं, मगर उनकी जिस कदर उपेक्षा की जा रही है, वह न्यायोचित नहीं कही जा सकती। यह कहना गलत नहीं है कि सरकार का काम करने का अपना तरीका होता है। उस पर इस मामले में अदालत का हस्तक्षेप भी हो चुका है। सरकार का कोई भी निर्णय पूरे देश के किसानों के हित को लेकर ही किया जाना उचित होगा। बड़े व रसूखदार किसानों को थोड़ा सब्र रखना होगा। उन्हें भी यह याद रखना होगा कि उनके किसी आचरण से आम जनता का जीवन न प्रभावित हो। क्योंकि रहवासियों से किसानों का कोई विवाद नहीं है।

साइबर ठगी/राजेश कुमार चौहान

समझदारी से ही बचेगा बटुआ

हाल ही में वित्त राज्यमंत्री ने संसद में बताया है कि देश में वर्ष 2023 में यूपीआई फ्राड के मामले लगभग 85 फीसद बढ़े हैं, यह सरकार और संबंधित विभागों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। साइबर अपराध देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है, इस पर महज चिंता और चर्चा नहीं बल्कि गंभीरता से चिंतन होना चाहिए।

कुछ महीने पहले वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स ने दुनिया के लगभग सौ देशों के साइबर क्राइम का आंकड़ा जारी किया है, इसमें हमारे देश को साइबर क्राइम के मामले में 10वां स्थान मिला है, जबकि नंबर एक पर रूस, दूसरे नंबर में यूक्रेन उसके बाद चौथा तीसरे स्थान पर जबकि अमेरिका भी साइबर क्राइम से अछूता नहीं है। अमेरिका इस आंकड़े में चौथे स्थान पर है। इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि दुनिया के दूसरे देश भी साइबर क्राइम से अछूते नहीं है, लेकिन यह चिंता का विषय है कि साइबर क्राइम दुनियाभर में फैला है, क्योंकि साइबर सुरक्षा बहुत जरूरी है, साइबर क्राइम से न धन की ही हानि होने की आकांक्षा रहती है बल्कि इससे तकनीक के साधनों के दुरुपयोग होने के भी चांस भी बढ़ सकते हैं। देश में बढ़ते साइबर अपराध या धोखाधड़ी मामले के लिए साइबर क्राइम सेल को चुस्ती दिखानी चाहिए। अगर किसी भी धोखाधड़ी की शिकायत साइबर क्राइम के किसी ब्रांच में करता है तो उस पर एकदम एक्शन लेना चाहिए। रिजर्व बैंक को भी इसके लिए बैंकों को विशेष हिदायत देनी चाहिए। हालांकि साइबर ठगी रोकने के लिए सरकार और बैंकों ने उचित कदम भी उठाएं हैं, इसके बावजूद साइबर ठगी के मामले कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं? साइबर ठगी की सुरक्षा में अभी कुछ कमी या फिर लोगों की इसके प्रति जागरूकता की कमी तो जरूर है। कुछ कंपनियां लोगों को ऑनलाइन पुराने सामान के बेचने और खरीदने का प्लेटफॉर्म अपनी-अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवा रही है, लेकिन साइबर ठग यहां भी लोगों को ठगने से बाज नहीं आ रहे। यहां पर ये साइबर ठग लोगों से सामान की एडवांस पेमेंट की मांग या देने की बात करके उनके बैंक खाते, डेबिड-क्रेडिट कार्ड और ई-वॉलेट की जानकारी मांग रहे, और कुछ लोगों ने ऐसी जानकारी देकर अपनी कमाई लुटा भी दी। लोगों को चाहिए की वो बेहद सतर्क रहें। ऐसी साइट्स पर किसी को न एडवांस पेमेंट करे और न किसी झांसे में आएं। कुल मिलाकर समझदारी में ही भलाई है।

अहम संदेश दे गए दिसानायके

वैश्विकी
गिरीश पांडे

श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के निहितार्थ कुछ समय पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके ने अपने प्रतिनिधिमंडल साथ तीन दिवसीय भारत यात्रा की थी। उनकी राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहली यात्रा है। पड़ोसी देशों यानी मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल तथा श्रीलंका के नेताओं की भारत यात्रा पर अगर नजर डालें तो स्पष्ट हो जाएगा कि पिछले करीब एक साल के भीतर इन देशों में चुनाव हुए थे और उनमें बांग्लादेश और श्रीलंका के नेताओं ने ही भारत की यात्रा की जबकि मालदीव और नेपाल ने चीन की यात्रा करना मुनासिब समझा।

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू 'भारत को बाहर करने' (इंडिया आउट) के नारे के साथ नवम्बर, 2023 में सत्ता में आए थे। इसलिए उन्होंने अपनी पहली सरकारी यात्रा के लिए भारत के बजाय चीन को न केवल चुना बल्कि मुइज्जू ने भारत से कहा था कि वह भारत द्वारा उपहार में दिए गए तीन विमानन प्लेटफॉर्म का संचालन कर रहे लगभग 90 भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुला ले। भारत ने 10 मई, 2024 तक अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला भी लिया था। हालांकि बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ।

बहरहाल, अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान श्रीलंकाई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साझेदारी को विस्तार देने के लिए भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाते हुए रक्षा सहयोग समझौता को जल्द अंतिम रूप देने का संकल्प लिया। साथ ही बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी एवं बहु-उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करके ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच संपर्क सुविधा बेहतर करने का भी निर्णय लिया। मोदी ने भौतिक, डिजिटल, ऊर्जा संपर्क को भारत-श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय सहयोग का प्रमुख स्तंभ बताया। चूंकि श्रीलंका के साथ मछुआरों का मुद्दा हमेशा से विवादित रहा है और इस विवाद में पारिस्थितिकी संबंधी चिंताएं और आजीविका संबंधी चुनौतियां दोनों शामिल हैं, जो दोनों देशों के बीच सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को प्रभावित करती रही हैं। इसलिए दोनों नेताओं ने मानवीय दृष्टिकोण से इस मसले का हल करने और मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। दिसानायके के भारत के दौरे के बीच श्रीलंका ने हिरासत में लिए गए 18 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। 2022-23 में भारत ने श्रीलंका को उसके राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में 4 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की थी, जिससे श्रीलंका को इस उथल-पुथल में आर्थिक संकट से निपटने में बहुत बड़ी मदद

मिली। इसका उल्लेख दिसानायके ने अपनी यात्रा के दौरान किया और भारत के प्रति आभार भी व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि भारत ने श्रीलंका को अब तक पांच अरब अमरीकी डॉलर की ऋण सुविधा व मदद प्रदान की है। अप्रैल 2022 में श्रीलंका को कड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। उस पर 83 अरब डॉलर का कर्ज था।

यहां उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि श्रीलंका भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी है और भारत की 'पड़ोसी-प्रथम नीति' तथा भारत की 'विजन सागर' का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए दोनों नेताओं ने हिंद महासागर क्षेत्र में साझा हितों को लेकर पैदा होने वाली पारंपरिक और गैरपारंपरिक चुनौतियों का मिलकर सामना करने और इस क्षेत्र को 'मुक्त, खुला व सुरक्षित' बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। विजन सागर (Security and Growth for All in the Region-SAGAR) एक समुद्री पहल है जिसे भारत ने 2015 में प्रस्तुत किया था जो हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत की शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हिन्द महासागर क्षेत्र को प्राथमिकता देती है। यह विश्व के सभी देशों की नौ सेनाओं और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग को तेज करने के लिए सहयोग प्राप्त करने का एक मंच है। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत और सबसे बड़ा निवेशक है। दोनों देशों के बीच 2023-24 में व्यापार 5.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच आपसी संपर्क को मजबूत करने और पर्यटन की दृष्टि से श्रीलंका ने भारतीय नागरिकों के लिए अगले वर्ष जनवरी, 2025 से श्रीलंका की वीजा मुक्त यात्रा करने का निर्णय भी लिया है। इस निर्णय से भारत उन 39 देशों में शामिल हो गया है जिनके लिए श्रीलंका ने वीजा मुक्त यात्रा की व्यवस्था की है।

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत को आश्वासन दिया कि वह अपने क्षेत्र का उपयोग भारत की सुरक्षा को हानि पहुंचाने के लिए नहीं करेगा तो स्वाभाविक है कि श्रीलंका के इस बयान से चीन की टेंशन बढ़ सकती है। दिसानायके का यह आश्वासन इस मायने में अहम है कि श्रीलंका के हंबनटोटा पोर्ट में बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक और सपोर्ट करने वाले चीनी जहाजों का खड़ा होना भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। फिलहाल जरूर श्रीलंका ने इन जहाजों के आने पर रोक लगा रखी है, लेकिन इस रोक की समयसीमा अगले साल की शुरुआत में ही समाप्त होने वाली है। देखना होगा कि दिसानायके सरकार भारत से किए अपने इस वादे को आगे किस तरह से पूरा करती है। दरअसल, नई दिल्ली को कोलंबो का यह आश्वासन ऐसे समय में आया है जब चीन अपनी कुख्यात विस्तारवादी नीति के तहत 'मिशन हिन्द महासागर' को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रहा है। इस मिशन को लेकर माना जाता है कि चीन का लक्ष्य भारत है, लेकिन श्रीलंका को अभी भी अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पड़ोसियों की दरकार है और भारत जैसा सर्वक्षेष्ठ उपयुक्त पड़ोसी और कोई हो नहीं सकता।

इसके लिए वह भारत की ओर देख रहा है। उसपर पहले से चीन का बहुत ज्यादा कर्जा है। अभी श्रीलंका पर कुल कर्ज 61.7 बिलियन डॉलर है। विश्व बैंक के मुताबिक, चीन ने पिछले कुछ साल में श्रीलंका को 8.54 बिलियन डॉलर का लोन दिया है। चीनी कर्ज का जो बोझ आज श्रीलंका पर है, उसके मद्देनजर उन्हें चीन और भारत के बीच संतुलन बनाए रखते हुए ही आगे बढ़ना होगा। देखने वाली बात यह होगी कि इस यात्रा के दौरान वह भारत की चिंताओं को किस तरह से और किस हद तक प्राथमिकता में बनाए रखते हैं।

(लेख में विचार निजी हैं)

दरअसल, नई दिल्ली को कोलंबो का यह आश्वासन ऐसे समय में आया है जब चीन अपनी कुख्तिस विस्तारवादी नीति के तहत 'मिशन हिन्द महासागर' को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रहा है। इस मिशन को लेकर माना जाता है कि चीन का लक्ष्य भारत है, लेकिन श्रीलंका को अभी भी अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पड़ोसियों की दरकार है और भारत जैसा सर्वथा उपयुक्त पड़ोसी और कोई हो नहीं सकता। इसके लिए वह भारत की ओर देख रहा है

मोटापा-रोधी गुणों से भरपूर हैं त्रिपुरा के बांस के फूल

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान (आईएएसएसटी) के अध्ययन से पता चला है कि त्रिपुरा के पारंपरिक बांस के अंकुरों में मोटापा-रोधी गुण विद्यमान हैं, और ये सुपाच्य एवं वजन नियंत्रित करने में सहायक होते हैं
- केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के स्वायत्त संस्थान आईएएसएसटी के प्रो. मोजीबुर जार खान के नेतृत्व में किया गया अध्ययन प्रतिष्ठित पत्रिका 'फूड फ्रंटियर्स' में प्रकाशित हुआ है
- त्रिपुरा में बांस की 21 किस्में हैं। चूंकि बांस के अंकुरों में पोषक तत्व अधिक होते हैं, इसलिए आदिवासियों और पहाड़ी लोगों के बीच उन्हें आसानी से उपलब्ध खाद्य उत्पाद माना जाता है

(फोटो: नीहित कुलकुर्णी)

संस्कृत में कहावत है 'मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना', हर सर अलग तरह से सोचता है! इसाइल युद्ध भूमि और भारतीय वहां से जबरन बेदखल किए गए कामगारों की जगह बुलाए गए हैं। पड़ोसी जॉर्जिया में 12 भारतीय रेस्तरां कर्मियों की मौत की खबर इलाके में आप्रवासियों की असुरक्षा का प्रमाण है।

मृणाल पांडे, पत्रकार
@MrinalPande1

अश्विन का संन्यास मनोज चतुर्वेदी

हैरान कर गया संन्यास का फैसला

भारत के करिश्माई स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बीच ऑस्ट्रेलियाई दौरे में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। पिछले कुछ समय से घुटने की तकलीफ की वजह से अश्विन के संन्यास लेने की चर्चाएं चल रहीं थीं, पर बीच दौरे में संन्यास लेने की घोषणा करना थोड़ा हैरान करने वाला है। वह भी तब अगले दो टेस्ट मेलबर्न और सिडनी में खेले जाने हैं, यहां दो स्पिनरों को खिलाया जा सकता है। इससे ऐसा लगता है कि सीरीज के पहले टेस्ट में पहली बार उनकी मौजूदगी में वाशिंगटन सुंदर के रूप में किसी दूसरे ऑफ स्पिनर को खिलाया गया, उससे शायद उन्हें यह भरोसा नहीं रहा था कि दो स्पिनर खिलाए जाने पर भी उनका खेलना पक्का भी है।

अश्विन गावा पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट के ड्रा होने से पहले ड्रेसिंग रूम में विराट से बात करते हुए भावुक नजर आए। विराट उनके कंधे पर हाथ रखे हुए थे और अश्विन के आंसू पोंछ रहे थे। इसके बाद संवाददाता सम्मेलन में रोहित शर्मा के साथ अश्विन के आने से वह साफ हो गया कि कुछ खास है। संवाददाता सम्मेलन में अश्विन ने कहा, ...मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज मेरा भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य के रूप में आखिरी दिन है। मुझे लगता है कि क्रिकेटर के तौर पर मेरे अंदर कुछ पंच बाकी है, इसे मैं क्लब स्तर की क्रिकेट में दिखाना चाहूंगा।... इससे ऐसा लगता है कि वह पहले टेस्ट में नहीं खिलाए जाने और दूसरे टेस्ट में अच्छा खेलने के बाद तीसरे टेस्ट में नहीं खिलाने से उन्हें लगने लगा कि टीम को अब उनकी जरूरत नहीं रह गई है। लगता है कि इस सोच ने ही उन्हें बीच सीरीज संन्यास लेने के लिए प्रेरित किया। यह सही है कि वह पिछले कुछ समय से अपनी घुटने की तकलीफ को लेकर परेशान थे और वह संन्यास के बारे में सोचने लगे थे। पर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हारने और स्तरीय गेंदबाजी नहीं कर पाने के बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने से पहले उनके मन में दोहरी सोच चल रही थी। पर एक बार दौरे पर जाने का फैसला कर लिया तो यह माना जा रहा था कि इस सीरीज को खेलेंगे ही। पर ब्रिस्बेन टेस्ट में नहीं खिलाने से वह शायद टूट गए और संन्यास का फैसला कर लिया। अश्विन की ही तरह एक अन्य महान स्पिनर हरभजन सिंह का कहना है कि मैंने जब

संन्यास लिया था, तब टीम से बाहर था, टीम के अंदर रहते संन्यास लेना बेहद मुश्किल फैसला है। मुझे लगता है कि भारत को अब घर में सीरीज अकूबर में खेलनी है। उससे पहले इंग्लैंड का दौरे करके पांच टेस्ट खेलने हैं। अश्विन बीच सीरीज में संन्यास लेने की वजह से अनिल कुंबले और महेंद्र सिंह धोनी की जमात में शामिल हो गए हैं। धोनी ने 2014 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे के बीच से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। धोनी के संन्यास लेने पर विराट कोहली करार बने। वहीं कुंबले ने इंग्लैंड के खिलाफ 2008 की घरेलू सीरीज के बीच में संन्यास की घोषणा कर दी थी। अश्विन के नाम गेंदबाजी में ढेरों रिकॉर्ड हैं और वह अनिल कुंबले के 619 विकेट के बाद देश के लिए दूसरे सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनके नाम 106 टेस्ट में 537 विकेट हैं और वह विकेट लेने के मामले में मुरलीधरन (800), शेन वार्न (708), जेम्स एंडरसन (704), अनिल कुंबले (619), स्टुअर्ट ब्रॉड (604) और ग्लेन मैकग्रा (563) के बाद सातवें नंबर पर हैं। बल्लेबाजी में उन्होंने 106 टेस्ट में छह शतकों और 14 अर्धशतकों से 3503 रन बनाए हैं। इस कद वाले खिलाड़ी का विदाई टेस्ट के साथ कॅरियर समाप्त होता तो कहीं बेहतर होता। भारत को अश्विन जैसे जादुई स्पिनर मिलने की कहानी कम दिलचस्प नहीं है। अश्विन ने एक बल्लेबाज के तौर पर अपने कॅरियर की शुरुआत की थी। इस दौरान वह कभी-कभी पेस गेंदबाजी भी किया करते थे। वह 14 साल की उम्र तक एक ओपनर के तौर पर खेला करते थे, लेकिन एक मैच में चोट लग जाने पर उन्हें करीब आठ माह तक क्रिकेट से अलग रहना पड़ा। वह ठीक होकर लौटे तो टीम में उनकी जगह किसी अन्य खिलाड़ी ने ले ली थी। इससे अश्विन काफी निराश हो गए थे, लेकिन मां कहने पर उन्होंने स्पिनर बनने का फैसला किया।

उनके वंचपन के कोच सीके विजय ने ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने की सलाह दी। कोच की इस सलाह ने क्रिकेट जगत को अश्विन जैसा गेंदबाज देखने को मिला। अश्विन ने 2005 में चेन्नई स्थित एसएसएन इंजीनियरिंग कालेज में दाखिला ले लिया। पर अगले ही साल उनका तमिलनाडु रणजी टीम में चयन हो गया। यह वह दौर था, जब क्रिकेट और पढ़ाई में सामंजस्य बनाना बेहद मुश्किल था। अश्विन क्रिकेट में कॅरियर बनाना चाहते थे, इसलिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने का विचार बना ही रहे थे कि चोट लग जाने की वजह से क्रिकेट से दूर रहने के कारण वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने में सफल हो गए। अश्विन ने ऑफ स्पिन गेंदबाजी को जिस मुकाम पर पहुंचाया है, उसकी जगह लेने वाला दूसरा ढूंढना आसान नहीं है।

ईश्वर विश्वास श्रीराम शर्मा आचार्य

ईश्वर विश्वास एक ऐसी चीज है कि इससे जीवन दर्शन को उच्चस्तरीय प्रेरणा मिलती है। संसार के सभी प्राणी ईश्वर के पुत्र हैं। कोई न्यायप्रिय,

निष्पक्ष पिता अपनी सभी संतानों को लगभग समान अनुदान देने का प्रयत्न करता है। ईश्वर ने अन्य प्राणियों को मात्र शरीर निर्वाह जितनी बुद्धि और सुविधा दी तथा मनुष्य को बोलने, सोचने, पढ़ने, कमाने, बनाने आदि की अनेकों विभूतियां दी हैं। अन्य प्राणियों की और मनुष्यों की स्थिति की तुलना करने पर जमीन-आसमान जैसा अंतर दिखाई पड़ता है। इसमें पक्षपात और अनीति का आक्षेप ईश्वर पर लगता है। जब सामान्य प्राणी अपनी संतान को समान स्नेह सहयोग देते हैं तो फिर ईश्वर ने इतना अंतर किसलिए रखा? इस विषेद को समझने में प्रत्येक विवेक सम्पन्न व्यक्ति को भारी उलझन का सामना करना पड़ता है। तत्वदर्शी विवेक बुद्धि इस विषेद के अंतर का कारण भली प्रकार स्पष्ट कर देती है। मनुष्य को अपने वरिष्ठ सहकारी जेष्ठ पुत्र के रूप में सृजा गया है। उसके कांधों पर सृष्टि को अधिक सुन्दर, समुन्नत और सुसंस्कृत बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसके लिए उसे विशिष्ट साधन उसी प्रयोजन के लिए अमानत के रूप में दिए गए हैं। मिनिस्टरों को सामान्य कर्मचारियों की तुलना में सरकार अधिक सुविधा साधन इसलिए देती है कि उनकी सहायता से वे अपने विशिष्ट उत्तरदायित्वों का निर्वाह सुविधापूर्वक कर सकें। यह सुविधाएं उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं वरन जनसेवा के लिए दी जाती हैं। बैंक के खजांची के हाथ में बहुत-सा पैसा रहता है। यह उनके निजी उपभोग के लिए नहीं बल्कि बैंक प्रयोजन के लिए अमानत रूप में रहता है। निजी प्रयोजन के लिए तो क्या मिनिस्टर, क्या खजांची, सभी को सीमित सुविधा मिलती है। अत्यधिक साधन जो उनके हाथ में रहते हैं, उन्हें वे निर्दिष्ट कार्यों में ही खर्च कर सकते हैं। मानवी कार्यों में उपभोग करने लगें तो यह दण्डनीय अपराध होगा। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के पास सामान्य प्राणियों को उपलब्ध शरीर निर्वाह भर के साधनों से अतिरिक्त जो कुछ भी श्रम, समय, बुद्धि, वैभव, धन, प्रभाव, प्रतिभा आदि की विभूतियां मिली हैं, वह सभी लोकोपयोगी प्रयोजनों के लिए मिली हुई सार्वजनिक संपत्ति है।

रीडर्स मेल

बाबा साहब पर राजनीति

भारत के संविधान निर्माता डॉ. बी आर अंबेडकर देश की राजनीति में अचानक केंद्र में आ गए हैं। 'बाबा साहब का अपमान नहीं करेगा हिंदुस्तान'। यह नारा विपक्षी दलों की जुबान पर है। सम्भवतः देश के गृहमंत्री के द्वारा डॉ. अंबेडकर के अपमान का इरादा नहीं रहा होगा, लेकिन कहनी हकीकत यह है कि देश के करोड़ों दलितों को संसद में अनावश्यक संदर्भ पर आपत्ति है और अपमान के रूप में देखा जा रहा है। विपक्ष ने यह मुद्दा जोरदार ढंग से संसद के अंदर और बाहर उठाकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सफाई देने पर मजबूर किया है, लेकिन विपक्ष में खासकर कांग्रेस ने डॉ. अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया था, ना ही डॉ. अंबेडकर चित्र संसद में लगाया था। देश के दलितों की मांग थी कि मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम डॉ अंबेडकर के नाम से किया जाए, लेकिन यह सब कांग्रेस ने नहीं किया था। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने भी लखनऊ एवं नोएडा स्थित अंबेडकर स्मारक बनाया था तो सपा के नेताओं ने अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था और केवल पत्थर की मूर्ति कह कर मजाक बनाया था। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने डॉ. अंबेडकर को भूमि माफिया कहा था जिस पर काफी बवाल मचा था।

वीरेन्द्र कुमार जाटव,. दिल्ली

संन्यास ने चौंकाया

इधर आस्ट्रेलिया में बार्डर गावस्कर ट्राफी का तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ और उधर भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अचानक संन्यास की घोषणा कर सभी को चौंका दिया। 15 साल में अश्विन ने श्रेष्ठ प्रदर्शन के बल पर कई कीर्तिमान स्थापित किए और दुनिया के महानतम स्पिनरों में जगह बनाई। 37 बार पारी में 5 विकेट लेने वाले अश्विन ने 106 टेस्ट में 537 विकेट लिए। पारी में पांच विकेट लेने के रिकॉर्ड के मामले में वह अनिल कुंबले और मुथैया मुरलीधरन जैसे दिग्गजों के समकक्ष हैं। अश्विन का टेस्ट में गेंदबाजी औसत 24 और स्ट्राइक रेट 50.7, स्पिनरों में सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने टेस्ट में 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीते, जो मुरलीधरन के रिकॉर्ड के बराबर है। अश्विन का फैसला अप्रत्याशित है, क्योंकि वह भारतीय गेंदबाजी का अहम हिस्सा रहे हैं। क्रिकेट में अमिट छाप छोड़ने वाले अश्विन अब केवल आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में ही नजर आएंगे। क्रिकेट के इस फिरकी जादूगर की कमी मैदान पर सदैव खलेगी।

अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो गीता

भारत सरकार गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहती है, लेकिन कुछ दल राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोग धर्मनिरपेक्षता की आड़ में राजनीति क्यों कर रहे हैं? भारत में धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा विषय है, जिसे हर दल ने अपने सुविधानुसार परिभाषित किया है। आज तक इस पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई। गीता भारतीय संस्कृति की पहचान है। गीता का विरोध करने वाले भारत की सनातन संस्कृति का विरोध कर रहे हैं। चंद वोटों के लालच में संस्कृति-द्रोह किया जा रहा है। सरकार से अनुरोध करूंगा कि विरोधियों की परवाह किए बगैर वो गीता को जल्द से जल्द राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करें। कुछ लोगों का काम ही विरोधना है। आम जनमानस सरकार के इस फैसले के समर्थन में खड़ा है।

संदीप कुमार, मधुपुर, झारखंड
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काजी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सहयोग भवन, नवमंजिल, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश सिंह*।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

दिल्ली में प्रदूषण

स्थिति गंभीर

दिल्ली में ग्रैप 4 लागू होने के बावजूद वायु गुणवत्ता एक बार फिर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई है। भले ही आप धूम्रपान न करते हों, पर दिल्ली में रहने पर रोज 10 सिगरेटों का धुंआ आपके भीतर जाता है। दिल्ली के प्रदूषण के बारे में डाक्टरों की यही राय है। बुधवार को राजधानी की वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट आई और वायु गुणवत्ता सूचकांक-एक्यूआई 400 का आंकड़ा पार कर गया। इससे वह एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। यह खतरनाक स्थिति 'ग्रेडेड रिस्पांसिव एक्शन प्लान'-ग्रैप के चौथे चरण के क्रियान्वयन के बावजूद पैदा हुई है जिसमें कठोर प्रदूषण-रोधी उपाय किए गए हैं। इसमें 'समीर' एप में सूचीबद्ध 37 निगरानी स्टेशनों पर एक्यूआई तथा अन्य निगरानी स्टेशनों की रिपोर्ट पर गौर करना शामिल है। इन आंकड़ों से शहर में वायु प्रदूषण की व्यापक व गंभीर प्रकृति सामने आई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन का ग्रैड एक चरणबद्ध व्यवस्था है जिसमें वायु गुणवत्ता को चार श्रेणियों में परिभाषित किया गया है। पहले चरण में 201-300 एक्यूआई को खराब, दूसरे चरण में 301-400 एक्यूआई को बहुत खराब, तीसरे चरण में 401-450 एक्यूआई को गंभीर तथा चौथे चरण में 450 से अधिक एक्यूआई को बहुत गंभीर माना जाता है। चौथे चरण के उपायों में सार्वजनिक ढांचागत परियोजनाओं समेत सारे निर्माण व विध्वंस गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध तथा दिल्ली में गैर-जरूरी चीजें लाने वाले डीजल ट्रकों पर प्रतिबंध लागू किया जाता है। इस स्थिति में सार्वजनिक, नगर निगम व निजी

कार्यालयों को अपनी उपस्थिति 50 प्रतिशत तक सीमित करने तथा बाकी को घर से काम की अनुमति देने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही इस गंभीर स्थिति में कालेजों व गैर-जरूरी बिजनेसों को बंद करने तथा वाहनों पर नियंत्रण के लिए 'आड-इवेन' लागू करने की सलाह दी जाती है। लेकिन इन उपायों के बावजूद दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार गिर रही है जिससे इन उपायों की प्रभावशीलता व क्रियान्वयन पर सवाल उठने लगे हैं।

लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इसका संबंध मौसमी परिस्थितियों के कारण है और यह ग्रैप की विफलता नहीं है। वे वायु प्रदूषण में अचानक वृद्धि का कारण खराब मौसमी स्थितियों, खासकर हवा की गति में भारी गिरावट को देते हैं। इसके कारण स्थानीय प्रदूषण एकत्र होता रहता है और पहले से ही गंभीर वायु की गुणवत्ता और खराब हो जाती है। जाड़ों में दिल्ली में वायु प्रदूषण संकट अनेक आयामों के कारण गंभीर हो जाता है। शहर के वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन है। वाहनों के उत्सर्जन के अलावा खेतों में पराली जलाने से प्रदूषण का बोझ बढ़ता है। फैक्ट्रियां भी बड़ी मात्रा में प्रदूषक छोड़ती हैं। लेकिन वर्तमान समय में तापमान में भी गिरावट आ रही है। जाड़ों में भारी हवा प्रदूषकों को जमीन के पास बांधे रखती है जिससे 'स्मोग' की गहरी पर्त पैदा होती है। दिल्ली में वायु की खतरनाक गुणवत्ता उसके निवासियों के लिए स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा करती है। प्रदूषण में लंबे समय तक रहने पर श्वसन तंत्र में विकृतियां, कार्डियोवैस्कुलर समस्यायें तथा अन्य गंभीर स्थितियां पैदा हो सकती हैं। बच्चों, वृद्धों तथा पहले से ही खराब स्वास्थ्य वाले संकटग्रस्त समूहों को खतरा सबसे अधिक होता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि इस मौसम में दिल्ली में वायु की गुणवत्ता अत्यधिक गंभीर स्थिति में पहुंची हो। नवंबर में इन स्थितियों के कारण ग्रैप 4 चरण लागू करना पड़ा था। गंभीर प्रदूषण से बार-बार दिल्ली में वायु गुणवत्ता संकट का दुष्कर स्पष्ट होता है। इसका कारण अनेक स्थानीय और क्षेत्रीय कारक हैं। दुर्भाग्य से अधिकारियों के पास इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए कोई समग्र योजना नहीं है और वे त्वरित प्रतिक्रिया के माध्यम से समस्या के निष्प्रभावी तत्कालीन समाधान निकालने का प्रयास करते हैं।

वर्ष 2025 से उम्मीदें

वर्ष 2025 परिवर्तन तथा प्रगति की अनेक उम्मीदों से भरा है। इस वर्ष अनेक महान आध्यात्मिक व राजनीतिक आयोजन होंगे जिनसे आर्थिक प्रगति के साथ राजनीतिक उथलपुथल भी पैदा हो सकती है।

कल्याणी शंकर
(लेखिका, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

इस समय अधिकांश लोग सोच रहे हैं कि आगामी वर्ष 2025 कैसा होगा? ये अनुमान मिश्रित प्रकृति के हैं। प्रख्यात फ्रांसीसी संत और ज्योतिषी नास्टरडैमस ने 2025 में भारत और दुनिया के भविष्य के बारे में अनेक महत्वपूर्ण अनुमान लगाए थे। सोलहवीं शताब्दी के इस संत ने अनेक ऐसी घटनाओं का अनुमान लगाया था जिन्होंने दुनिया को स्वरूप दिया है। इनमें कोविड-19 वैश्विक महामारी से लेकर मनुष्य के चंद्रमा पर उतरने जैसी बातें शामिल हैं। इनसे नास्टरडैमस के अनुमानों पर आश्चर्य होता है। आज अनेक लोग सोलहवीं शताब्दी के इस संत की भविष्यवाणियों की व्याख्या कर रहे हैं और उनकी ऐतिहासिक सटीकता से प्रभावित हैं।

नास्टरडैमस ने अनुमान लगाया था कि रूस-यूक्रेन युद्ध 2025 में समाप्त हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि दोनों देश जलवायु संकट और बाढ़ का सामना कर सकते हैं। 'द न्यूयार्क पोस्ट' के अनुसार, तुर्किये और फ्रांस यूक्रेन और रूस के बीच शांति प्रक्रिया में काफी सहायता दे सकते हैं। नास्टरडैमस ने 2025 में इंग्लैंड में 'प्राचीन प्लेग' का पूर्वानुमान किया था जिससे एक ऐतिहासिक बीमारी के पुन: उभरने की आशंका पैदा होती है। इसके साथ ही उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध में ब्राजील की संलिप्तता तथा अनेक प्राकृतिक विभीषिकाओं का भी पूर्वानुमान लगाया है। इनके साथ ही नास्टरडैमस ने अनुमान लगाया है कि धरती की एक छुद्र ग्रह या एस्टीरायड से टक्कर हो सकती है। उन्होंने कहा था, 'ब्रह्मांड से आग का एक गोला उठेगा जो भविष्य बदलने वाला होगा।' नास्टरडैमस की भविष्यवाणियां हमें संभावित भावी घटनाओं तथा उनके प्रभावों के बारे में सचेत करती हैं।

जहां तक भारत के भविष्य का सवाल है, वर्ष 2025 की शुरुआत गणतंत्र दिवस परेड से होगी। इस बार परेड की थीम 'स्वर्णिम भारत: विकसित भारत' है, हालांकि अभी परेड में आमंत्रित मुख्य अतिथि के नाम को अंतिम रूप नहीं दिया

गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगला महाकुंभ 13 जनवरी, 2025 से 26 फरवरी, 2025 तक होगा। महाकुंभ के अवसर पर हर 12 साल के अंतराल पर अलग-अलग स्थानों पर यह महान आध्यात्मिक आयोजन होता है। इस अवसर पर लाखों-लाख तीर्थयात्री और श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकार महाकुंभ के इस आयोजन को असाधारण और अभूतपूर्व बनाने के सभी प्रयास कर रही हैं। अगले वर्ष 2025 में भारत में तेज आर्थिक प्रगति, सामाजिक परिवर्तन तथा नई नई तकनीकें देखने को मिल सकती हैं। सरकार तकनीकी शिक्षा तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से सुधार कर रही है।

इन प्रयासों से आर्थिक प्रगति तेज होने की आशा है जो भारत में भावी समृद्धि के लिए शुभ संकेत है। विश्व स्तर पर भारत का महत्व इस वर्ष और बढ़ने की आशा है जिससे वह अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार, रक्षा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अपने प्रयास तेज करेगा। इनसे भारत की दुनिया भर में बढ़ती राजनीतिक शक्ति का भी पता चलता है। देश के स्तर पर विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है और इसकी एकजुटता

> **प्रख्यात फ्रांसीसी संत और ज्योतिषी नास्टरडैमस ने 2025 में भारत और दुनिया के भविष्य के बारे में अनेक महत्वपूर्ण अनुमान लगाए थे। सोलहवीं शताब्दी के इस संत ने अनेक ऐसी घटनाओं का अनुमान लगाया था जिन्होंने दुनिया को स्वरूप दिया है।**

पर सवाल उठने लगे हैं। इस विपक्षी गठबंधन के भीतर पहले ही काफी तनाव पैदा हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस-टीएमसी तथा आम आदमी पार्टी-आप ने गठबंधन से दूरी बना ली है। 'आप' ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने का मन बना लिया है। विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' में हालिया हरियाणा, महाराष्ट्र व झारखंड विधानसभा चुनावों के समय दरारें दिखने लगी थीं। जहां कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन किया, वहीं झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा-जेएमएम के साथ उसके गठबंधन ने चुनाव में विजय प्राप्त की। 'इंडिया' गठबंधन के सदस्य कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन से दु:खी हैं। उनकी नजर अब इस बात पर लगी है कि 2025 में होने वाले दिल्ली व बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है। आगामी विधानसभा चुनावों से भावी राजनीतिक पुन: ध्रुवीकरण के भी संकेत मिलेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी में होंगे जहां भाजपा आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटाने के लिए कमर कस रही है।

'आप' ने निकट अतीत में अनेक चुनौतियों का सामना किया है जिसमें उसके अनेक नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं। एक रणनीति के रूप में 'आप' ने आतिशी को चुनावों तक दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। हालांकि, आप और कांग्रेस ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव एकसाथ लड़ा था। इसमें आप का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर था, पर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। अगले वर्ष बिहार विधानसभा के चुनाव भी होंगे। यह राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। यहां सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-राजग का नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, पर उनको 'महागठबंधन' से कठोर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल-राजद नेता तेजस्वी यादव कर रहे हैं। भाजपा और जनता दल युनाईटेड-जदयू राज्य में पुन: अपनी सरकार बनाने के लिए प्रयासरत हैं।

वर्ष 2025 में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन-भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-सीपीआई व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-आरएसएस अपनी शताब्दी मनाएंगे। आरएसएस अपनी स्थापना के 100 वर्ष सितंबर में पूरे करेगा, जबकि सीपीआई इस वर्ष दिसंबर में अपने शताब्दी समारोहों की शुरुआत करेगी। अनेक उतार-चढ़ावों के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-आरएसएस ने भारतीय राजनीति और समाज को गहराई तक प्रभावित किया है। ऐसे में किसी सरकार के लिए अब भविष्य में उसे कमजोर करना बहुत कठिन हो गया है। इसके साथ ही दक्षिणपंथी दलों के ज्यादा लोकप्रिय होने के कारण कम्युनिस्ट पार्टियों का प्रभाव कम हो गया है।

अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर गौर करें तो भारत 2025 में क्वाड सम्मेलन आयोजित करेगा। मूलत: इसका आयोजन इस सितंबर में नई दिल्ली में होना था, पर इसमें भाग लेने वाले नेताओं के अन्य कार्यक्रमों के कारण इसका आयोजन न्यूयार्क में हुआ। अब भारत 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिल्ली आने की आशा है जिससे अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। अगले वर्ष के प्रारंभ में रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन की भारत यात्रा प्रस्तावित है जो एक महत्वपूर्ण अवसर होगा।

क्रेमलिन ने अगले वर्ष के प्रारंभ में इसकी तारीख तय करने की पुष्टि की है। यह यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन की पहली यात्रा होगी। कुल मिला कर वर्ष 2025 भारत के लिए उम्मीदों से भरा है। अर्थव्यवस्था की अच्छी प्रगति हो रही है तथा विदेशी संबंध स्थिर हैं, हालांकि अभी राजनीतिक स्थिति अस्पष्ट है।

अगले वर्ष देखना होगा कि कांग्रेस की स्थिति में कुछ सुधार होता है अथवा भाजपा व अन्य क्षेत्रीय पार्टियां मतदाताओं पर अपनी पकड़ और मजबूत करने में सफल होती हैं।

सकारात्मकता की शक्ति

> **आध्यात्मिक आत्मचिंतन और सकारात्मकता को अपनाकर हम उथल-पुथल से ऊपर उठ सकते हैं।**

ब्रह्मकुमार निकुंज
(लेखक, आध्यात्मिक उपदेशक हैं)

आजकल जीवन के हर कदम पर संकट, निराशा और द्वंद्व का संघर्ष नजर आता है। हम इससे कैसे निपटें? हम खुद को निराशावादी या निराश होने से कैसे रोकें? आज मानव चेतना की सबसे बड़ी आधुनिक बीमारी यह है कि हम अपने भीतर, मूल्यों, दृष्टिकोणों और उद्देश्यों की जांच किए बिना खुशी पाने के लिए बाहर की ओर देखते हैं; बाहरी संकेतों पर ज्यादा भरोसा करते हैं और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं। हालांकि, व्यावहारिक रूप से, ऐसी उम्मीदों के साथ जीवन नहीं बनाया जा सकता है।

क्योंकि खुशी पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आज की दुनिया में, कोई भी व्यक्ति और कुछ भी हमारे भीतर खुशहाली की स्थायी स्थिति नहीं बना सकता है, क्योंकि यह हमारा विशेषाधिकार और जिम्मेदारी है। बाहरी कारक हमें योगदान दे सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं और हमें प्रेरित कर सकते हैं लेकिन आखिरकार हमारा जीवन वही है जो हम उससे बनाते हैं।

सच्ची खुशी या उसकी कमी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपने अंदर की चीजों से आती है। उदाहरण के लिए, पैसा खुशी का साधन नहीं है और न ही यह किसी के दुख का कारण है। वास्तव में, यह हमारे दृष्टिकोण और मूल्य हैं जो बाहरी साधनों के उपयोग या दुरुपयोग को निर्धारित करते हैं, चाहे वह पैसा हो, कोई व्यक्ति हो, कोई घटना हो या कोई वस्तु हो।

एक ऐसा जीवन जिसका मूल्य है और जो जीने योग्य है, वह तभी संभव है जब एक चिंतनशील परीक्षा हो जिसके माध्यम से प्रकाशमान परिवर्तन हो सके। इसलिए, अपनी चेतना को पुन: उन्मुख करने के लिए, हमें आत्म-ज्ञान पर आधारित चेतना

की आवश्यकता होगी यानी आध्यात्मिक आत्म का ज्ञान जो आत्म-सम्मान और सकारात्मकता पैदा करता है, जिससे हम जीवन पर सही दृष्टिकोण प्राप्त कर पाते हैं जो बदले में हमें किसी भी तरह की नकारात्मकता से संतुलित और कम दर्दनाक तरीके से निपटने में मदद करेगा। तदनुसार, सकारात्मकता के साथ, हम अपने जीवन में संतुलन की भावना को प्रभावित करने वाले बाहरी मुद्दों से निपटने के लिए आंतरिक शक्ति का अनुभव करते हैं। जब हम अपने प्रति अधिक सकारात्मक होते हैं, तो जाहिर है कि हम दूसरों के प्रति और सभी स्थितियों में समान दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं। आंतरिक शक्ति तब भी आती है जब हम दूसरों के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं कि प्यार, शांति और खुशी ईमानदारी से व्यक्त और अनुभव की जाती है। मुख्य बिंदु ईमानदारी है क्योंकि झूठ, नकल या द्वैत के माध्यम से पूर्णता की भावना को दृष्टिकोण के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए समय की मांग है कि हम शाश्वत आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित जीवन जिएं जो हमें स्वयं और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की अनुमति देगा, जिससे हमारा जीवन संघर्षपूर्ण या भ्रम की स्थिति में रहने के बजाय आनंदमय हो जाएगा। आध्यात्मिकता पूजा या अनुष्ठान की कोई प्रणाली या तकनीक नहीं है, यह संक्षेप में, यह जानना है कि जीवन कैसे जिया जाए और इस ज्ञान के माध्यम से खुशी मिलती है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति ने अपने भीतर शाश्वत संदर्भ की चिंगारी पा ली है, जो उसे न केवल गहन संतुष्टि देती है, बल्कि उद्देश्य की भावना भी देती है।

आध्यात्मिकता के लिए पहली शर्त एक ऐसा जीवन है जो उचित रूप से कार्य करता है और सबसे सभ्य तरीके से अपने बारे में सोचता और परवाह करता है। अपने बारे में अनुचित तरीके से सोचना और परवाह करना दूसरों पर बहुत अधिक निर्भरता, बहुत अधिक ज़रूरतें, बहुत अधिक माँगें, बहुत अधिक अधिकार जताना पैदा करता है। इसलिए आगे बढ़ने का सही तरीका यह है कि पहले खुद की जाँच करें और फिर अपने भीतर सकारात्मक और नकारात्मक लक्षणों को स्वीकार करें।

ऐसा करने से हमें बिना किसी डर और दिखावे के जो कुछ भी बदलने की जरूरत है उसे बदलने का साहस मिलता है। बेहतरी के लिए सफल बदलाव का आधार उन दृष्टिकोणों, भावनाओं और उद्देश्यों को समझना है जो हमें स्वयं की मूल सकारात्मकता, आत्मा की अमर अच्छाई को स्वीकार करके बदलाव के लिए प्रेरित करते हैं।

यह स्वयं की अच्छाई ही है जो मनुष्य के रूप में हमारी गरिमा की नींव बनाती है। हमारे जीवन में इस मूल अच्छाई की अभिव्यक्ति को देवत्व कहा जाता है जो हमें वास्तव में मानव बनाता है। तो आइए हम अपने भीतर दिव्यता की अभिव्यक्ति को जागृत करें ताकि चारों ओर की अराजकता और संकट के बीच एक पूर्ण आनंदमय जीवन जी सकें।

आप की बात

एआई के लाभ

उधर ट्रंप और इधर मोदी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सब्सिडी देने के पक्ष में है ताकि रोजगार बढ़ सके रोजगार बढ़ाने का यह क्या तरीका है? अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है उसके जरिए छोटे गांव से लेकर कस्बा और शहरों तक रोजगार के नए संसाधन उपलब्ध करवाने का यह तरीका न केवल रोजगार प्रदान करता है, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है! आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन से अब रोजगार के नए संसाधनों को उपलब्ध करवाने के लिए कई अवसर हैं। एआई का उपयोग करके हम छोटे गांवों से लेकर कस्बों और शहरों तक रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं! एआई और अन्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों के बारे में शिक्षा प्रदान करना, जिससे लोगों को नए कौशल सीखने में मदद मिल सके। एआई आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, जिससे नए व्यवसायिक अवसर पैदा हो सकें। एआईके साथ काम करने के लिए आवश्यक कौशलों का विकास करना, जैसे कि डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग आदि। एआईके माध्यम से रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, जैसे कि रिमोट वर्क, फ्रीलांसिंग आदि। इन कदमों को उठाकर, हम,ड्ड का उपयोग करके रोजगार के नए अवसर प्रदान कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं!

– **सुभाष बुड़ावनवाला**, रतलाम

कैंसररोधी वैक्सीन

भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में भी प्रतिवर्ष कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है । ऐसे में यह समाचार सुखद है कि रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि उसके वैज्ञानिकों ने कैंसर रोधी वैक्सीन को ईजाद कर लिया है । इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सफल हुआ है, जो ट्यूमर के विकास को रोकने में सफल हुआ है । रूस में इस वैक्सीन के टीके अगले साल से रूसी नागरिकों को फ्री में लगाएं जायेंगे । यह वैक्सीन पूरी तरह से कारगर हो व कैंसर को रोकने में सफल हो तो निश्चित ही यह रूस के वैज्ञानिकों की मानव हीत में बड़ा वरदान साबित होगा। वैज्ञानिकों को इसी तरह के प्रयास करते रहना चाहिए की जो भी खतरनाक व असाध्य बिमारियां है, उनकी रोकथाम के लिए ऐसे वैक्सीन ईजाद करते रहे । कहते हैं कि भगवान गरीबी दें देना मगर बीमारी मत देना। ईसान गरीबी से लड़ सकता है मगर बीमारी से नहीं । चीन जमीन से सोना निकाल रहा है, रूस कैंसर जैसी बीमारी को रोकने हेतु वैक्सीन बना रहा है, वही हम धर्म, जाति की सियासत व मस्जिदों में मंदिर ढूंढने में लगें हैं। यह वक्त का तकाजा है कि भारत सरकार को भी घातक व जानलेवा बीमारियों की रोकथाम के लिए सतत वैज्ञानिक प्रयास जारी रखना चाहिए। रूस के वैज्ञानिकों को इस बड़ी सफलता पर साधुवाद।

– **हेमा हरि उपाध्याय**, अक्षय खाचरोद, उज्जैन

प्रदूषित जल से बचाव

पानी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन आजकल पानी में कई तरह के विषाक्त पदार्थ घुलते जा रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विषाक्त पदार्थ हैं हरित और रासायनिक कीटनाशक, जो फसलों पर कीटों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कीटनाशकों का दुष्प्रभाव न केवल पानी पर, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ये कीटनाशक पानी में घुलकर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इन कीटनाशकों के दुष्प्रभावों में से कुछ प्रमुख हैं। पानी में घुले कुछ कीटनाशक कैंसर का कारण बन सकते हैं। कीटनाशकों के संपर्क में आने से न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो सकती हैं। कीटनाशकों के संपर्क में आने से प्रजनन समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा पानी में माइक्रो प्लास्टिक भी पाया गया है। इन रसायनों के के दष्प्रभाव से बचने के लिए स्वच्छ पानी का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। आप पानी को छानकर या फिल्टर करके उपयोग कर सकते हैं। खेती में जैविक खाद्य पदार्थों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। ये खाद्य पदार्थ कीटनाशकों से मुक्त होते हैं। कीटनाशकों का सुरक्षित उपयोग करना महत्वपूर्ण है। हम कीटनाशकों का उपयोग करते समय सुरक्षा उपायों का उपयोग कर सकते हैं।

– **विभुक्ति बुपक्या**, खाचरोद

अशोभनीय आचरण

वैचारिक बहस को नकार कर संसद भवन परिसर में हंगामा करने एवं धक्का मुक्की जैसी अराजकता पर उतर आए, तो लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की कल्पना भी कैसे की जा सकती है। ग़ौरतलब है कि कांग्रेस के नेता सांसद राहुल गांधी ने जिस प्रकार से संसद भवन परिसर में धक्का मुक्की की, जिसमें भाजपा के दो सांसद प्रताप सारंगी व मुकेश राजपूत घायल हुए, उससे सांसद के आचरण पर ही सवालिया निशान उठ गया है। निस्संदेह देश के लोकतंत्र में इससे अधिक कलंकित दिवस और कोई नही हो सकता , कि जब संसद भवन परिसर में लोकतंत्र के प्रहरी ही धक्का मुक्की पर उतर आए हों तथा संसद की गरिमा को तार तार किया गया हो। विचारणीय प्रश्न यही है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में धक्का मुक्की करने का अधिकार किसी भी सांसद को क्यों होना चाहिए। कौन नही जानता कि संसद भवन किसी भी मुद्दे पर वैचारिक बहस स्वीकार्य है, किंतु धक्का मुक्की नहीं। किंतु देश में राजनीतिक अस्तित्व संकट से गुज़र रही कांग्रेस विरोध के नाम पर अराजकता करने से भी नही चूकती। कांग्रेसी का अशोभनीय आचरण अत्यंत निंदनीय है।

– **डॉ. सुधाकर आशावादी**, मेरठ

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 262

बदलती अपेक्षाएं

बदलती नीतिगत वास्तविकता के मुताबिक ढलना अक्सर वित्तीय बाजारों के लिए मुश्किल होता है। बुधवार को अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) ने दरों में 25 आधार अंकों की कमी की। यह कमी वित्तीय बाजारों की अपेक्षाओं के अनुरूप ही थी। लेकिन शेयर और बॉन्ड बाजार दोनों में बिकवाली हुई। एसऐंडपी 500 में तीन फीसदी की गिरावट आई जबकि 10 वर्ष के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड की यील्ड 13 आधार अंक बढ़कर 4.5 फीसदी हो गई जो कई महीनों का उच्चतम स्तर है। बॉन्ड कीमतें और यील्ड एक दूसरे से उलटी चाल चलते हैं। भारत में बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स में गुरुवार को 1.2 फीसदी की गिरावट आई। वित्तीय बाजारों में इस बिकवाली की प्राथमिक वजह एफओएमसी के संशोधित अनुमानों को माना गया। इसने दिखाया कि समिति को अब उम्मीद है कि फेडरल फंड दरों में 2025 में केवल 50 आधार अंकों की कमी होगी जबकि सितंबर में एक फीसदी कमी का अनुमान लगाया गया था।

इस बदलाव की वजह है मुद्रास्फीति। हालांकि मुद्रास्फीति की दर 2022 की ऊंचाइयों से काफी नीचे आई है लेकिन अभी भी यह फेडरल रिजर्व के मध्यम अवधि के दो फीसदी के लक्ष्य से ऊपर है। संशोधित अनुमानों के मुताबिक 2025 में मुद्रास्फीति की दर सितंबर के अनुमान से 40 आधार अंक बढ़कर 2.5 फीसदी रह सकती है। कोर मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन क्षेत्र से परे) के अनुमानों को भी संशोधित करके बढ़ाया गया है। सकारात्मक बात यह है कि एफओएमसी के सदस्यों ने वृद्धि और रोजगार के अनुमानों में भी अनुकूल संशोधन किया है। बहरहाल वित्तीय बाजार 2025 में दरों में अधिक कटौती पर दांव लगा रहे हैं। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। मुद्रास्फीति के ऐसे नतीजों से परे वित्तीय बाजार डॉनल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले नए प्रशासन की अनिश्चित संभावनाओं पर भी चिंतित है। उदाहरण के लिए ट्रंप तमाम वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाना चाहते हैं। उनका इरादा चीन जैसे चुनिंदा देशों पर ऊंचा शुल्क लगाने का भी है। हालांकि दुनिया वास्तविक कार्रवाई पर नजर रखेगी लेकिन फेड के नजरिये से ऐसे कदम अपरिहार्य रूप से अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ाएंगे जिसका असर उच्च मुद्रास्फीति में नजर आएगा। हालांकि मुद्रास्फीति पर शुल्क दरों का प्रभाव समय के साथ कम हो सकता है लेकिन यह फेड के काम को जटिल बना सकता है। ऐसे बदलाव वैश्विक वित्तीय बाजारों में भी अस्थिरता बढ़ाएंगे। तुलनात्मक रूप से ऊंची ब्याज दरें पूंजी प्रवाह को अमेरिका की ओर करेंगी और डॉलर को मजबूती देंगी। यह बात अन्य मुद्राओं पर, खासकर उभरते बाजारों की मुद्राओं पर दबाव डालेगी। फेड के निर्णय के बाद डॉलर सूचकांक दो वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसके परिणामस्वरूप शेयर बाजार में गिरावट के अलावा गुरुवार को भारतीय रुपये ने भी डॉलर के समक्ष 85 रुपये का मनोवैज्ञानिक अवरोध भंग कर दिया। रुपया अपेक्षाकृत स्थिर रहा है और वर्ष की शुरुआत से अब तक उसमें बमुश्किल दो फीसदी की गिरावट आई है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा हाल के महीनों में भारी बिकवाली के बावजूद ऐसा हुआ है क्योंकि रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजार में अच्छा खासा हस्तक्षेप किया है। रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर से अब तक करीब 50 अरब डॉलर कम हुआ है। हालांकि इसके लिए कुछ हद तक परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन भी वजह हो सकता है।

अमेरिका की नीतिगत संभावनाएं यही संकेत देती हैं कि कम से कम निकट भविष्य में रुपये पर दबाव रहेगा। रिजर्व बैंक के लिए बेहतर होगा कि वह बहुत अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करके रुपये का बचाव न करे। वास्तव में रुपये की कीमत अब भी ज्यादा है और उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर दूसरे विकासशील देशों की मुद्राओं में मजबूत डॉलर के कारण गिरावट आती है तो अपेक्षाकृत मजबूत रुपया देश के कारोबार योग्य क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धा पर असर डालेगी। इससे बचना चाहिए। बहरहाल, मुद्रा में अपेक्षित कमजोरी रिजर्व बैंक के मुद्रास्फीति संबंधी अनुमानों और मौद्रिक नीति समिति की चर्चाओं में भी नजर आनी चाहिए। अमेरिकी नीतियों को लेकर आने वाले कुछ महीनों में स्पष्टता नजर आनी चाहिए।

विनय सिन्हा

ट्रंप के टैरिफ युद्ध से बचने की चीनी जुगत और भारत

डॉनल्ड ट्रंप के आने के बाद शुल्कों की जंग तेज होने की आशंका भांपकर चीन विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे भारत के लिए होड़ बढ़ जाएगी। बता रहे हैं श्याम सरन

चीन की सालाना सेंट्रल इकनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस (सीईडब्ल्यूसी) आम तौर पर साल के आखिर में होती है। इसका बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि इससे पता चलता है कि चीनी नेतृत्व को गुजरते साल में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन कैसा लगा और आगे की चुनौतियों से निपटने के लिए वह क्या कदम उठाएगा।

इस साल सीईडब्ल्यूसी 11-12 दिसंबर को हुई, जब डॉनल्ड ट्रंप बतौर राष्ट्रपति अमेरिका की बागडोर संभालने जा रहे हैं। इससे पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो की बैठक हुई, जिसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति और भविष्य के लिए नीतियों की दिशा पर फैसला लिया गया। सीईडब्ल्यूसी में इन उपायों पर विस्तार से बात की गई मगर पहले की ही तरह बारीकियां नहीं बताईं। कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक माहौल प्रतिकूल होने की बात तो कही गई है मगर अमेरिका में ट्रंप सरकार द्वारा शुल्क लगाए या बढ़ाए जाने से होने वाले खतरों की आशंका पर कुछ भी नहीं कहा गया।

2023 की सीईडब्ल्यूसी बैठक से तुलना करें तो इस बार कुछ उल्लेखनीय बिंदु नजर आते हैं। पहला, मांग में ठहराव और बिगड़ती बाहरी आर्थिक चुनौतियों के बीच चीनी अर्थव्यवस्था में लगातार मंदी की बात स्वीकार करते हुए नेतृत्व ने अधिक बड़े आर्थिक प्रोत्साहन का रास्ता चुना। पहले उसका जोर 'दूरअंदेशी भरी मौद्रिक नीति' और 'व्यापक बदलाव के बजाय चुनिंदा हस्तक्षेप' पर था मगर अब उसकी जगह 'उदार मौद्रिक नीति' पर रजामंदी बन गई है।

इसका मतलब है ब्याज दरें कम रहेंगी, बैंकों की रीपो दर भी कम रहेगी और लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड अधिक मात्रा में जारी होंगे। पिछली बार यह शब्दावली वैश्विक वित्तीय एवं आर्थिक संकट के दौरान इस्तेमाल हुई थी, जब चीन ने अर्थव्यवस्था बचाने के लिए 600 अरब डॉलर का भारीभरकम राहत पैकेज जारी किया था। उस समय के लिहाज से यह रकम बहुत बड़ी थी। वह पैकेज मुख्य रूप से बुनियादी ढांचा निवेश के लिए था मगर इस बार का पैकेज देश के भीतर मांग और उपभोग व्यय बढ़ाने के मकसद से लाया गया है।

दूसरा, राजकोषीय नीति के मामले में चीन लीक पर चलने वाला रहा है और राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3 प्रतिशत की अनौपचारिक सीमा के भीतर ही रखता आया है। हाल के वर्षों में पहली बार राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी को स्वीकार किया जा रहा है। खबर हैं कि 2025 में देश का राजकोषीय घाटा 4 प्रतिशत रह सकता है।

तीसरा बिंदु यह है कि प्रोत्साहन के अधिक महत्त्वाकांक्षी उपाय करने के बाद भी तकनीक के बल पर उच्च गुणवत्ता वाली वृद्धि हासिल करने के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के पसंदीदा मॉडल पर बैठक में एक बार फिर मुहर लगाई गई है। नए प्रकार के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने वाली औद्योगिक नीति जारी रहेगी, जिसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) से वृद्धि पाने पर जोर रहेगा। चौथा, 2023 में सीईडब्ल्यूसी बैठक में 'समस्याओं से निपटने के बजाय विकास को प्राथमिकता' देने पर जोर दिया था। इस बार भी आर्थिक वृद्धि ही 'शीर्ष प्राथमिकता' है मगर अब 'विकास की रफ्तार और गुणवत्ता के बीच संतुलन' होना चाहिए। निचोड़ यह है कि शी चिनफिंग अर्थव्यवस्था के नए उच्च तकनीक से चलने वाले क्षेत्रों के विकास की खातिर उच्च वृद्धि दर को कुछ समय के लिए त्यागने को राजी हैं।

रिपोर्ट में शी की पसंदीदा योजना बेल्ट ऐंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) का कोई जिक्र नहीं है। शी ने विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक और एशियाई विकास बैंक समेत 10 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के प्रमुखों के साथ 10 दिसंबर को जो बैठक की थी, उसमें देश की आर्थिक सेहत को ट्रंप से होने वाले खतरों की चीनी चिंता ही केंद्र में रही। बैठक के दौरान शी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिकूल आर्थिक स्थिति की ओर सबका ध्यान खींचते हुए कहा कि 'अभूतपूर्व वैश्विक परिवर्तन की रफ्तार तेज होने के साथ ही दुनिया उथलपुथल और बदलाव के नए दौर में दाखिल हो गई है तथा एक बार फिर चौराहे पर खड़ी हो गई है।' उन्होंने भरोसा जताया कि चीन 5 प्रतिशत वृद्धि का अपना लक्ष्य हासिल कर लेगा और पिछले वर्षों की तरह वैश्विक जीडीपी वृद्धि में 30 प्रतिशत योगदान देता रहेगा।

शी ने बीआरआई का जिक्र भी किया और कहा कि ग्लोबल साउथ यानी विकासशील दुनिया को आगे बढ़ाने में उस योजना का बहुत योगदान है। उसे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठनों से हाथ बंटाने का अनुरोध किया। उन्होंने चीन और अमेरिका के संबंधों का खास जिक्र किया और कहा कि दोनों पक्षों के आपसी लाभ के लिए वह बातचीत करने, मतभेद दूर करने और सहयोग करने को तैयार हैं।

लेकिन उन्होंने अमेरिका की 'छोटा घर ऊंची चारदीवारी' वाली रणनीति को सिरे से खारिज करते हुए चेताया कि शुल्क, व्यापार और प्रौद्योगिकी की जंग में विजेता कोई नहीं होता। इसमें चीन के पलटवार की धमकी छिपी थी और अपनी संप्रभुता, सुरक्षा तथा विकास संबंधी हितों को बचाने का संकल्प भी था।

यदि ट्रंप डरे बगैर शुल्क की जंग को आगे बढ़ाते हैं तो चीन के पास क्या विकल्प बचेगा? निकट भविष्य में तो बहुत कम विकल्प हैं क्योंकि चीन अमेरिका और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं (यूरोप तथा जापान) से बहुत करीब से जुड़ा है। आगे जाकर वह स्पष्ट तौर पर दक्षिण-पूर्व एशिया, खाड़ी, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में व्यापार तथा निवेश के नए ठिकानों का रुख करेगा। इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। चीन के लिए सोयाबीन और अन्य कृषि उत्पादों का प्रमुख स्रोत अमेरिका था, जिसकी जगह अब लैटिन अमेरिका ले चुका है।

पसंदीदा आर्थिक एवं वाणिज्यिक साझेदार के रूप में ग्लोबल साउथ का महत्त्व बढ़ रहा है। सजा देने के लिए व्यापार का रास्ता अपनाया गया तो जैसे को तैसा वाला जवाब फौरन मिलेगा। चीन पहले ही अमेरिका को गैलियम जैसी दुर्लभ धातु का निर्यात रोक चुका है। अमेरिका बैटरी एवं कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इन धातुओं के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। चीन ने व्यापार के अनुचित तरीके अपनाने का आरोप लगाकर चिप बनाने वाली कंपनी एनविडिया के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी है। मगर इसके साथ ही उसने भविष्य के व्यापार समझौतों में अमेरिका से तेल एवं गैस आयात में भारी बढ़ोतरी करने की अपनी मंशा भी जाहिर कर दी है।

चीन भू-राजनीतिक नजर से ही नहीं बल्कि व्यापार और निवेश के साझेदार के रूप में भी ग्लोबल साउथ को देख रहा है। इस मामले में बीआरआई की भूमिका बहुत अहम रहेगी। विकासशील देशों में राजनीतिक एवं आर्थिक होड़ में भारत को चीन के सामने कड़ी मशक्कत करनी होगी। हमें आगे की नीतियां और समीकरण तैयार करते समय चीन की नीतिगत दशा में इस बदलाव का ख्याल रखना होगा।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में जो बदलाव हो रहे हैं और चीन से जो निवेश बाहर जा रहा है, भारत कम से कम अमेरिका, यूरोप और जापान के मामले में तो उसका फायदा नहीं उठा पाया है। हमारा कंपनी जगत कह रहा है कि अमेरिका और पश्चिमी बाजार पर अपनी जरूरत से ज्यादा निर्भरता कम करने के लिए चीन जो कदम उठा रहा है, उनका ज्यादा फायदा हम उठा सकते हैं। चीन ऐसी सोच को बढ़ावा दे रहा है। यह पेचीदा मसला है और इस पर बहुत बारीकी से सोचने-विचारने की जरूरत है वरना हम फिर ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, जहां हमारे नसीब का फैसला कोई और करेगा।

(लेखक विदेश सचिव रह चुके हैं)

शतरंज जगत में होगी मेंटल कोच की भरमार!

तकनीकी तंत्र

देवांशु दत्ता

पिछले दिनों ही शतरंज में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बने गुकेश दोम्माराजू के कामयाबी भरे इस सफर का एक पहलू बहुत दिलचस्प था और वह था पैडी अप्टन का उनकी टीम में शामिल होना। दक्षिण अफ्रीका के अप्टन प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेल चुके हैं और रग्बी के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। वह स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच के रूप में भी काम कर चुके हैं।

मगर अप्टन की असली पहचान मेंटल कोच (मानसिक मजबूती में मदद करने वाले) की है और वह 20 से ज्यादा खेलों में यह भूमिका निभा चुके हैं। भारत के लोग अप्टन को 2011 में क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम के हिस्से और 2020 में टोक्यो ओलिंपिक में हॉकी का कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सलाहकार के रूप में याद कर सकते हैं। अप्टन ने एक बेहद लोकप्रिय पुस्तक 'बेयरफुट कोच: लाइफ चॉजिंग इनसाइट्स फ्रॉम वर्किंग विद द वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिकेटर्स' भी लिखी है। अब इस किताब को शतरंज की दुनिया में भी खासी शोहरत मिल सकती है।

अप्टन खुद को शतरंज का नौसिखिया खिलाड़ी बताते हैं। मई में जब गुकेश के प्रायोजक ने उनसे संपर्क किया तो उन्हें हिचक भी हुई और उत्सुकता भी। बकौल अप्टन वह पहले कभी ऐसे खेल से नहीं जुड़े थे, जहां सारा खेल दिमाग का ही होता है। परंतु उन्होंने सोचा कि किसी भी खेल में प्रदर्शन सुधारने के गुर तो एक जैसे ही होते हैं।

अप्टन और गुकेश की बढ़िया छनने लगी और हर हफ्ते कुछ घंटे साथ में बिताकर वे ऊंचे दर्जे का शतरंज खेलने के तैयारी करते और उस पर चर्चा भी करते। नए विश्व चैंपियन ने अप्टन को पूरा सम्मान देते हुए संवाददाता सम्मेलन में उनके योगदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अप्टन ने उनका व्यायाम तथा नींद का समय दुरुस्त किया और मानसिक तौर पर उन्हें इस तरह तैयार किया कि वह खिताबी मुकाबले में किसी भी तरह की स्थिति का सामना कर सकें।

अप्टन से पूछिए तो उनके मुताबिक गुकेश किसी छात्र की तरह तैयारी करते हैं, जो परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम की सभी किताबों को शुरू से आखिर तक पढ़ता है। वह कहते हैं कि गुकेश ने पूरी 'किताब' पढ़ी है, समझ लिया है कि सही तरीके से नींद कैसे ली जाए, निराशा से कैसे उबरा जाए और खेल के हर पल में खुद को कैसे संभाला जाए। अप्टन गुकेश को जबरदस्त तैयारी वाला असाधारण पेशेवर बताते हैं, जो खुद को बहुत अच्छी तरह जानता है और 25 साल के उन सभी युवाओं से ज्यादा परिपक्व है, जिनके साथ उन्होंने काम किया है।

अप्टन कहते हैं कि किसी भी खेल में आने वाले युवाओं को एक चीज सीखनी चाहिए - किसी बड़े मुकाबले में पहली बार हिस्सा लें तो अपनी सामान्य शैली तथा सामान्य तरीके से खेलें और एकदम नए स्तर का खेल शुरू कर हारने का जोखिम मोल न लें। यह बहुत अहम बात है। आप बड़ी प्रतियोगिता में पहुंच ही इसीलिए पाए हैं क्योंकि आपका सामान्य स्तर वहां तक ले जाने के लिए काफी था। यह बात अजीब लग सकती है कि शतरंज सबसे ज्यादा दिमागी मशक्कत वाला खेल है फिर भी मानसिक तैयारी को इसके खिलाड़ियों की तैयारी का अभिन्न अंग बनने में इतना समय लग गया।

ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि शतरंज ने हमेशा खुद को दूसरे खेलों से अलग माना है। कुछ साल तक तो ऐसा रहा भी होगा मगर अब ऐसा नहीं है क्योंकि यह खेल टूर्नामेंट के सख्त माहौल में खेला जाता है, तय समय के भीतर चाल चलनी होती हैं और जीतने वाले को इनाम में भारी-भरकम रकम भी मिलती है। ऐसे में इसके खिलाड़ियों पर भी उस तरह के डर और घबराहट हावी रहते हैं, जैसे दूसरे खेलों में होते हैं और हरेक पेशेवर खिलाड़ी को इनसे निपटना तथा अपना हुनर निखारना सीखना चाहिए।

शतरंज के खिलाड़ी तस्वीरों (विजुअल पैटर्न) को पहचानने में बेहतर होते हैं और आम तौर पर सामान्य या कभी-कभार कुछ बेहतर मेधा वाले होते हैं। परंतु वे मान लेते हैं कि दिमागी खेल में एक दूसरे को पछाड़ने समेत बाकी बातों में भी वे उतने ही चतुर हैं। जरूरी नहीं है कि यह सच हो। यह बहुत कम संभव है कि एक पेशेवर शतरंज खिलाड़ी जिसने अपना समय खेल की ओपनिंग सीखने और कठिन खेलों से निपटना सीखने में लगाया हो वह अपने भावनात्मक उतारचढ़ाव से निपटने के मामले में किसी मनोवैज्ञानिक से बेहतर हो क्योंकि मनोवैज्ञानिक का तो काम ही दिमाग को समझना है। जिस पेशेवर शतरंज खिलाड़ी ने अपना वक्त बाजी की शुरुआती चालों में बढ़त हासिल करना और आखिरी लम्हों में मुश्किलों के बीच उम्दा चाल चलकर सामने वाले को मात देना सीखने में ही खपा दिया हो, वह अपने जज्बातों पर उस मनोवैज्ञानिक के मुकाबले ज्यादा अच्छी तरह काबू कर सकता है, जिसने अपनी जिंदगी ही दिमाग की गुत्थियां सुलझाने में लगा दी है, यह मानना मुश्किल है।

मेंटल कोचिंग यानी दिमागी प्रशिक्षण, प्रेरित करने वाला प्रशिक्षण जैसे कौशल वे हैं, जिनके असर को मापना और तय करना मुश्किल होता है। अप्टन कहते हैं कि एक अच्छा मेंटल कोच अव्वल दर्जे के खिलाड़ी के प्रदर्शन में एक-दो फीसदी सुधार ही कर सकता है। लेकिन जब आला दर्जे के दो खिलाड़ी भिड़ रहे हों तो इतना सा फर्क ही बहुत काम आ सकता है। शायद यही बात गुकेश का पलड़ा भारी बना गई हो।

परंतु इतने मामूली अंतर का आकलन कर पाना मुश्किल है और इंटरनेट ऐसी सेवाएं देने वाले नौसिखियों और धोखेबाजों से भरा पड़ा है। यह पता कर पाना वाकई बहुत मुश्किल है कि उनमें से कौन सही और काम का है। फिर भी अब अप्टन की मदद लेकर गुकेश शानदार सफलता हासिल कर चुके हैं तो दुनिया भर में शतरंज की प्रतिभाएं ऐसे कोच और ऐसी सेवाओं के बाजार का रुख करेंगे। हो सकता है कि दिमाग को पढ़ने वाले ऐसे प्रशिक्षकों का नया बाजार खड़ा हो जाए।

आपका पक्ष

राष्ट्रहित को आगे रखें राजनीतिक दल

लेख 'समग्र चर्चा जरूरी' में भारत के लोकतंत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत के लिए समग्र चर्चा के वास्ते राजनीतिक दलों का आह्वान किया गया है। जहां विपक्ष ने 'एक देश एक चुनाव' का विभिन्न कारणों से विरोध किया है, वहीं जनमानस में इसकी स्वीकार्यता बिल्कुल स्पष्ट है, इसका संज्ञान भी राजनीतिक दलों को लेना और स्वीकार करना चाहिए। जब संपूर्ण देश में लोक सभा, विधान सभाओं और स्थानीय चुनावों को समय पर करने में एकरूपता और समय-बद्धता के प्रति प्रतिबद्धता है तो यह लोकतंत्र का हनन कैसे हुआ, यह जनमानस नहीं समझ पा रहा। केवल चुनावों के समय का परिवर्तन है, निरंतरता में कोई अवरोध नहीं है। राजनीतिक दल अपनी आशंकाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर रहे और शोर शराबे से 'एक देश एक चुनाव' का विरोध कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा है कि वह राष्ट्र हित को आगे रखें। 'एक देश एक चुनाव' को लेकर राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों और मीडिया में एक चिंता यह भी है और इस के विरोध की चिंगारी बनी हुई है कि एक साथ लोक सभा और विधान सभाओं के चुनावों से स्थानीय विषय गौण हो जाएंगे। यह केवल एक भ्रम है क्योंकि इसमें जनमानस के विवेक पर प्रश्नचिह्न लगता है जो लोकतंत्र में कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर समय हर महीने चुनावों के शोर से जनता बहरी हो रही है और अरबों रुपये की देश, राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के आर्थिक संसाधनों की बरबादी अलग। हर समय चुनावों से देश विरोधी शक्तियों को उपजाऊ जमीन उपलब्ध होती रहती है। सभी राजनीतिक दलों को निजी हितों से ऊपर राष्ट्र हितों को वरीयता देनी होगी।

विनोद जौहरी, दिल्ली

संसद के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को राज्य सभा की कार्यवाही के दौरान पीठासीन सभापति तथा सांसद

बढ़ते सड़क हादसों पर चिंतन जरूरी

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 तक देश में सड़क दुर्घटनाओं में 7.77 लाख लोगों की मौत हुई। साल दर साल बढ़ते मौत के आंकड़े भयावह और चौंकाने वाले हैं। साथ ही कुछ हमारी और कुछ सरकार की गलतियों या लापरवाहियों को साफ दर्शा रहे हैं। देश में नई सड़कें जरूर बन रही हैं लेकिन पुरानी सड़कों के रखरखाव व पुलों की देखभाल में ढिलाई बरती जा रही है। इसके अलावा राज्यों के परिवहन विभाग वाहन चालकों को नियम पालन कराने में भी शिथिल नजर आते हैं। सरकार के साथ ही लोगों भी लापरवाही कम नहीं है। अव्यावहारिक स्पीड ब्रेकर व गड्ढे नुमा सड़कें भी दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है। अनहोनियों के इतर अगर नई-नई सड़कें बनाने के साथ ही पुरानी सड़कों की भी मरम्मत हो, परिवहन विभाग सख्ती से वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन कराए, समय-समय पर वाहनों की उचित जांच, चालकों पर अतिभार, लोगों की जल्दी गंतव्य तक पहुंचने के बुरी प्रवृत्ति, सार्वजनिक वाहनों में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने, सड़क पर गति सीमा पर वाहन चलाने आदि नियंत्रित रहे तो कई दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं।

शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ने गुरुवार को अपने सालाना संवाददाता सम्मेलन और 'कॉल-इन शो' कार्यक्रम के दौरान आर्थिक मोर्चे पर देश के तेजी से आगे बढ़ने के बारे में बात की और यूक्रेन में अपने सैनिकों की सफलता की सराहना की। इस वार्षिक कार्यक्रम का इस्तेमाल वह अपने प्रभुत्व का अहसास बनाए रखने और देश के राजनीतिक परिदृश्य पर व्यापक नियंत्रण होने का प्रदर्शन करने के लिए करते रहे हैं।

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शुक्रवार, 20 दिसंबर 2024

सहयोग संग सावधानी

भारत और चीन के बीच बुधवार को हुई विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत में बनी सहमति इस बात का ठोस संकेत है कि दोनों देशों के रिश्तों में पिछले चार साल से आया ठहराव धीरे-धीरे दूर हो रहा है। हालांकि यह प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है और इससे जुड़े कई किंतु-परंतु कायम हैं।

मानसरोवर यात्रा | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर बैठक के दौरान हुई

भारत-चीन: बढ़ रही सहमति

मुलाकात के बाद से मतभेद दूर करने की प्रक्रिया में जो तेजी आई, उसका असर पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर बने माहौल पर भी दिखा। पांच साल के अंतराल पर हुई विशेष प्रतिनिधियों की बैठक में सहमतियों पर अमल की तो पुष्टि हुई ही, यह संकेत भी मिला कि अब दोनों पक्ष इससे आगे बढ़ने को तैयार हैं। बॉर्डर ट्रेड, ट्रांस बॉर्डर नदियों पर डेटा शेयरिंग और मानसरोवर यात्रा की संभावनाएं वाकई उत्साह बढ़ाने वाली हैं।

सहयोग पर जोर | जैसे-जैसे सीमा संबंधी मसलों पर सहमति बन रही है और वहां माहौल सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है, दोनों देशों के रुख में सहयोग पर जोर भी बढ़ता जा रहा है। ध्यान रहे, चीन का काफी समय से आग्रह रहा है कि LAC से जुड़े मसलों को एक तरफ करके सहयोग बढ़ाया जाए, लेकिन भारत अपने इस रुख पर अडिग रहा कि जब तक LAC पर हालात सामान्य नहीं होते, रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। ऐसे में यह गौर करने वाली बात है कि अब भारत की तरफ से भी सहयोग का दायरा बढ़ाने की संभावना पर पॉजिटिव रुख दर्शाया जा रहा है।

बयानों में अंतर | इस बात को भी कुछ हलकों में रेखांकित किया गया है कि संबंधों में सुधार और बातचीत में प्रगति को व्यक्त करने के दोनों पक्षों के तरीकों में पूरी तरह समानता नहीं है। मिसाल के तौर पर, बातचीत के बाद दोनों तरफ से जो अलग-अलग बयान जारी किए गए, उनमें अंतर है। जहां चीन के बयान में स्पष्ट शब्दों में सर्वसम्मति के छह बिंदु गिनाए गए हैं, वहीं भारत के बयान में इन्हें सर्वसम्मति करार देने से बचा गया है।

LAC पर भारी हथियार | अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की ओर से बुधवार को ही जारी पेंटागन की सालाना रिपोर्ट की यह बात भी गौर करने लायक है कि चीन ने न तो गलवान घाटी में जून 2020 को हुई सैन्य झड़प के बाद इस क्षेत्र में बढ़ाई गई सैन्य तैनाती में कोई कमी की है और न ही टैंकों, मिसाइलों व अन्य भारी हथियारों की संख्या में कोई कटौती की है। हालांकि अभी उस इलाके से सैन्य वापसी की प्रक्रिया शुरू होनी बाकी है, लेकिन फिर भी चीन के पिछले रेकॉर्ड को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता।

रोज़-ब-रोज़

इमरान का मामला

शैलेंद्र पांडेय

विव रिचर्ड्स को परेशानी वखैम अकरम की बोलिंग से नहीं, उनके बोलने से थी। उन्होंने स्लेजिंग पर अकरम को बैट दिखाते हुए चेतावनी दी, 'सोट डू इट मैन'। अकरम ने कप्तान इमरान खान से कहा। इमरान ने अपने बोलर को हौसला देते हुए कहा कि कमेंट करना जारी रखो, मैं देख लूंगा। लेकिन, जब खेल खत्म हुआ और चिढ़े बैठे विव बैट लेकर पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम के बाहर खड़े हो गए तो इमरान ने मदद मांगने आए अकरम को जवाब दिया, 'तेरा मामला है, तू देख।' यहां तक का किस्सा अकरम कई बार शेयर कर चुके हैं, अब इसके बाद उन्होंने उस मामले को कैसे देखा, यह नहीं बताया। लेकिन, इमरान की यह वाली आदत लगता है कि गई नहीं, पहले लहकाओ और फिर साइड में खड़े हो जाओ। वह भीड़ में उठी उस आवाज की तरह हैं, जिसका काम लोगों को भड़काना भर है। एक बार जब मारपीट शुरू हो जाती है, तो आवाज लगाने वाला किधर लापता हो जाता है, किसी को भनक भी नहीं लगती।

इमरान ऐसी ही तांक फिर लगा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगें नहीं मानी गईं, तो विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों से कह देंगे कि मुल्क में पैसा न भेजो। इससे देश की इकॉनमी डूब जाएगी, जो पहले ही गले तक पानी में है। इमरान का दावा है कि लोग तैयार बैठे हैं, बस उनके इशारे का इंतजार है। याद होगा, पिछले महीने इमरान के बुलावे पर उनकी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता विरोध-प्रदर्शन करने इस्लामाबाद के हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंच गए थे। वहां उनका सामना पुलिस और सेना की गोलियों से हुआ। तब भीड़ तक इमरान का मेसेज पहुंचाने वाली और उकसाने वाली थीं बुशरा बीबी, इमरान की तीसरी बेगम। सुरक्षाकर्मियों ने जब हथियार निकाले, तो वह भी लापता हो गई थीं।

इमरान ने अब जो नई धमकी दी है, अगर वह थोड़ी भी सच होती है, तो क्या होगा? कुछ आंकड़े हैं, 2021 में जब कोरोना के चलते पूरी दुनिया बंद थी, तब रेमिटेंस में मिली रेकॉर्ड रकम 31 बिलियन डॉलर ने पाकिस्तान को चालू रखा था। 2023 में उसे 26.3 बिलियन डॉलर प्रवासी पाकिस्तानियों से मिले थे। इस साल इसके 33 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। यह पाकिस्तान की जीडीपी के लगभग 10% के बराबर है। विश्व बैंक के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024 में पाकिस्तान की गरीबी दर 40.5% थी। 26 लाख लोग तो केवल इसी साल गरीबी रेखा के नीचे चले गए। अगर इमरान के उकसावे में कुछ लोग आए, तो यह आंकड़ा और बढ़ा हो जाएगा। लोग गरीबी रेखा के नीचे जाएंगे, विदेशी मुद्रा भंडार भी नीचे जाएगा और महंगाई दर जो पहले ही 23.4% है, वह ऊपर की ओर बढ़ेगी। और इमरान... वह शायद तब भी जेल से कहें, 'तुम लोगों का मामला है, देख लो!'

एकदा

कला का महाराजा

एक दिन की बात है, मद्रास के गवर्नर डूयूक ऑफ बकिंघम तिरुवनंतपुरम की यात्रा पर आए। वह महान चित्रकार राजा रवि वर्मा के प्रशंसक थे। 1876 में रवि वर्मा ने उनका पोर्ट्रेट बनाया था। डूयूक ने एक विदेशी से भी अपना पोर्ट्रेट बनवाया था। पर उसमें इस चित्र जैसी बात नहीं थी। उन्होंने कहा भी था, 'मैंने उस चित्रकार को 18 सिटिंग दी थीं। पर उसका बनाया पोर्ट्रेट तो इस पोर्ट्रेट का आधा भी नहीं है।' इसलिए जब वह आए तो रवि वर्मा से भी मिले। उन्होंने रवि वर्मा से कहा, 'मैं आपका स्टूडियो देखना चाहता हूं।' रवि वर्मा चिंता में पड़ गए। स्टूडियो नए महाराजा ने बंद करवा दिया था। रवि वर्मा ने जुगाड़ लगाया। बोले, 'आप क्यों कष्ट करेंगे, मैं खुद आपके घर चित्र लेकर आ जाऊंगा।'

Subrata Char

तय समय पर रवि वर्मा चित्र लेकर पहुंचे। उस समय डूयूक ऑफ बकिंघम महाराजा विशाखम से बातचीत कर रहे थे। डूयूक ने उन्हें बैठने के लिए कहा, पर रवि वर्मा खड़े रहे। महाराजा के सामने कैसे बैठते? डूयूक कलाकारों की कद्र करना जानते थे। यह कैसे हो सकता है कि एक श्रेष्ठ चित्रकार खड़ा रहे और वे बैठे-बैठे उससे बात करें! डूयूक खड़े हो गए। अब तो महाराजा विशाखम को भी उठना पड़ा। उनका बैठे रहना सौजन्यता नहीं होती। डूयूक ने रवि वर्मा के चित्र देखे, उनकी प्रशंसा की। खड़े-खड़े तीनों बात करने लगे। रवि वर्मा ने महाराजा की ओर देखा। उनके मुख पर क्रोध का भाव था। एक कलाकार की कला ने उनका अभिमान तोड़ दिया था। आज उन महाराजा के बारे में कुछ ही लोग जानते हैं, लेकिन राजा रवि वर्मा को दुनिया जानती है।

संकलन : ज्योति वर्मा

श्रीलंका के राष्ट्रपति नई दिल्ली दौरे पर आए थे, इस दौरान दोनों देशों में कई मुद्दों को लेकर सहमति बनी

भारत और श्रीलंका नहीं तोड़ेंगे यह दोस्ती

हर्ष वी. पंत

सितंबर में देश की कमान संभालने के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके इसी हफ्ते भारत आए। दिसानायके को पहले राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिली, फिर उनकी पार्टी नेशनल पीपल्स पावर (NPP) ने 225 सदस्यों वाले संसदीय चुनाव में ऐतिहासिक विजय हासिल की और संसद पर उनका नियंत्रण हो गया।

जयशंकर की यात्रा | दिसानायके की जीत के 15 दिनों के अंदर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कोलंबो की यात्रा पर गए थे। राजनीतिक बदलाव के बाद श्रीलंका की यात्रा करने वाले वह पहले विदेश मंत्री बने। उन्होंने दिसानायके सरकार के साथ बातचीत में भारत-श्रीलंका के रिश्तों को बेहतर बनाए रखने की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया।

साझा हित | दिसानायके ने भी अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुनकर यह संदेश दिया कि श्रीलंका, भारत के साथ मजबूत साझेदारी चाहता है। भारत विरोधी जनता विमुक्ति पेरामुना (JVP) पार्टी से जुड़े होने के कारण दिसानायके को लेकर कुछ आशंकाएं थीं, लेकिन उन्होंने उसे दूर करने का संकेत दिया है। अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आकर उन्होंने संदेश दिया कि वह आपसी हितों के आधार पर रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं।

भारत के साथ | यात्रा में उन्होंने श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान मदद और लोन रिस्ट्रक्चरिंग में भारत की उदारता की सराहना की। उन्होंने यह बात भी दोहराई कि श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी तरह से नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने आशा जताई कि भारत के साथ आने वाले वक्त में सहयोग निश्चय ही और बढ़ेगा।

डिजिटल इन्फ्रा में मदद | भारत ने भी श्रीलंका के साथ टिकाऊ साझेदारी की अपनी प्रतिबद्धता जताई। यह भी कहा कि इसमें पड़ोसी मुल्क की ख्वाहिशों का ख्याल रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा बयान में इसका संकेत भी दिया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में भारत की जो द्विपक्षीय परियोजनाएं हैं, उनमें हमेशा उसकी विकास की प्राथमिकताओं का ख्याल रखा गया है। दोनों देश हाउसिंग, अक्षय ऊर्जा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कृषि, डेयरी, फिशरीज और डिजिटल आइडेंटिटी प्रॉजेक्ट में मिलकर काम करेंगे।

सहयोग पर सहमति
- भारत-चीन पर श्रीलंका की संतुलित नीति
- हिंद महासागर पर बढ़ेगा द्विपक्षीय सहयोग
- रक्षा क्षेत्र में भी द्विपक्षीय साझेदारी होगी अहम

रक्षा सहयोग | दिलचस्प बात यह है कि सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ने की आशा है क्योंकि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय समझौते को जल्द पूरा करने पर सहमति बनी है। संयुक्त अभ्यास, जॉइंट मैरीटाइम सर्विलांस और रक्षा संवाद जैसी पहल इसमें शामिल होंगी। असल में, हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल की वजह से श्रीलंका के साथ भारत के मजबूत रिश्ते काफी अहमियत रखते हैं। दिसानायके ने हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) को मुक्त, खुला, सुरक्षित बनाए रखने की बात कही, जिसमें भारत को लेकर संवेदनशीलता का ख्याल रखा गया।

तमिलों का मुद्दा | श्रीलंका की राजनीतिक स्थिरता और नई सरकार की नीतियों को देखते हुए लगता है कि भारत के साथ उसके रिश्ते और मजबूत होंगे, लेकिन कई ऐसे मुद्दे भी हैं, जिन्हें संजीदगी से लेना होगा। इनमें से एक श्रीलंकाई तमिलों का मुद्दा भी है। तमिल वहां अल्पसंख्यक हैं। प्रधानमंत्री ने यह मामला बड़ी ही संवेदनशीलता से उठाया। उन्होंने कहा कि वह आशा करते हैं श्रीलंका अपने संविधान को पूरी तरह से लागू करेगा और वहां की सरकार सूबों के चुनाव का वादा भी पूरा करेगी।

संतुलन का ख्याल | दिसानायके की यात्रा और उसके नतीजों से भारत को कई चिंताएं दूर हुई हैं। यह बात भी एक बार फिर साबित हुई कि भारत के पड़ोसी देश उसके और चीन के बीच संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि किसी एक ओर झुकने पर उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।

भारत ने दोस्ती निभाई | अगर श्रीलंका की बात करें तो आर्थिक संकट के दौरान भारत ने जिस तरह से उसकी मदद की, उससे वहां के सारे राजनीतिक दलों में भारत के प्रति अच्छी भावना बनी है। यह भी जाहिर हुआ कि भारत के साथ लंबी अवधि से रिश्तों की वजह से ही ऐसा हो पाया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि चाइना फैक्टर अब प्रासंगिक नहीं रह गया है। ऐसी खबरें आई हैं कि दिसानायके जल्द ही चीन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। लेकिन भारत का श्रीलंका के प्रति जो दोस्ताना रवैया रहा है, उसे देखते हुए साफ है कि श्रीलंका की विदेश नीति में वह अहम बना रहेगा।

लक्ष्मण रेखा | श्रीलंका इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता है कि भारत की लक्ष्मण रेखाएं क्या हैं। हिंद महासागर को लेकर भी दोनों देशों को आपस में सहयोग आगे भी जारी रखना चाहिए। इस क्षेत्र में चीन अपना दखल बढ़ाने की नीयत पहले से रखता है, जबकि पारंपरिक रूप से भारत यहां हमेशा से ही मजबूत रहा है।

(लेखक लंदन के किंग्स कॉलेज में प्रफेसर हैं)

देश की ग्लोबल ब्रैंडिंग का मौक़ा है कुंभ

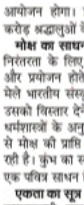

विरोध गुप्ता

मकर संक्रांति पर्व से प्रयागराज में ऐतिहासिक महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। यह भारत ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होगा। इस बार इसमें 40-45 करोड़ श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है।

मोक्ष का साधन | देश में संस्कृति की निरंतरता के लिए कई तरह के आयोजन और प्रयोजन होते रहे हैं। तीर्थयात्रा और मेले भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने व उसको विस्तार देने के ही उपक्रम हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार, पुण्यार्थ के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य की अंतिम इच्छा रही है। कुंभ का स्नान भी मोक्ष प्राप्ति का ही एक विशेष साधन है।

एकता का सूत्र | कुंभ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय संस्कृति की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोता है। देश में आज विभिन्न धर्म और संस्कृतियों के बीच खुद को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ है। ऐसे समय में कुंभ जैसे आयोजन भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सहनशीलता को अपने अंदर समेटे हुए है।

पुण्य पाने का अवसर | कुंभ पर गंगा का स्नान महज स्नान नहीं, उस पवित्र नदी में डुबकी है जिससे इंसान पाप से पुण्य की ओर चल पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि कुंभ के समय पृथ्वी पर अमृत उतरता है। इस अमृत को पाने की चाह में ही दुनियाभर से श्रद्धालु आकर्षित होते हैं कुंभ की ओर। कुंभ हमारी पुरातन भारतीय सभ्यता के बहुत बड़े स्तंभ हैं, जो धर्म और अध्यात्म के उत्कर्ष का मार्ग आलोकित करते हैं। ये भारत के ज्ञान का विस्तार हैं। यही कारण है कि विभिन्न मठ-अखाड़ों से जुड़े साधु-संत, संन्यासी मत वैभिन्यता को भुलाकर एक साथ जुटते हैं और शाही स्नान करते हैं।

बेमिसाल अनुशासन | दुनिया में ऐसा कोई भी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक संगठन नहीं है, जो 30-40 करोड़ लोगों को जुटाने और उनके बीच अनुशासन बनाए रखने का दावा कर सके। यह उपलब्धि केवल कुंभ के हिस्से है, जहां श्रद्धालु अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर और विश्वास से भरकर आते हैं। कुंभ भारत की धर्मपरायण संस्कृति की उच्चता को ही प्रदर्शित नहीं करता, यह विभिन्न समुदायों के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संवाद की परंपरा का अग्रदूत भी है।

मार्गदर्शन करेगा कुंभ | इस बार यह

कॉमन रूम

आयोजन ऐसे समय हो रहा है, जब हमारे सामने ग्लोबल वॉर्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण, जल संकट, आतंकवाद और अतिवाद जैसी चुनौतियां हैं। देश की सामूहिकता, सामुदायिकता, धार्मिक और आध्यात्मिक दांचा, आस्था, परंपराएं, मूल्य और संस्कार अपनी भारतीय अस्मिता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यही नहीं, पुरानी और नई पीढ़ी के बीच बढ़ती दूरी भी चिंता का कारण बनी हुई है। ऐसे समय में महाकुंभ निश्चित तौर पर रास्ता दिखाएगा।

सुनहरा अवसर | इस बार संगम नगरी में होने वाला आयोजन हाईटेक होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का मानना है कि महाकुंभ के माध्यम से भारत की सनातन संस्कृति का सम्यक साक्षात्कार करने का हमारे पास सुनहरा अवसर है। यह आयोजन केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि भारत की ग्लोबल ब्रैंडिंग का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। इस बार स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधाओं के नए मानक स्थापित होने की उम्मीद है। महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए इसे नया जिला ही घोषित कर दिया गया है।

सुखद संयोग | महाकुंभ भारत की महान धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्कृति का सामूहिक प्रकटीकरण है। यह बेहद खुशी की बात है कि महाकुंभ के दौरान ही भगवान श्रीराम के अयोध्या में निर्मित भव्य मंदिर का एक साल पूरा होगा। यह भी सुखद संयोग है कि श्रीराम का जन्मस्थान उत्तर प्रदेश में है और इस बार का महाकुंभ भी इसी प्रदेश में आयोजित हो रहा है। इसलिए प्रयागराज महाकुंभ में केवल तीन पवित्र नदियों का त्रिपक्षीय मिलन ही नहीं, दो सनातन संस्कृतियों का महासम्मिलन भी होने जा रहा है। यह कहने में कोई हिचक नहीं कि यह महाकुंभ राष्ट्र की उज्ज्वल छवि को वैश्विक स्तर तक स्वीकृति और प्रशस्ति दिलाने का शानदार अवसर साबित होगा।

(लेखक उत्तर प्रदेश वाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं)

अब और इंतजार नहीं

कांग्रेस के अंदर बड़े बदलाव की आवाज पिछले कई महीनों से उठ रही है। पार्टी नेतृत्व ने इस बारे में पहले भी कई मौकों पर संकेत दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक पार्टी में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब पार्टी के अंदर से बदलाव की

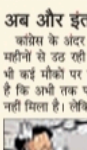

आवाज जोर-शोर से उठने लगी है। कांग्रेस नेताओं का एक बड़ा वर्ग अगले हफ्ते बेंगलुरु में होने वाली मीटिंग का इंतजार कर रहा है। वहां 26 दिसंबर को मीटिंग होनी है। उसके तुरंत बाद अगर बदलाव नहीं हुआ तो एक बार फिर से पार्टी का पुराना सिरदर्द G23 समूह सक्रिय हो सकता है। हालांकि इस बार इस G23 में दूसरे नेता होंगे। इन नेताओं का आरोप है कि पार्टी के अंदर फैसले नहीं होने से वर्करों में अब बेचैनी होने लगी है। नेताओं का यह समूह पार्टी को चेतावनी दे रहा है कि अगर अब बड़े फैसले नहीं लिए गए, तो ये वर्कर अपने लिए नया विकल्प तलाशना शुरू कर देंगे। ऐसा हुआ तो पार्टी के लिए आगे की राह और कठिन हो जाएगी। कांग्रेस नेतृत्व को भी इसका अहसास होने लगा है और यह बदलाव का ब्लूप्रिंट तैयार पेश करने की तैयारी में है। दरअसल, बदलाव की सारी प्रक्रिया एक अहम पद पर आकर रुक जा रही है। पार्टी के इस सबसे अहम पद पर किस तरह का बदलाव हो और किसे वहां रखा जाए, यही चुनौती इसमें सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है।

विशुद्ध राजनीति

पॉलिटॉक

नई किताब, नया सिरदर्द

कांग्रेस को नई किताबें अक्सर सिरदर्द देती रही हैं। पार्टी के सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर अपनी किताब के साथ सामने आए, जिसमें उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए। हालांकि उनके सवालों की कोई खास चर्चा नहीं हो पाई। पार्टी को उनसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी किताब में ऐसे सवाल उठाएंगे। अब चर्चा है कि पार्टी के एक और सीनियर नेता अपनी किताब लेकर आ रहे हैं। उसमें काफी राजनीतिक मसाला होने की बात कही जा रही है। पार्टी नेतृत्व किताब का कंटेंट पता लगाने की कोशिश कर

रहा है। इससे पहले जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे किताब लेकर आ गए थे। इसमें उन्होंने ऐसी बात लिख दी, जिससे BJP को कश्मीर में कांग्रेस पर हमला करने का पूरा मसाला मिल गया। 2014 में भी पीएम डॉ. मनमोहन सिंह के सलाहकार की लिखी किताब ने राजनीतिक बवाल मचा दिया था और उससे पार्टी को बहुत नुकसान हुआ था। कांग्रेस के एक नेता ने इस ट्रेंड पर चुटकी लेते हुए कहा कि BJP इसलिए अपने नेताओं को लिखने की अनुमति नहीं देती है।

कौन बोले, कौन नहीं

संविधान पर लोकसभा में हुई चर्चा में कांग्रेस की ओर से कौन-कौन स्पीकर भाग लेंगे, इस बारे में पार्टी में अंतिम समय तक दुविधा रही। सबसे बड़ी दुविधा तो इस बात को लेकर थी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, दोनों संविधान पर हो रही इस बहस में भाग लें या नहीं। एक वर्ग का मानना था कि एक बहस में दोनों का भाषण न हो। लेकिन दूसरा तर्क यह आया कि बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब तकरीबन हर बहस में भाग लेंगे, ऐसे में इस आधार पर प्रियंका गांधी को दूर रखना सही नहीं होगा। जाहिर है, दूसरे तर्क की जीत हुई और आखिरकार प्रियंका गांधी को बहस में उतारा गया।

दुविधा में सांसद

इन दिनों दो क्षेत्रीय दलों के सांसदों के अगले कदम को लेकर बहुत चर्चा है। एक पार्टी के राज्यसभा सांसदों के बारे में लोकसभा चुनाव के बाद से उलझन है, तो दूसरी पार्टी के लोकसभा सांसदों के बारे में हालिया विधानसभा चुनाव के बाद उलझन बन गई है। इनके बारे में तरह-तरह की चर्चाएं उठ रही हैं और दबे स्वरों में कहा जा रहा है कि मौका मिलने पर वे पाला बदल सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं उठने के बाद इन दोनों दलों के नेतृत्व के भी कान खड़े हो चुके हैं। संसद सत्र के दौरान दोनों दलों के सांसदों को हमेशा एक साथ दिखाने की कोशिश की गई। किसी न किसी बहाने उन्हें एक साथ लाया जाता रहा, जिससे संदेश जा सके कि सब साथ हैं और टूट की खबर बेबुनियाद है। लेकिन अंदरखाने की चर्चा के अनुसार ऊपर से भले ही सब ठीक-ठाक दिखाया जा रहा हो, टूट की बात में दम है। दोनों दलों के सांसद अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं और वे अपने लिए तमाम विकल्प टटोल रहे हैं।

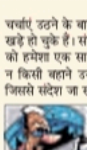

एक दल के सांसद ने कहा कि वे ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां उन्हें आगे की राह समझ नहीं आ रही है। उन्होंने माना कि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है और कल जाकर वे क्या कदम उठाएंगे, उन्हें खुद नहीं पता है।

होमवर्क ने बिगाड़ा प्लान

केंद्र सरकार के कई मंत्री और BJP के नेता साल के अंत में आकर कुछ राहत महसूस कर रहे थे। इनमें कुछ मंत्रियों ने विदेश दौरा भी तय कर लिया था ताकि पिछले एक साल से लगातार जारी थकान से कुछ राहत पा सकें।

इनका कहना है कि तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव, उसके बाद आम चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव के कारण पिछला एक साल बहुत दबाव भरा निकला। न सांस लेने की जरा सी फुरसत मिली और न ही परिवार के साथ समय बिताने की। ऐसे में संसद के मौजूदा सत्र के तुरंत बाद सभी ने छोटा ब्रेक लेने की योजना बनाई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐन मौके पर कई मंत्रियों और नेताओं को लोगों तक संवाद पहुंचाने का नया होमवर्क दे दिया। सभी जानते हैं कि जब पीएम मोदी कोई होमवर्क दे दें तो फिर कुछ दिनों बाद उस पर रिपोर्ट भी लेते हैं। ऐसे में अब सब इस कशमकश में हैं कि पहले हल्का ब्रेक लें, या होमवर्क पूरा करने के बाद निकलें। हालांकि कुछ नेताओं और मंत्रियों ने छोटा ब्रेक लेने की अनुमति ले ली है।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

परीक्षा प्रणाली में सुधार

संपादकीय 'अमल का सवाल' (19 दिसंबर) में नैशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की नई जिम्मेदारियों और चुनौतियों पर विस्तृत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। यह विषय आज के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। NEET पेपर लीक जैसी घटनाओं ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। ऐसे में NTA का वकीलों के समक्ष करना और उसे केवल प्रतियोगी परीक्षाओं तक सीमित करना एक सराहनीय कदम है। इससे न केवल परीक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि पेपर लीक जैसी घटनाओं की आशंका भी कम होगी।

जयदेव चौधरी, इंदिरापुरम

भारत की अलग समस्या

संपादकीय पेज पर 19 दिसंबर को प्रकाशित लेख 'प्रदूषण पर चीन से क्या सीख सकता है भारत' पढ़ा। चीन ने 2013 के बाद वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो ठोस कदम उठाए, वे अनुकरणीय हैं। विशेष रूप से, उद्योगों, वाहनों और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सुधार और नियमों का सख्ती से पालन यह दिखाता है कि एक मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति से कठिन लक्ष्यों को भी हासिल किया जा सकता है। हालांकि, भारत में प्रदूषण के स्रोत और जटिलताएं चीन से अलग हैं। हमारे देश में पराली जलाने, पुराने वाहन और ठोस कचरे जलाने जैसी समस्याएं प्रमुख हैं।

दिनेश शर्मा, गुड़गांव

तकनीक में महिलाएं

19 दिसंबर को आयी दुनिया कॉलम में प्रकाशित लेख 'चुनौतियों से संबल' पढ़ा। मीनाक्षी चंद्रशेखरन द्वारा AI के संभावित प्रभावों पर प्रस्तुत दृष्टिकोण प्रेरणादायक है, खासकर स्वास्थ्य सेवा में AI के उपयोग की उनकी कल्पना। यह स्पष्ट है कि AI के जरिए स्वास्थ्य क्षेत्र में रियल टाइम डेटा के आधार पर सटीक और त्वरित निदान संभव हो सकता है। यह न केवल चिकित्सा सेवाओं को तेज करेगा बल्कि इलाज को अधिक सटीक और प्रभावी बनाएगा।

अर्जुन प्रसाद सिंह, लोनी

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

इटावा सफारी में आयुर्वेदिक दवाएं खाकर कब्ज भगा रहे शेर- एक खबर

– अब दहाड़ने से पहले पेट तो हल्का होना ही चाहिए।

मानसी अरोड़ा

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

हिंसा से मुक्त नहीं हो सकते पर ईसा तो बन सकते हैं

महात्मा गांधी

अहिंसा सर्वोच्च प्रकार की सक्रिय शक्ति है। वह आत्मबल या हमारे भीतर विराजमान भगवान की शक्ति है। अपूर्ण मानव उसे पूरा ग्रहण नहीं कर सकता। वह उसके संपूर्ण तेजपुंज को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। परंतु उसका लेशमात्र भी जब हमारे भीतर सक्रिय बन जाता है तब वह गजब का काम करता है। सूर्य सारे विश्व को गरमी देता है। परंतु कोई उसके बहुत निकट चला जाए, तो उसे वह जलाकर राख कर देगा। इसी तरह ईश्वर की बात है। हम जिस हद तक अहिंसा को सिद्ध करते हैं, उसी सीमा तक ईश्वर के सदृश बनते हैं, परंतु हम पूरी तरह ईश्वर कभी नहीं बन सकते।

मानव जाति के हाथ में अहिंसा सबसे बड़ा बल है। विनाश मानव का धर्म नहीं है। मनुष्य अपने भाई के हाथों जरूरत पड़ने पर मरने को तैयार रहकर आजादी से जीता है, उसे मारकर हरगिज नहीं। दया, अहिंसा, प्रेम और सत्य के सद्गुणों की परीक्षा किसी मनुष्य में तभी हो सकती है जब उनका मुकाबला क्रूरता, हिंसा, वैर और असत्य आदि से होता है। यह सच है तो यह कहना गलत होगा कि एक हत्यारे के सामने अहिंसा काम नहीं देगी। यह अवश्य कहा जा सकता है कि एक हत्यारे के सामने अहिंसा का प्रयोग करना आत्म-विनाश को न्यौता देना है। अहिंसा की यही सच्ची कसौटी है। परंतु जो निरी लाचारी के कारण अपना वध होने देता है उसके लिए यह हरगिज नहीं कहा जा सकता कि उसने यह परीक्षा पास कर ली है। जो वध होते समय भी अपने हत्यारे के प्रति क्रोध नहीं करता, बल्कि ईश्वर से भी उसे क्षमा करने को कहता है वही सच्चमुच अहिंसक है।

इतिहास ईसा मसीह का ऐसा ही वर्णन करता है। सूली पर अंतिम सांस लेते समय उन्होंने अपने हत्यारों के बारे में ऐसा कहा बताते हैं- 'परम पिता, इन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं।' दूसरे धर्मों से भी हमें ऐसे ही उदाहरण मिल सकते हैं, परंतु यह उद्धरण इसीलिए दिया गया है कि यह विश्व-विख्यात है। यह दूसरी बात है कि हमारी अहिंसा अभी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंची है। हमारे लिए यह बिलकुल गलत होगा कि हम अपने ही दोष के या अनुभव के अभाव के कारण अहिंसा का स्तर नीचा कर दें। आदर्श को सही तौर पर समझे बिना हम उस तक पहुंचने की कभी आशा नहीं रख सकते। इसलिए यह जरूरी है कि हम अहिंसा की शक्ति को समझने में अपनी बुद्धि लगाएं।

अहिंसा एक व्यापक सिद्धांत है। हम हिंसा की ज्वाला में फंसे हुए असहाय प्राणी हैं। 'जीवो जीवस्य जीवनम्' में एक गहरा अर्थ है। मनुष्य जाने-अनजाने बाह्य हिंसा किए बिना नहीं रह सकता। उसके जीने में - खाने-पीने और चलने-फिरने में कुछ न कुछ हिंसा होती ही है, फिर वह कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हो। इसीलिए यदि अहिंसा के पुजारी के सब कामों का स्रोत दया है, यदि

चिंतन

संसद लोकतंत्र का मंदिर, यह धक्का-मुक्की का स्थान नहीं

संसद लोकतंत्र का मंदिर है। यह राजनीतिक कलह का मंच नहीं है, लेकिन लंबे समय से जिस तरह संसद की मर्यादा का जबरदस्त ह्रास हो रहा है, यह न केवल लोकतंत्र बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। देश के 97 करोड़ मतदाता सांसदों को चुनकर संसद में इसलिए भेजते हैं कि वे देश की समस्याओं, विकास और युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करने के लिए चर्चा करें और देश को आगे बढ़ाएं। लेकिन संसद में जो हो रहा है वो देश को चिंता में डालने वाला है। युवा के सपने साकार करने के बजाए सांसद सदन में धक्का-मुक्की कर रहे हैं। बात केवल सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष की नहीं है। यह मंच हर देशवासी का है। गुरुवार को संसद में जो हुआ उससे पूरा देश शर्मसार है। संसद परिसर में धक्का-मुक्की के दौरान ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, जो उनके ऊपर गिरा। सारंगी जब मीडिया के सामने आए, तब उनके सिर से खून निकल रहा था। सारंगी के अलावा फर्रुखाबाद के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई है। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। धक्का-मुक्की को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम शांति से प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन भाजपा ने मसल पावर दिखाई। ये उनका अड़ाणी जैसे जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का तरीका है। वहीं, भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर खड़गे-राहुल को माफी नहीं मांगनी थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। उनका अहंकार झलक रहा है। आज जो संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कांग्रेस ने गुंडे-पहलवान संसद में भेजे हैं। बात यह नहीं है कि कसूर सत्ता पक्ष का है या विपक्ष का। संसद सदस्यों पर विधि निर्माण और संविधान संशोधन की जिम्मेदारी है। आश्चर्य है कि अनेक सदस्य कार्यवाही में बाधा डालते हैं। नियमावली की भी उपेक्षा करते हैं। इससे आहत पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने सदन की नियमावली को ही जला देने की बात कही थी। विद्यायी संस्थाओं में विधि और नियम का उल्लंघन साधारण घटना नहीं है। सदनों में कार्यवाही की गुणवत्ता की चिंता पुरानी है और इसमें कोई सुधार होने की बजाए हर सत्र के बाद यह गंभीर होती जा रही है। एक समय था जब विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही कार्यवाही की पवित्रता के प्रति सजग थे। हमेशा सदन की मर्यादा का ध्यान रखा जाता था। शोर-शराबा और हंगामा विपक्ष का काम नहीं है। राहुल गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के वक्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने लोकसभा के एक प्रकाशन की भूमिका में लिखा है, संसद में अनुशासनहीनता और अव्यवस्था से मर्यादा क्षीण होती है। नागरिकों में लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, लेकिन हो रहा है बिलकुल इसके विपरीत। बहुत जरूरी है कि संसद के सभी दलों के संसदीय पदाधिकारी परस्पर संवाद बनाएं। संसद में मर्यादा बनाए रखने के विषय पर संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार करें। पवित्र सदन में संवाद के स्थान पर अव्यवस्था उचित नहीं। इससे न केवल हर देशवासी आहत होता है बल्कि पूरे दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र की पवित्रता पर भी आंच आती है। इस पर सभी दलों को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

विश्लेषण
शशि शेखर

कृतज्ञता की भी होती है एक सीमा

> बाबा साहेब ने कहा था 'हम भारतीयों को एक महान व्यक्ति के पैरों में अपनी स्वतंत्रता गिरवी नहीं रखनी चाहिए और तमाम शक्तियों से लैस उस महान व्यक्ति पर भी ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, जिससे कि वह हमारी संस्थाओं का नाश करने में सक्षम हो जाए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि हम उन लोगों के प्रति आभारी बनें, जिन्होंने देश के लिए जीवन भर सेवाएं दीं, लेकिन कृतज्ञता की भी एक सीमा होनी चाहिए। भक्ति (किसी व्यक्ति की) या नायक पूजा लोकतंत्र के क्षरण और संभावित तानाशाही के लिए एक मार्ग प्रशस्त करती है।' इस उक्ति को मैं इंदिरा गांधी से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री तक के संदर्भ में देखता हूं।

अमित शाह के बयान को बाबा साहेब के संविधान सभा में दिए अंतिम भाषण के सन्दर्भ में देखना काफी दिलचस्प होगा। अमित शाह की यह एक खूबी राजनीति में रेयर है, पॉलिटिकल करेक्ट न हो तब भी वो बात कहने की ताकत। बाबा साहेब ने संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में तीन महत्वपूर्ण बातें कही थी। ये बातें नहीं चेतावनी थी। भारत के हर नागरिक को इसे ताबीज बना कर अपने गले से लटका कर चलना चाहिए, क्योंकि ये तीन चेतावनियां ही हैं जो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का सशक्त नागरिक होने का एहसास कराती हैं।

बाबा साहेब ने जॉन स्टुअर्ट मिल को कोट करते हुए कहा था 'हम भारतीयों को एक महान व्यक्ति के पैरों में अपनी स्वतंत्रता गिरवी नहीं रखनी चाहिए और तमाम शक्तियों से लैस उस महान व्यक्ति पर भी ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, जिससे कि वह हमारी संस्थाओं का नाश करने में सक्षम हो जाए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि हम उन लोगों के प्रति आभारी बनें, जिन्होंने देश के लिए जीवन भर सेवाएं दीं, लेकिन कृतज्ञता की भी एक सीमा होनी चाहिए। भक्ति (किसी व्यक्ति की) या नायक पूजा लोकतंत्र के क्षरण और संभावित तानाशाही के लिए एक मार्ग प्रशस्त करती है।' इस उक्ति को मैं इंदिरा गांधी से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री तक के संदर्भ में देखता हूं। कदाचित, मैं अमित शाह की तारीफ नहीं करता। लेकिन, कल-परसों जब बाबा साहेब वाली टिप्पणी उन्होंने की, तो मुझे लगा कि यह शख्स इतना अबूझ भी नहीं की राजनीतिक रूप से इतना खतरनाक बयान दे। यह शायद इस व्यक्ति की मूलवृति है कि सच बोल दो, भले नुकसान हो जाए। वैसे भी जो अपने घर से निकाला जा चुका हो, उसे और अधिक भय क्या होगा?

गांधी जी के चतुर बनिए बयान से बाबा साहेब पर ताजा बयान तक, अमित शाह का बयान मैं सिर्फ और सिर्फ उपरोक्त कोट (बाबा साहेब के भाषण) के सन्दर्भ में ही देखना चाहता हूं। और तमाम बाबा साहेब में आस्था रखने वालों से पूछना चाहता हूं कि आप बाबा साहेब को कितना जानते हैं, कितना अपभाते हैं और क्या आपने सिर्फ इसी एक भाषण के अंश को पढ़ा और समझा है, जिसमें बाबा साहेब खुद व्यक्ति पूजा, नायक पूजा को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं। आप बाबा साहेब के निर्देश (पढ़ो-लिखो, ताकतवर बनो) पर कितना अमल करते हैं। आपके लिए नायक प्रोफेसर रतन लाल होने चाहिए, जिन्होंने पढ़ लिखकर अपने समाज के लिए मिसाल पेश की या कोई दुच्चा नेता, जिसकी भाषा में भी बाबा साहेब की शाब्दिक गरिमा तक नहीं झलकती? या आपको मैनिपुलेट करने वाला एक दुच्चा टाइप पूर्व पत्रकार जो आजकल सरकार की नायक और व्यक्ति पूजा में लीन है? मैं बस इन चंद सरल सवालों तक ही रुक जाता हूं। क्योंकि मेरे कठिन प्रश्न अलबत्ता आपको समझ नहीं आएंगे, आ भी गए तो जवाब आप दे नहीं पाएंगे। ऐसे में अमित शाह ने बिलकुल सही कहा कि आप किसी व्यक्ति को फैशनेबल बना कर अपने समाज या राष्ट्र का भला नहीं कर सकते।

जैसे, वीर सावरकर या दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेते रहने से हिन्दुओं का कोई भला नहीं होने वाला है।

क्योंकि मैं तमाम भाजपा समर्थकों से सिर्फ इतना पूछ लूं कि दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का संपूर्ण संरक्षण (स्पाइरल स्टूवर्ट) का अर्थ क्या है, तो मुंह बा देंगे। इसलिए, मुझे लगता है कि पॉपुलर परसेप्शन से दूर जाकर खतरनाक सच बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। यह हिम्मत मैं राहुल गांधी में भी कई बार देखता हूं, लेकिन मनुस्मृति बिना पढ़े उस पर टिप्पणी करके वे कभी-कभी लड़खड़ा जाते हैं। ऐसे में अमित शाह का बयान राजनीतिक रूप से भले करेक्ट न हो, व्यवहार्य में एकदम सटीक है। आप माने ना माने। हिन्दुस्तान के दलित विमर्श में या अन्य ऐसे किसी भी ऐसे विमर्श को लेकर एक बड़ी दुविधाजनक स्थिति है। दलित साहित्य पर बात प्रेमचंद करेंगे, लेकिन उनकी आलोचना होगी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री दोक्टोरे श्रीकृष्ण सिंह देवघर के मंदिर में दलितों को एंट्री दिलाएंगे और भारत का पहला राज्य बिहार को बनाएंगे जहां, बाकायदा क़ानून बनाकर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, लेकिन उन्हें हमेशा सवर्णों का नेता ही माना जाएगा।

वैसे ही वीपी सिंह ने मंडल आयोग के जरिये एक मूक सामाजिक क्रान्ति ला दी, लेकिन पिछड़ों का नेता उन्हें कभी नहीं माना जाएगा। तो, यह सब परसेप्शन और एक आम धारणा का खेल है, जो अक्सर राजनीति में सबसे फिट बैठता है। मसलन, मुस्लिम तुष्टिकरण एक ऐसा शब्द है, जिसे मैं आज तक समझ नहीं पाया। 70 साल तक अगर किसी एक कौम का तुष्टिकरण किसी दल ने किया, तब भी वह कौम आज विकास के सभी पैमानों पर कहां है, इसे बताने के लिए इस देश को सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमिशन बनाना पड़ता है। ऐसे में, बाबा साहेब के नाम पर या कांशीराम जी के नाम पर राजनीति तो होगी ही, लेकिन उनके विचारों को कितना अमल में लाया जाएगा, यह किसी के एजेंडे पर नहीं है। चाहे वह कांग्रेस हो, मायावती हो या भाजपा ही क्यों न हो? इस हमाम में सब साफ़-सुथरे कपड़े पहनकर मजा ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में अमित शाह या किसी भी नेता के द्वारा बाबा साहेब पर ऐसा बयान देना कितना खतरनाक हो सकता है, सब जानते हैं। फिर भी, सच बोलना हिम्मत की बात है। अमित शाह ने हिम्मत के साथ बयान दिया। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि मैं इस बयान को सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब के उपरोक्त भाषण के नजरिये से ही देख रहा हूं। रही बात विकास की, तो कौन किसका विकास करता है, यह सबर्ण भी जानते हैं, दलित भी जानते हैं, पिछड़े भी जानते हैं, अल्पसंख्यक भी। लेकिन, राजनीति है और राजनीति सबको करनी है, सो राजनीति का लोकतंत्र का नृत्य जारी है।

बता दें कि बुधवार 18 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था, 'अभी एक फैशन बन गया है... अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता।' अमित शाह के बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर को लेकर दिए गए इस बयान पर राजनीति गरमा गई है। पूरे देश में बाबा साहेब के अनुयायियों और विपक्ष में गृहमंत्री अमित शाह के लिए जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश व्याप्त है। वहीं, अमित शाह ने इस पूरे मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरे बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। पहले उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के एडिटेड कर के शेयर किया था। मैं मीडिया से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वह मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखें, मैं उस पार्टी से हूं जो कभी भी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, अम्बेडकर जी के सिद्धांतों का पालन किया। हमने आंबेडकर जी के सिद्धांतों का प्रचार किया है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

प्रौद्योगिकी

प्रमोद भार्गव

विलो-क्वांटम चिप कंप्यूटर तकनीक का नया आधार

गूगल ने वर्ष 2024 के अंतिम माह दिसंबर में विलो नाम की क्वांटम चिप बनाकर तकनीक के क्षेत्र में बड़ा हल्ला मचा दिया है। अत्यंत सूक्ष्म महज 4 वर्ग सेंटीमीटर की यह चिप एक तरफ तो 30 साल से भी ज्यादा पुरानी समस्या का हल खोजने में सक्षम है, वहीं यह चिप 5 मिनट में ऐसे कार्य कर सकती है, जिन्हें करने में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को भी 10 सेप्टिलियन अर्थात अरबों साल लग सकते हैं। अतएव इससे कृत्रिम बुद्धि, फ्यूजन ऊर्जा तथा ब्रह्मांड के तारामंडल के गृह-नक्षत्रों को जानने में मदद मिलेगी। मौसम व प्राकृतिक आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी करने में सुविधा होगी। तकनीक के क्षेत्र में इस नवीन उपलब्धि की सर्वत्र चर्चा है। एलन मस्क जैसे लोग इस उत्पाद को लेकर अचंभित हैं। इसलिए इसे सुपर ब्रेन की संज्ञा दी जा रही है। विलो चिप व्यावसायिक रूप में क्वांटम कंप्यूटिंग की नई दिशा तय करती हुई मील का पत्थर साबित होगी। दुनिया में इस समय दिन दूनी ,रात चौगुनी गति से प्रगति हो रही है। कुछ समय पहले तक असंभव सी लगने वाली चीजें आज प्रौद्योगिकी की मदद से सरलता से परिणाम तक पहुंच रही हैं। एक समय संगणक के विकास ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया था। अब कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) ने चिकित्सा से लेकर हथियारों के निर्माण तक हर क्षेत्र में कंप्यूटर और रोबोट के प्रयोग को नया आयाम दिया है। पारंपरिक कंप्यूटर की दुनिया में इस प्रगति के समानांतर एक और अनुसंधान चल रहा है, जिसका नाम है 'क्वांटम कंप्यूटिंग' यानी अति-सूक्ष्मता का विज्ञान। भारत ने भी अब इस क्षेत्र में गति लाने का ऐलान कर दिया है। भौतिक-शास्त्र के क्वांटम सिद्धांत पर काम करने वाली इस कंप्यूटिंग में असीमित संभावनाएं देखी जा रही हैं। शोध के लिहाज से यह विषय किसी के लिए भी रुचिकर हो सकता है। इस क्वांटम कंप्यूटिंग या मैकेनिक्स की खास बात यह है कि इसकी शुरुआत के बाद भारतीय और पश्चिमी वैज्ञानिक यह मान रहे हैं कि भारतीय भाववादी सिद्धांत को जाने बिना अणु या कण में चेतना का आकलन नहीं किया जा सकता। क्वांटम भौतिकी और कृत्रिम बौद्धिकता एक तरह से चेतना के भाववादी सिद्धांत को ही अस्तित्व में लाने के उपाय हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग या यांत्रिकी एक लैटिन शब्द है। इसका अर्थ अतिसूक्ष्म कण है। इस विषय के अंतर्गत पदार्थ के अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। इनमें परमाणु, न्यूक्लियस एवं इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन सभी मौलिक कणों का अध्ययन शामिल है। इसमें इनके व्यवहार और उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है।

क्वांटम सिद्धांत के तहत अणु, परमाणु और इनके भी मूलभूत कण बेहद लघुतम अवस्था में मौजूद रहते हैं। इस खोज पर 1918 में मैक्स प्लांक को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1924 में सत्येंद्रनाथ बोस ने प्लांक के विकिरण नियम को समझाने के लिए एक सर्वथा नवीन विधि सुझाई। उन्होंने प्रकाश की कल्पना द्रव्यमानरहित कणों के एक गैस पिंड के रूप में ली। इसे फोटॉन गैस के रूप में मान्यता मिली। बाद में इस मान्यता को अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी स्वीकृति दी। कण-यांत्रिकी को कल के कंप्यूटर का भविष्य माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसकी मदद से आंकड़ों और सूचनाओं को कम से कम समय में प्रसारित किया जा सकेगा। एआई,जीपीटी चेट और चैटबॉट जैसी तकनीक इसकी सहायता से और तेजी से गतिशील रहेंगी। लेकिन विलो चिप निर्माण कर लिए जाने की घोषणा ने सुपर कंप्यूटर के निर्माताओं को फिलहाल सकते में डाल दिया है क्योंकि विलो चिप की क्षमताएं ब्रह्मांड व्यास की तरह शक्तिशाली और असीमित बताई गई हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि क्वांटम यांत्रिकी का क्षेत्र जितना महत्वपूर्ण है, उस तुलना में इस क्षेत्र में कुशल युवाओं की संख्या बहुत कम है।

क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता को देखते हुए इसके विकास में भारत समेत अनेक देश लगे हैं। यही वजह है कि आविष्कार से पहले इसकी क्षमताओं का मूल्यांकन कर लेने वाले देश इसके अनुसंधान पर बड़ी राशि खर्च कर रहे हैं। चीन ने 15 अरब डॉलर खर्च करने की घोषणा की है। यूरोपीय यूनियन ने इस क्षेत्र में करीब 8 अरब डॉलर खर्च कर रही है। भारत सरकार ने भी इस दिशा में शोध को बढ़ावा देने के लिए क्वांटम सूचना-विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था का गठन तो पहले ही कर लिया था, लेकिन केवल क्वांटम तकनीक पर नवीन शोध और आविष्कार के लिए 2023-24 से 2030-31 तक चलने वाले इस अभियान पर इस 6003.65 करोड़ खर्च किए जाएंगे। भारत इतनी बड़ी राशि पहली बार खर्च कर रहा है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

जीवन का प्रथम अनुबंध किसको माना है?

संकलित
दर्शन

अनुबंध चतुष्टय में 'अधिकारी' को प्रथम अनुबंध स्वीकार किया गया है। मानव की आध्यात्मिक और लौकिक यात्रा के निर्विघ्न संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लोक में इसके लिए योग्यता या पात्रता पद का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य है, किसी कार्य के निष्पादनार्थ पात्रता प्राप्त करना।सामान्यतः प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति पात्र नहीं होता। इसलिए अनधिकारी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य सफल और लोकमंगलकारी हो, यह आवश्यक नहीं, परंतु अधिकारी (पात्र) व्यक्ति द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य सफल भी होता है और लोकमंगलकारी भी। इसलिए अधिकारी आत्मिक और जागतिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला मानव जीवन का प्रथम अनुबंध है। इसीलिए इसे शास्त्रों में विशेष महत्व दिया गया है। वेदांत में अधिकारी को परिभाषित करते हुए कहा गया-जिसने विधिवत ज्ञान प्राप्त कर काम्य एवं निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर दिया है। नित्य, नैमित्तिक और उपासनादि कर्म करने से जिसकी बुद्धि परिष्कृत और अंतःकरण निर्मल हो चुका है, ऐसा पापरहित व्यक्ति ही विशिष्ट ज्ञान का अधिकारी है। विश्वामित्र आदि ऋषियों ने अधिकारी समझकर ही राम को विविध आयुध प्रदान किए, जिससे उनका दुरुपयोग न हो सके। जैसे अधिकारी व्यक्ति का ज्ञान लोकमंगल के लिए होता है, उसी प्रकार अधिकारी को प्रदान की गई शक्तियां समाज, देश और मानवता की रक्षा के लिए होती हैं। इतिहास साक्षी है कि जब भी अनधिकारी को शक्तियां प्रदान की गई हैं, उनका दुरुपयोग ही हुआ है।

हनुमान जी ने सूर्य देव से हासिल किया था ज्ञान

संकलित
प्रेरणा

गुरु पूर्णिमा पर गुरु का पूजन किया जाता है। शास्त्रों में गुरु को भगवान के बराबर माना गया है। महाभारत, रामायण में गुरु-शिष्य से जुड़ी कई कथाएं हैं। सूर्य पंचदेवों में से एक हैं और हनुमान जी के गुरु भी हैं। बाल हनुमान जब थोड़े बड़े हुए तो माता अंजनी और पिता केसरी ने उन्हें सूर्य देव के पास ज्ञान हासिल करने के लिए भेजा। माता-पिता की बात मानकर हनुमान जी ने सूर्य देव के पास पहुंचे और उनसे गुरु बनने के लिए प्रार्थना की। हनुमान जी की बात सुनकर सूर्य देव ने कहा कि मैं तो एक पल के लिए कहीं रूका नहीं हूं, न ही मैं रथ से उतर सकता हूं तो ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे पाऊंगा। तब हनुमान जी ने कहा कि आप अपनी गति कम किए बिना ही मुझे ज्ञान दीजिए। मैं आपके साथ चलते-चलते विद्या हासिल कर लूंगा। इस बात के लिए सूर्य देव मान गए। इसके बाद सूर्य देव ने हनुमान जी को सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान दिया। इस प्रकार सूर्यदेव की कृपा से ही हनुमान जी को ज्ञान मिला। इस प्रसंग में हनुमान जी ने संदेश दिया है कि योग्य गुरु से ज्ञान हासिल के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। योग्य गुरु ही हमें सही ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। आज योग्य गुरु की तलाश काफी कठिन हो गई है।

अंतर्मन

आज की पाती

खरमास में न करें मांगलिक कार्य

सनातन धर्म में खरमास की अवधि को अत्यधिक महत्वपूर्ण समय माना जाता है। खरमास की अवधि वर्ष में दो बार आती है और प्रत्येक बार यह लगभग 30 दिनों की होती है। देखा जाए तो इनमें से एक अवधि प्रायः मार्गशीर्ष एवं पौष महीने के संधिकाल में आती है, जब खरमास का जन्म होता है। इस बार 15 दिसंबर रविवार को खरमास आरंभ हो गया है, जो 14 जनवरी मंगलवार तक रहेगा। हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णन है कि खरमास के दौरान अंशु तथा भग नामक दो आदित्य, कश्यप और क्रतु नाम के दो ऋषि, महाफन एवं कर्कोटक नाम के दो नाग, विज्ञांग और अर्णायु नामक दो गंधर्व, सह तथा सहस्या नाम की दो अप्सराएं, तार्क्ष एवं अरिष्टनेमि नाम के दो यक्ष और आप तथा वात नाम के दो राक्षस सूर्यदेव के रथ के साथ-साथ चलते हैं। खरमास की अवधि में पूजा-पाठ करें, परंतु मांगलिक कार्य न करें। - मनोज सुक्ल, राजनांदगांव

ट्रेंड

कांग्रेस आरक्षण विरोधी

कथक कालेलकर आयोग और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने वाली कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। राजीव गांधी जी ने तबसे लंबा भाषण ओबीसी आरक्षण के विरोध में दिया था।

-अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

भाजपा की मंशा

भाजपाई बाबासाहेब के बनाये संविधान को आज तबसे हवा विरोधी लगती है क्योंकि उनवाले लगता है कि वो जिस प्रकार संविधान दलित का शोषण करके आजतक प्रभुत्व कायम रखना चाहते है, उनकी इस मंशा के आगे संविधान ढाल बनकर खड़ा है।

-अखिलेश यादव, सपा सांसद

थोरियम का सबसे बड़ा भंडार

दुनिया में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत के पास है? प्रधान मंत्री ने थोरियम हमारे पास थोरियम को यूरेनियम में बदलने और छोटे रिएक्टरों का उपयोग करके उससे बिजली पैदा करने की तकनीक है जो लगातार प्रतिरूपी है। परमाणु ऊर्जा देश का पेटन्ट कराल सकती है।

-अनिल अग्रवाल, उद्योगपति

मेरा व्यंग्य संग्रह

मेरे व्यंग्य संग्रह "मौन मुस्कान की मार" का एक व्यंग्य 'मंकुजी पटेल उर्फ बीसीसी' सत्ता मिले तो सुनिएगा, व्यंग्य का लिंक मेरे एक्स अकाउंट पर उपलब्ध है। अफसोस लेकिन मेरे परिवार का कहना है।

-आशुतोष राणा, अभिनेता

करंट अफेयर

भारत, अमेरिका ने अंतरिक्ष सहयोग की रूपरेखा तैयार की

भारत और अमेरिका के अधिकारियों ने अंतरिक्ष सहयोग में अगले कदमों की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान, संयुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण और बढ़ती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष कंपनियों के बीच वाणिज्यिक साझेदारी को सुविधाजनक बनाने की प्रतिबद्धता शामिल है। व्हाइट हाउस ने बुधवार को बताया कि इस संबंध में शुरुटन में 17 दिसंबर को एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें अमेरिका के प्रधान उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर, उप विदेश मंत्री कर्ट कैम्पबेल और अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा शामिल हुए। व्हाइट हाउस ने एक तथ्य-पत्र में कहा, ''(पूर्व) राष्ट्रपति (जो) बाइडन और प्रधानमंत्री (नरेन्द्र) मोदी की जून 2023 में 'अंतरिक्ष सहयोग के सभी क्षेत्रों में नयी ऊंचाइयों तक पहुंचने' के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता और भारत के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देश नागरिक, सुरक्षा और वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचे।' उसने कहा, 'इसमें मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान, संयुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण और बढ़ती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी और भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों के बीच वाणिज्यिक साझेदारी को सुविधाजनक बनाने की प्रतिबद्धता शामिल है।'

ऑफ बीट

अध्ययन से स्पष्ट, लोग नकदी कम खर्च करते हैं

मेहनत की कमाई किसी को देना हमेशा से थोड़ा कष्टदायी होता है। और ऐतिहासिक रूप से, अध्ययनों में पता चला है कि ग्राहकों को जब नकदी में भुगतान करना होता है तो वे कम पैसा खर्च करते हैं। इस सदी की शुरुआत में यह पता लगाने अध्ययन किया गया था कि ज्यादातर उपभोक्ता नकदी से भुगतान करते हैं या फिर प्री-पेड कार्ड का उपयोग करके। अध्ययन में पता चला कि लोग नकदी कम खर्च करते हैं। इस अध्ययन के दौरान किराने की एक दुकान में उपभोक्ता रसीदों की पड़ताल करके इसकी पुष्टि की गई थी। साक्ष्य यह भी बताते हैं कि ग्राहक पारंपरिक रूप से नकदी की जगह डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके ज्यादा भुगतान करते रहे हैं। भुगतान का तरीका आपके मनोविज्ञान से जुड़ा होता है। यह भी पता चला है कि नकद पैसे देने से भुगतान का कष्ट उपभोग के आनंद को फीका कर देता है। वास्तव में, यह पता चला है कि नकदी का उपयोग मन को दुखी कर देता है। यह भी पता चला है कि मोबाइल भुगतान (उदाहरण के लिए, फोन या स्मार्टवॉच से) भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड के उपयोग की तरह ही खर्च को प्रभावित करता है। यानी, नकदी की तुलना में मोबाइल से भुगतान करते समय अधिक पैसा खर्च होता है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

हिन्दुस्तान

संसद में आचरण

भारतीय संसद के प्रांगण में फिर अप्रिय स्थिति का उत्पन्न होना हर लिहाज से दुखद और निंदनीय है। दो सांसद घायल हो गए, तो कई सांसदों ने धक्का-मुक्की की शिकायत की है। आरोप-प्रत्यारोप की वजह से परिवेश ऐसा बन गया है, मानो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शुद्ध शत्रुता हो गई हो। और तो और, धक्का-मुक्की, दुर्व्यवहार जैसे आरोपों की पुलिस तक पहुंचने की नौबत आ गई। वास्तव में, यह जो कटुता फैल रही है, उसका समय रहते उपचार करना चाहिए। अगर उपचार न किया गया, तो संसद में काफी कुछ अप्रिय होने की आशंका को बल मिलेगा। दल चाहे जो हो, जो भी सांसद धक्का-मुक्की में शामिल रहे हैं, उन्हें यह संदेश देने की जरूरत है कि संसद ऐसे किसी संघर्ष का अखाड़ा नहीं है। संसद और संविधान, दोनों ही सांसदों से उच्च गरिमा की आशा करते हैं। संसद देश की आवाजों और दलीलों का मंच है, यह किसी भी प्रकार की शारीरिक जोर-आजमाइश का मंच न बने, इसी में सबकी भलाई है। हर सांसद को फिर संसद की आचार संहिता को पढ़ना चाहिए। जो सांसद नहीं जानते, उन्हें बताना चाहिए कि संसद में ऐसे दृश्य को लोग स्वीकार नहीं करेंगे।

सांसदों को समग्रता में सोचना चाहिए कि अगर आगे एफआईआर की राजनीति बढ़ेगी, तो सभी को परेशानी होगी। संसद में तनाव कोई नई बात नहीं है। तनाव और तल्खी का इतिहास रहा है, पर बहुत कम अवसर ऐसे आए हैं, जब शारीरिक बल का दुरुपयोग देखा गया है। संसद भवन के प्रांगण में ही नहीं, बल्कि देश में कहीं भी सांसदों को ऐसे आमने-सामने नहीं आना चाहिए, जैसे गुरुवार को देश ने देखा है। लोकसभा प्रांगण में अच्छा आचरण सुनिश्चित करने की क्षमता और अधिकार जो भी नेता या अधिकारी रखते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। वैसे भी, यह बात छिपेगी नहीं कि वास्तव में धक्का-मुक्की किसने शुरू की। संसद भवन के प्रांगण में जगह-जगह कैमरे लगे हैं। उन कैमरों की मदद से कम से कम यह तो सुनिश्चित करना चाहिए कि सच की जीत हो और झूठ खुद को सुधारे। अगर किसी सांसद के सिर में चोट लगी है, तो यह वैसे भी गंभीर मामला है। भाजपा सांसद प्रताप सारंगी ने यही बताया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वजह से एक व्यक्ति उनसे टकराया और वह गिर गए। पक्ष-विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप लगेंगे, पर ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सच सामने आए। यदि सच सामने न आए, तो कम से कम सभी सांसद ऐसी स्थिति फिर न बनने दें, यह भी पर्याप्त होगा।

संसद देश की आवाजों और दलीलों का मंच है, संसद किसी भी प्रकार की शारीरिक जोर-आजमाइश का मंच न बने, इसी में सबकी भलाई है।

यह समझना होगा कि उग्र राजनीति का देश नहीं है। यह अलग-अलग विचारों के बीच सद्भाव, समन्वय की राजनीति का देश है। यह भी सोचना चाहिए कि जिस महापुरुष भीमराव आंबेडकर के नाम पर अप्रिय स्थिति बनी, क्या वह स्वयं ऐसे व्यवहार की प्रशंसा करते? बाबा साहेब का संसद या संविधान सभा में जीवन ज्यादा नहीं रहा, वह दो-दो बार चुनाव हार गए, पर उन्होंने कभी भी अपने विरोधियों, अपने प्रतिद्वंद्वी दल के नेताओं के प्रति द्वेष का भाव नहीं बढ़ाया। बाबा साहेब का भी बार-बार अपमान हुआ, पर उन्होंने कभी आपा नहीं खोया। खुलकर या मुखरता से अपने विचार रखे। कभी किसी को अपशब्द नहीं कहे, कभी किसी बल प्रयोग का हिस्सा नहीं बने। ऐसे बाबा साहेब के नाम पर किसी भी प्रदर्शन या प्रति-प्रदर्शन को शालीनता की सुरक्षित सीमाओं में ही रखना होगा, ताकि संविधान के तहत देश के सर्वोच्च जन-प्रतिनिधि मंच की मर्यादा अक्षुण्ण रहे।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 20 दिसंबर, 1949

काश्मीर कमीशन की गलती

काश्मीर के मामले में जो गतिरोध उत्पन्न हो गया है, उसके लिए पाकिस्तान का दुराग्रह तो जिम्मेदार है ही, स्वयं काश्मीर कमीशन भी कम उत्तरदायी नहीं है। काश्मीर कमीशन ने अपनी विफलता की जो रिपोर्ट सुरक्षा कौंसिल को भेजी थी, वह सर्वसम्मत नहीं थी। कमीशन के चेक सदस्य ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। उन्होंने अपनी अलग रिपोर्ट लिखी है, उससे उपरोक्त तथ्य भली-भांति सामने आ जाता है। चेक सदस्य डा. चीले ने सबसे बड़ा उद्घाटन कमीशन के पंच फैसले के सुझाव के संबंध में किया है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा कौंसिल ने कमीशन को जो आदेश दिया था, पंच फैसले का सुझाव उसकी सीमा के बाहर था। विग्रम-संधि के लिए भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के सम्मेलन का प्रस्ताव विचाराधीन था, तभी कमीशन ने पंच फैसले के सुझाव पर सोच-विचार शुरू कर दिया। कमीशन ने पंच फैसले की जो योजना तैयार की, वह एक गोपनीय दस्तावेज था, किन्तु वह दस्तावेज भारत और पाकिस्तान की सरकारों के सामने रखा गया, उसके साथ-साथ या उससे भी पहले अमरीकी और ब्रिटिश राजदूतों को दे दिया गया और उसके आधार पर अमरीकी राष्ट्रपति श्री ट्रूमैन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री एटली ने भारत और पाकिस्तान की सरकारों से सार्वजनिक रूप से पंच फैसले के सुझाव को स्वीकार करने का अनुरोध किया। डा. चीले ने अमरीकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के इस कार्य को कमीशन के कार्य में हस्तक्षेप बताया है। उन्हें कमीशन के एक सदस्य की हैसियत से ऐसी शिकायत करने का पूरा हक है। थोड़ी देर के लिए यह माना जा सकता है कि अमरीका के राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री यह कदम उठाने में पूरी सद्भावना से प्रेरित थे, फिर भी उनके इस कार्य पर संयुक्त राष्ट्र संघ के और सदस्य आपत्ति कर सकते हैं।

पाकिस्तान ने तो पंच फैसले का सुझाव स्वीकार कर लिया था, किन्तु भारत ने ब्रिटिश और अमरीका के हस्तक्षेप पर एक परेशानी जरूर महसूस की और उनके अनुरोध को अस्वीकार करने में काफी जोखम का सामना करना पड़ा। इस देश में लोकमत ने ट्रूमैन और एटली की अपील का स्वागत नहीं किया था। जहां नाजुक मामला विचाराधीन हो वहां यदि आवश्यक सावधानी न रखी जाये, तो मामला बिगड़ सकता है, जैसा कि काश्मीर के मामलों में हुआ है।

बाबा साहेब के लिए सियासी बवाल

यहां स्कैन करें

विजय त्रिवेदी | वरिष्ठ पत्रकार

पिछले दस वर्ष में बाबा साहेब के विचार व विरासत को लेकर लड़ाई बहुत तेज हो गई है। दोनों बड़े दलों के बीच छिड़ी यह लड़ाई अनेक पड़ावों से गुजरी है और आगे अभी गुजरेगी।

जिंदगी के दो पहलू हैं- विचार और विरासत। समाज में ज्यादातर लड़ाइयां इन्हीं दो को लेकर हो रही हैं। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद केवल एक शख्स डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के लिए यह कहा जा सकता है, जिनके विचार और विरासत, दोनों को हासिल या कब्जा करने के लिए आज संघर्ष चल रहा है।

एक संघर्ष यह है कि बाबा साहेब के विचारों के साथ कौन चलेगा? दूसरा संघर्ष यह है कि बाबा साहेब की विरासत किसके पास होनी चाहिए? हम अगर आंबेडकर को पढ़ें और जानें, तो वह स्वयं विचार व विरासत की लड़ाई से आगे रहे। न उन्होंने किसी की विरासत पर कब्जा किया और न किसी एक विचार को पकड़कर जड़ बने। उन्होंने समाज की बदलती ताकत और हालात को ध्यान में रखकर ऐसे नए विचारों को जन्म दिया, जिन्हें अपनाना हिम्मत भरा काम है।

पिछले दस वर्ष में अगर देखें, तो बाबा साहेब के विचार और विरासत को लेकर लड़ाई बहुत तेज हो गई है। यह लड़ाई राजनीतिक ताकत और वोट बैंक के रूप में बदल गई है। सत्तारूढ़ भाजपा के राष्ट्रीय फलक पर नरेंद्र मोदी के आने के बाद सवर्णों और ब्राह्मण-बनियों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा ने आंबेडकर की विचारधारा को मजबूत करने की लड़ाई शुरू की। इसका नतीजा यह हुआ कि आज भाजपा के पास बड़े अनुपात में दलितों का समर्थन है।

याद करना चाहिए कि जब 2014 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे, अमित शाह उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रभारी थे, तब भाजपा वहां कमजोर थी, अमित शाह ने पूरी दलित समीकरण में दखल देकर सियासी नक्शे को बदल दिया। उन्होंने उन दलितों पर फोकस किया, जिन्हें तब तक वाजिब अधिकार नहीं मिले थे। भाजपा ने दलितों का नया वोट बैंक तैयार कर लिया, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी अहम भूमिका रही। मोहन भागवत ने एक नारा दिया- एक मंदिर, एक कुआं, एक श्मशान। मतलब छुआछूत या भेदभाव दूर करने का एक नया नारा निकला, जो काम कर गया। संघ ने दूसरा काम यह किया कि वंचित जातियों के लोक देवताओं, नेताओं को पूरा सम्मान दिया, उनके मेले लगाए, इससे पार्टी का जनाधार बढ़ा। आश्चर्य नहीं कि देश में भाजपा के पास 75 से ज्यादा दलित सांसद हो गए और पिछड़ों का बड़ा समूह साथ आया।

दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस भी आंबेडकर को अपना नेता मानती रही है। दलितों और मुस्लिमों को साथ लेकर अपनी राजनीति चलाती रही है। बरसा जब उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई, तब कांग्रेस के दलित वोटों में कमी आई, कुछ अन्य दलों ने भी कांग्रेस से दलित वोट बैंक छीना और वह कमजोर होती गई।

बीते दस वर्ष की बात करें, तो सरकार में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आंबेडकर से दूर करने के लिए काम शुरू कर दिए। बार-बार बताया गया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ न्याय नहीं किया। उन्हें दो बार चुनाव में हराया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया। एक पत्र नेहरू ने माउंटबेटन को लिखा था, जिसमें कहा गया कि आंबेडकर को अगर मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए, तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। यह चर्चा भी बार-बार की गई कि कांग्रेस ने नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी को भारत रत्न दिया, मगर बाबा साहेब को नहीं दिया। बताया गया कि इसका मतलब, कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है। ऐसे आरोपों से छुटकारा पाने में कांग्रेस को लगातार मुश्किल हो रही थी। कांग्रेस की ये दलीलें पर्याप्त सिद्ध नहीं हो रही थीं कि नेहरू ने ही बाबा साहेब को संविधान सभा का सदस्य बनाया, मसौदा समिति का प्रमुख बनाया और कानून मंत्री बनाया। बाद में पहला दलित राष्ट्रपति भी कांग्रेस ने ही दिया। काम तो कांग्रेस ने भी किए हैं, पर वह भाजपा के आरोपों से खुद को बचा नहीं पा रही थी। इस बीच नरेंद्र मोदी ने पंचतीर्थ का निर्माण कर बताया कि आंबेडकर उनके सम्मानित नेता हैं। भाजपा ने जैसे सरदार पटेल को अपने साथ ले लिया, वैसे ही बाबा साहेब को ले लिया। बाबा साहेब के लिए ही संविधान दिवस मनाने का कार्यक्रम भाजपा ने शुरू किया।

समावेशी राजनीति की कोशिश के बावजूद भाजपा को तगड़ा झटका तब लगा, जब विपक्ष ने साल 2024 के चुनाव में संविधान को बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने बार-बार बताया कि भाजपा अगर 400 पार पहुंची, तो बाबा साहेब का संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। इस प्रचार का भाजपा जवाब नहीं दे पाई और आम चुनाव में खास तौर पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में उसकी सीटें आधी से कम हो गईं। कांग्रेस को दलितों के जितने वोट मिले, भाजपा ने लगभग उतने ही गंवा दिए। यहीं से आंबेडकर की विरासत को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच लड़ाई और तेज हो गई। पिछले पांच चुनाव को देखें, तो निघर दलित रहे हैं, उसी दल या गठबंधन की सरकार बनी है।

संसद में संविधान पर हुई बहस में जब गृह मंत्री अमित शाह ने आंबेडकर का नाम लेते हुए कांग्रेस पर तंज किया कि वह केवल दिखावे के लिए आंबेडकर का नाम लेती है, पर कांग्रेस को मौका मिल गया। शब्दों के सहारे कांग्रेस ने आंबेडकर के अपमान को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। सरकार को घेरने की कोशिश ही धक्का-मुक्की और दुर्व्यहार तक पहुंच गई। अब बाबा साहेब की विरासत की लड़ाई कहां खत्म होगी, कहना मुश्किल है। भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। कितना अच्छा होता कि दोनों दल विरासत के लिए लड़ने के बजाय बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाते? क्या आज किसी पार्टी के पास अभी तक वंचित दलितों के उत्थान की कोई नई योजना है?

अब आगे क्या होगा? जातिगत जनगणना की मांग को बल मिल सकता है। मंडल-2 या आरक्षण का अगला चरण शुरू हो सकता है। भाजपा दलितों के पक्ष में किसी योजना के साथ सामने आ सकती है। श्रीराम मंदिर बनने के बाद कमंडल की राजनीति के बजाय मंडल की राजनीति का ज्यादा जोर रह सकता है।

एक सवाल और है, वह है बड़े दलों के अलावा ऐसी पार्टियां भी हैं, जो बाबा साहेब का नाम लेकर दलितों-पिछड़ों की लड़ाई लड़ती रही हैं। अब इन पार्टियों का रुख क्या होगा? दोनों बड़े दल नहीं चाहेंगे कि बाबा साहेब की विरासत बसपा जैसे दलों के पास लौटे। मतलब- चल रहा संग्राम जारी रहेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जनहित की बड़ी समस्या उठे और समाधान तक पहुंचे

यहां स्कैन करें

विजय केलकर | अर्थशास्त्री व शिक्षाविद

हाल के वर्षों में भारतीय न्यायपालिका द्वारा स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति पर महत्वपूर्ण बहस छिड़ी हुई है। मूल रूप से इसका मकसद सार्वजनिक या जनहित की रक्षा करना और न्याय सुनिश्चित करना है। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, जिन पर अगर अदालत संज्ञान न ले, तो सरकार का ध्यान ही नहीं जाएगा। वैसे, अब इस शक्ति के संभावित दुरुपयोग की जांच की जा रही है। हालांकि, यह शक्ति अदालतों के लिए अत्यावश्यक और असाधारण मामलों में हस्तक्षेप का महत्वपूर्ण उपकरण बनी हुई है।

जो मामले पहले से ही निचली अदालतों में चल रहे हैं, जिन मामलों में राजनीतिक प्रेरणा से फैसले प्रभावित हो सकते हैं, वहां भी संज्ञान लेने की परिपाटी ने चिंता बढ़ाई है। इससे न केवल आंतरिक की भावना पैदा होती है, बल्कि समाधान में भी देरी होती है। उदाहरण के लिए, कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुखद बलात्कार और हत्या के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया। यह ध्यान देने की बात है कि इस मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय ने पहले ही महत्वपूर्ण कदम उठा लिए थे। बिना जरूरत सर्वोच्च स्तर पर संज्ञान लेने से निचली अदालतों के क्षेत्राधिकार में भी तनाव पैदा हो सकता है।

न्यायालयों को मिली स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति बहुत आवश्यक है, पर इसके प्रयोग के अनुकूल परिणाम सबके सामने आने चाहिए।

कई बार स्वतः संज्ञान की शक्ति किसी मामले में प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करने में नाकाम रहती है। उदाहरण के लिए, शीर्ष अदालत ने कोविड 19 संकट के समय लोगों के स्वास्थ्य के अधिकार की चिंता की थी, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का एक प्रमुख घटक है। शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप ने शुरू में उम्मीदें जगाईं, चिकित्सा सुविधाओं पर सबका ध्यान गया, लेकिन ठोस परिणाम के अभाव ने न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं को उजागर कर दिया। अगर अदालतें अपने काम में व्यस्त रहें और उनके आदेशों-निर्देशों का कोई नतीजा न निकले, तो न्यायिक शक्ति के प्रति लोगों का विश्वास घटता है।

दूसरा उदाहरण देखिए, यमुना नदी का प्रदूषण आज भी चिंता का विषय है। साल 1994 में प्रारंभिक न्यायिक हस्तक्षेप के बावजूद, इस मामले को देश के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पास जाने में दो दशक से अधिक समय लग गया। भारत में सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक के समाधान में यह देरी स्वतः संज्ञान शक्ति की एक प्रमुख कमजोरी को दर्शाती है। हालांकि, स्वतः संज्ञान लेना महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है, पर इन मामलों में लंबे समय तक निष्क्रियता अक्सर न्यायिक प्रक्रिया के प्रति निराशा और मोहभंग का भाव पैदा करती है। ध्यान रहे, ऐसा उस देश में हो रहा है, जहां अनेक समस्याओं का समाधान शेष है। आज पर्यावरणीय गिरावट, सामाजिक अन्याय और शासन-प्रशासन की विफलताओं से निपटने के लिए संतुलित व निर्णायक न्यायिक पहल की बड़ी जरूरत है।

गंभीर चिंता के मामलों में अदालतों द्वारा स्वतः संज्ञान लेना बेशक सराहनीय है, लेकिन अनेक मामलों में उसके क्रियान्वयन में कमी निराश कर देती है। एक और उदाहरण देखिए, मणिपुर में जातीय संघर्ष के बीच यौन हिंसा पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया स्वतः संज्ञान के बाद एक समिति का गठन और मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपना यह तो दर्शाता ही है कि पूर्वोत्तर की समस्या को शीर्ष स्तर पर गंभीरता से लिया गया है। हालांकि, अदालत के निर्देशों का कमजोर क्रियान्वयन वास्तव में व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता है। पुनर्वास प्रयास और सांप्रदायिक सद्भाव की बहाली अनिवार्य है, पर इस दिशा में प्रगति धीमी और अपर्याप्त है, जिससे अनेक पीड़ितों को लंबे समय से संकट में रहना पड़ रहा है। ये कमियां न्यायिक निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मजबूत तंत्र की जरूरत पर भी प्रकाश डालती हैं, ताकि न्याय अदालती कक्षों से परे उन लोगों तक पहुंचे, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

आदर्श स्थिति तो यही है कि ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय अपने और उच्च न्यायालयों, दोनों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करे। अदालती आदेशों का जमीन पर ठीक से क्रियान्वयन हुआ या नहीं, यह जांचने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसे कदम से ही न्यायिक विश्वसनीयता व प्रभावशीलता को बल और बढ़ाया मिलेगा।

(सहयोगी लेखक प्रदीप एस मेहता)

मनसा वाचा कर्मणा

निश्छल भक्ति का वरदान

एक मध्ययुगीन किंवदंती है कि जिसे हम आज ऑस्ट्रिया के नाम से जानते हैं, वहां एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में बर्कहार्ड पेंतीर्ते और उनका बेटा तीन ही लोग थे। क्रिसमस पार्टियों में वे तीनों कविताएं सुनाकर, पुराने गीत गाकर और करतब दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। उनके पास उपहार खरीदने के कभी पैसे नहीं बचते, लेकिन पिता हमेशा अपने बेटे से कहता- 'जानते हो, दुनिया में इतने सारे बच्चे होने के बावजूद सांता क्लॉज का थैला कभी खाली क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें खिलौनों के अलावा बांटने के लिए और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जिनको हम अदृश्य उपहार कहते हैं। ईसाई धर्म की सबसे पवित्र रात सांता किसी टूटे घर में सद्भाव व शांति लाने की कोशिश करता है; जहां प्यार की कमी होती है, वहां बच्चों के हृदय में विश्वास के बीज बोता है। जहां भविष्य अंधकारमय व अनिश्चित लगता है, वहां वह आशा लेकर पहुंचता है। हमारे मामले में फादर क्रिसमस के अगले दिन हमसे मिलने आते हैं। कभी मत भूलना कि हम सब जीवित हैं और अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम है, लोगों को खुश करना।'

समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया और एक दिन जब वह परिवार प्रभावशाली मेल्क एबे (ईसाई मठ) के सामने से गुजर रहा था, तो युवा बर्कहार्ड ने पादरी बनने की चाहत जताई। परिवार ने उसकी इच्छा का सम्मान किया। उन्होंने मठ के दरवाजे पर दस्तक दी। पादरियों ने उनका उदारतापूर्वक स्वागत किया और युवा बर्कहार्ड को एक नौसिखिए के रूप में स्वीकार कर लिया।

क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मेल्क में एक चमत्कार हुआ। यीशु को अपनी गोद में लिए वर्जिन मैरी ने मेल्क का दौरा करने के लिए धरती पर उतरने का फैसला किया। वर्जिन के अभिवादन के लिए सभी पादरी कतारबद्ध हो गए। उनमें से प्रत्येक वर्ष के साथ उनकी स्तुति करता रहा। कतार के अंत में खड़े युवा बर्कहार्ड को अपनी बारी का इंतजार था। मगर उसे तो प्रार्थना आती ही नहीं थी। उसके माता-पिता ने उसे सिर्फ करतब दिखाना सिखाया था। जब उसकी बारी आई, तब अन्य पादरी प्रार्थना की प्रक्रिया खत्म कर देना चाहते थे, क्योंकि बर्कहार्ड के पास उसमें जोड़ने के लिए कुछ भी न था।

युवा बर्कहार्ड के लिए यही वे अनुपम क्षण थे, जब वर्जिन मैरी ने मुस्कराते हुए यीशु को अपनी गोद में लेने का सौभाग्य देने के लिए बर्कहार्ड की ओर अपनी बांहें फैला दीं!

फिर भी, बर्कहार्ड के हृदय में यीशु व वर्जिन मैरी को कुछ न कुछ अर्पित करने की उत्कंठा जगी। अपने साथियों की तिरस्कारपूर्ण दृष्टि को सहते हुए उसने जेब से कुछ संतरे निकाले और उन्हें वह हवा में उछालने व पकड़ने लगा। इससे हवा में एक सुंदर घेरा बन गया। मैरी की गोद में लेटे यीशु खुशी से ताली बजाने लगे। युवा बर्कहार्ड के लिए यही वे अनुपम क्षण थे, जब वर्जिन मैरी ने मुस्कराते हुए यीशु को कुछ पलों के लिए अपनी गोद में लेने की अनुमति दी और अपनी बांहें बर्कहार्ड की ओर बढ़ा दीं!

पाउलो कोएल्हो

ओम बिरला | लोकसभा अध्यक्ष

जलवायु परिवर्तन आज दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है और इससे निपटने में पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली सबसे कारगर उपाय है। मुझे आशा है कि हमारे युवा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

अब तो टीम को बख्श दें रोहित-विराट

लगभग पूरे साल भर से भारतीय क्रिकेट टीम के दो दिग्गज खिलाड़ियों- विराट कोहली और रोहित शर्मा -के खेल में काफी अधिक गिरावट आ गई है। आज जब इन दोनों बड़े खिलाड़ियों को अपने अच्छे प्रदर्शन से टीम के युवा क्रिकेटरों का उत्साह बढ़ाना था, उनका मार्गदर्शन करना था, तब एक-दो मौकों को छोड़कर इन दोनों ने लगातार लचर बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। ये दोनों वरिष्ठ क्रिकेटर अपनी पारियों में कभी 15 से 25 के बीच, तो कभी 30 से 40 रन के बीच पवेलियन लौटते रहे हैं। इन्होंने काफी लंबे समय से निरंतरता के साथ बड़े स्कोर नहीं बनाए। इनके कमजोर प्रदर्शनों का पूरी टीम इंडिया के प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ रहा है। जाहिर है, जिन खिलाड़ियों को टीम का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है, अगर वे ही यूं घराशायी होते रहेंगे, तो युवा खिलाड़ियों का मनोबल कमजोर होगा ही। शुरुआती बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने से बाद के क्रम में आने वाले खिलाड़ियों पर दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में, टीम का बिखर जाना बहुत स्वाभाविक है। यह एक स्थापित तथ्य है कि किसी भी टीम की पारी की शुरुआत अच्छी होने पर बाद के खिलाड़ी दबाव-मुक्त होकर बल्लेबाजी करते हैं और उनका खेल एक बड़े स्कोर में तब्दील हो जाता है, मगर चाहे रोहित शर्मा हों या फिर विराट कोहली, पिछले कई टेस्ट मैचों से इन दोनों का योगदान टीम के कुल स्कोर में नहीं के बराबर रहा है।

टेस्ट मैचों को तो छोड़िए, अब एकदिवसीय मैचों में भी इन दोनों के बल्ले खास जौहर नहीं दिखा पा रहे। ऐसे में, इन दोनों के बारे में आज यही कहने का दिल करता है कि प्लीज रोहित, प्लीज विराट, अब आप दोनों अच्छे मुहूर्त देखकर अपने-अपने बल्ले को विराम दे ही दीजिए। जब तक आप दोनों टीम इंडिया की कमजोर कड़ी बनकर खेलते रहेंगे, तब तक उभरती हुई टीमों को टेस्ट और एकदिवसीय मैचों में खेलने के अवसर नहीं मिल सकेंगे।

यह ठीक है कि आज भी रोहित शर्मा और विराट कोहली का काफी नाम है, मगर यदि ज्यादा समय तक इन दोनों का कमजोर कड़ी वाला औसत दर्जे का प्रदर्शन जारी रहा, तो फिर इससे इनकी प्रतिष्ठा पर भी काफी बुरा असर पड़ेगा और ये दोनों इसी तरह से लगातार आलोचना के शिकार बनते रहेंगे। हम तो यही कहेंगे कि आप दोनों का क्रिकेट अब खत्म हो गया है। आप दोनों को क्रिकेट प्रशंसक टीम पर बोझ समझने लगें, इससे पहले खुद ही किनारे हो जाएं। अब बस कर दीजिए विराट कोहली, बस कर दें रोहित शर्मा!

एम एम राजावत राज, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
क्रिकेट के दिग्गज

अपने दिग्गजों का यूं अपमान न करें

हम भारतीयों में एक बड़ी खराब बीमारी यह है कि हम पल भर में ही किसी को अपने सिर पर बिठा लेते हैं और फौरन उसे अपनी नजरों से गिरा भी देते हैं। यह प्रवृत्ति एक सभ्य, स्थिर समाज की नहीं है। खासकर क्रिकेट में हम देखते हैं कि टीम इंडिया यदि एक मैच शानदार तरीके से जीत ले, तो हमारे क्रिकेटरों की शान में ऐसे-ऐसे जुमले गढ़ लिए जाते हैं कि खुद ये क्रिकेटर झेंप जाएं, लेकिन अगले मैच में हार मिलते ही उनकी लानत-मलामत शुरू हो जाती है। यह प्रवृत्ति बहुत पुरानी नहीं है। इन दिनों आलोचकों के निशाने पर रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं।

खेल में उतार-चढ़ाव एक बहुत स्वाभाविक बात है। याद कीजिए सचिन तेंदुलकर के करियर को, उनके सौवें शतक के लिए कितना इंतजार किया गया था? मगर विराट-रोहित के प्रदर्शन को खेल भावना से लेने के बजाय प्रशंसक और आलोचक अपने मर्म पर प्रहार के रूप में लेने लगे हैं और उन्हें इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, जैसे उन्होंने कोई संगीन अपराध कर दिया है। लोग उनकी महान पारियों और भारतीय क्रिकेट के गौरवशाली अध्याय में उनके योगदान को बिसरा बैठे हैं? कोहली ने अपनी टीम के लिए टेस्ट व एकदिवसीय मैचों में कुल 80 शतक जड़े हैं? ट्वंटी-20 और आईपीएल मैचों के शतक जोड़ दें, तो यह आंकड़ा 89 हो जाता है। दुनिया के कितने क्रिकेटरों के नाम यह गौरव है? इन दिनों उन्हें वे लोग भी विराट और रोहित को संन्यास लेने की सलाह दे रहे हैं, जिन्हें क्रिकेट के सारे नियम-कायदे भी ढंग से मालूम न होंगे।

इसमें कोई दोराय नहीं कि खराब प्रदर्शनों की समीक्षा और स्वस्थ आलोचना होनी ही चाहिए, इससे न सिर्फ संबंधित खिलाड़ी पर अपना प्रदर्शन सुधारने का एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है, बल्कि इससे दूसरे तमाम खिलाड़ियों को भी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। मगर आलोचकों द्वारा इन दोनों दिग्गजों की निजी जिंदगी और उनके परिजनों को अपनी आलोचना में खींचना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। खासकर विराट कोहली इस ओछेपन के सबसे ज्यादा शिकार रहे हैं। ऐसी आलोचना प्रदर्शन सुधारने का सकारात्मक दबाव बनाने के बजाय खिलाड़ी को विचलित करती है, उनके मनोबल तोड़ती है। इससे न खिलाड़ी का फायदा होने वाला और न टीम इंडिया का। इसलिए आलोचकों से यही गुहार लगाई जा सकती है कि आपने इन दोनों को काफी लंबे समय तक सिर-आंखों पर बिठाया है, इसी का ख्याल करते हुए कम से कम आलोचना और अपमान के बीच अंतर बनाए रखें।

मेघना महतो, टिप्पणीकार

सम्पादकीय

नेहरूवादी मानवतावाद और भारत का विकास

नेहरू के युग (1950-64) में लागू विकास नीति की आलोचना राजनीति में ही नहीं हुई है बल्कि कुछ अर्थशास्त्री भी देश के प्रदर्शन का आकलन करते समय उसकी आलोचना करते हैं। नेहरू के युग की 4 फीसदी वृद्धि दर और 1980 के बाद की 6 फीसदी वृद्धि दर के बीच का बड़ा अंतर अक्सर याद दिलाया जाता है। मगर ध्यान रखें कि नेहरू के दौर में 4 फीसदी वृद्धि दर उस अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा ढांचागत बदलाव थी, जो उससे पहले के 100 साल में 1 फीसदी से भी कम रफ्तार से बढ़ी थी। विश्व बैंक के पास नेहरू के अंतिम सालों (1961-64) के तुलना करने लायक आंकड़े मौजूद हैं, जिनके मुताबिक उन सालों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 5 फीसदी थी। उस दौरान निम्न और मध्यम आय वाले देशों की औसत वृद्धि दर 4.3 फीसदी और दुनिया भर की औसत वृद्धि दर 5.2 फीसदी थी। वृद्धि में असली गिरावट नेहरू युग के बाद आई जब 1965-66 के भीषण खाद्य संकट ने विकास में रुकावट डाली। उसके बाद कांग्रेस में विभाजन, आपातकाल थोपे जाने के राजनीतिक असर और जनता पार्टी की विजय तथा पतन के कारण आई राजनीतिक अस्थिरता ने विकास के प्रयासों को और भी बेअसर किया। यहां ध्यान रहे कि 1962 में चीन के साथ युद्ध और 1965 तथा 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्धों ने भी विकास को पटरी से उतारे रखा। मगर 1980-81 के बाद औसत वृद्धि दर 6 फीसदी पर बनी रही।

नेहरू के जमाने की वृद्धि दर और 1980-81 से छह फीसदी की औसत वृद्धि दर के बीच अंतर की वजह अक्सर नेहरू के दौर की एक खास नीति को बताया जाता है। कहते हैं कि नेहरू ने उन उद्योगों पर जोर दिया, जो आयात होने वाले माल को देश में ही बनाते। इस वजह से श्रम के अधिक इस्तेमाल से बनने वाले माल के निर्यात के मौकों का फायदा नहीं उठाया जा सका, जबकि उससे विनिर्माण में रोजगार तेजी से बढ़ता। 1951 में मिल में बने कपड़े के निर्यात की सबसे अधिक संभावना थी और हथकरघा बुनकरों को संरक्षण देने का राजनीतिक आंदोलन उसकी राह में बाधा बन गया। ध्यान रहे कि आजादी के पहले के कॉरपोरेट औद्योगिक विकास की दिशा काफी हद तक आयात ही रहे माल का उत्पादन करने की ओर थी और उससे व्यापार संरक्षण की मांग उठी। यह प्रवृत्ति विकास पर हमारे कंपनी जगत के नजरिये से कभी खत्म नहीं हुई है। 1950 में निर्यात पर निराशा का भाव इसलिए था क्योंकि उससे पिछले सालों में दुनिया भर में वस्तुओं का व्यापार तहरा हुआ था। 1948 में 58.5 अरब डॉलर का वैश्विक वस्तु व्यापार हुआ था, जो 1949 में 58.6 अरब डॉलर और 1950 में 61.5 अरब डॉलर तक ही पहुंच पाया। विश्व व्यापार में जिस वृद्धि ने खास तौर पर पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के निर्यात को रफ्तार दी, वह 1960 के बाद ही दिखी थी। विकसित दुनिया ने भी 1950 में विकासशील देशों की संभावनाओं में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई। 1950 के दशक की शुरुआत में यूरोप के देश और रूस दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका से उबर ही रहे थे। अमेरिका भी मार्शल प्लान के साथ यूरोप को पटरी पर लौटाने में जुटा था।

निस्तेज विपक्ष देश को कब तक अंधेरों में धकेलेगा?

बाबा साहेब आंबेडकर पर घडियाली आंसू बहाने वाला विपक्ष एवं विशेषतः कांग्रेस यह भूल रही है कि आंबेडकर का सर्वाधिक अपमान एवं उपेक्षा इन्हीं दलों ने की है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आंबेडकर को पसन्द नहीं करते थे। क्योंकि आंबेडकर मुस्लिम तुष्टिकरण की कांग्रेस नीति से नाखुश थे। उनका मत था कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ है, अतः सभी मुस्लिम को भारत छोड़ देना चाहिए? गांधी और नेहरू ने इस विचारधारा का विरोध किया? गांधी तो विरोध में भूख हड़ताल पर बैठ गए? बाबा साहेब ने गांधी से समझौता कर संविधान को मुस्लिम के अनुसार ड्राफ्ट कर दिया? फिर भी नेहरू बाबा साहेब के विरुद्ध लगातार लगे रहे।

ललित गर्ग

विपक्ष बात-बात पर तू-तू, मैं-मैं करते हुए बात का बतंगड़ बनाकर देश का भारी नुकसान कर रहा है। संसद को चलने नहीं दे रहा है, आधे-अधूरे बयान के हिस्से को प्रचारित कर घटिया एवं सस्ती राजनीति करते हुए देश को गुमराह कर रही है। बेबुनियाद एवं भ्रामक मुद्दों को उछाल कैसे गुल खिलाये, कैसे देश को अंधेरों में धकेला जाये, इसी फिराक में कांग्रेस एवं समूचा विपक्ष दिनरात लगा है, इसका प्रमाण है गत दिवस संसद में गृह मंत्री अमित शाह के डा. आंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर विपक्ष का हंगामा, तीखी नोकझोंक एवं होहल्ला। इस हंगामे का आधार यह है कि गृह मंत्री ने यह कह कर आंबेडकरजी का अपमान कर दिया कि यदि आंबेडकर, आंबेडकर करने वाले इतना नाम भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मुश्किल यह है कि हंगामा करने वाले यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ऐसा कहने से आंबेडकरजी का अपमान कैसे हो गया? विडम्बना देखिये कि आजादी के बाद से अब तक आंबेडकर का अपमान करने, तिरस्कार करने एवं उनकी उपेक्षा करने वाला दल एकाएक उनका हितायती कैसे हो गया? यह सारा हंगामा विपक्ष इसलिये कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भारतीय जनता पार्टी ने आंबेडकर को शीर्ष राष्ट्रनायकों में शुमार कर किया है और उनकी नीतियों, सिद्धान्तों एवं मूल्यों को राजनीति का अहम हिस्सा बनाया है। विपक्ष डरा हुआ है कि भाजपा आंबेडकर को आजादी के बाद प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह के बाद उचित स्थान देकर दलित समुदाय के हितों की वास्तविक चिन्ता की है, जिससे दलित वोट भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। इसलिये शाह के बयान को तोड़-मरोड एवं आधा-अधूरा प्रस्तुत कर बेवजह का हंगामा करने पर तुले विपक्ष एवं उनके नेताओं ने जो एवं जैसे तर्क दिए हैं, वे विचित्र ही नहीं, हास्यास्पद भी हैं।

आंबेडकर के चुनाव लड़ने पर नेहरू ने उनके खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी खड़ा कर उन्हें हरवा दिया? विडम्बना देखिये कि आंबेडकर के सचिव नारायण सदोबा काजरोलकर को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने न केवल दो बार उन्हें चुनाव में हराया बल्कि केन्द्र सरकार में उनकी घोर उपेक्षा लगातार जारी रखी। इसी से नाराज होकर आंबेडकर ने मंत्री पद से इस्तिफा देते हुए नेहरू पर गंभीर आरोप लगाये। इतना ही नहीं आंबेडकर ने स्वयं के बनाये संविधान को जला देने की बात भी इसलिये कही थी कि संविधान का संचालन गलत हाथों में है। इतिहास को इन त्रासद एवं विसंगतिपूर्ण स्थितियों के बावजूद आखिर कांग्रेस किस आधार पर आंबेडकर की तस्वीरें लेकर संसद परिसर में विरोध कर रही है। अपने आरोप को पुष्ट करने के लिए विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस नेता गृह मंत्री के बयान के एक हिस्से को तो प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन उसके शेष हिस्से को सुनने के लिए तैयार नहीं, जिसमें उन्होंने कहा था कि डा. आंबेडकर का नाम लेने वालों ने किस तरह उनके विचारों के खिलाफ काम किया और उन्हें अपमानित करने में भी संकोच नहीं किया। लगता है कांग्रेस को यही नागवार गुजरा और इसी कारण वह संसद के भीतर-बाहर इस मामले को तूल देने में जुट गई। इसे तूल देने के लिए उसके नेताओं की ओर से संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा बरपाया कि दोनों दलों के सांसदों के बीच मकर द्वार पर धक्कामुक्की में भाजपा सांसद प्रताप सारंगी के सिर में चोट देखी गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल सांसद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, जो मेरे ऊपर गिरे। आरोप पर जवाब देते हुए राहुल ने कहा कि हां! ऐसा हुआ। वे हमें प्रवेश द्वार पर रोकने की कोशिश रहे थे। ये तर्क एवं त्रासद स्थितियां संसदीय गरिमा को धुंधलाने वाली है। कांग्रेस के तर्कों का स्तर न केवल राजनीतिक विमर्श का गिराने वाला ही नहीं, बल्कि यह बताने वाले भी हैं कि नेतागण किस तरह तिल का ताड़ बनाने में माहिर हो गए हैं। कांग्रेस भाजपा के बारे में तथ्यहीन एवं भ्रामक अफवाहें फैला रही है। कांग्रेस नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक गरीब और बेरोजगारी का गीत गाते रहे हैं, लेकिन उनके शासनकाल में न तो गरीब खत्म हुए और न बेरोजगारी? नीयत में खोट और अनुभवहीनता का जब सत्ता प्राप्ति के संदर्भ में समन्वय हो जाता है, तो ऐसी हास्यास्पद स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। भारत की राजनीति में इस समय यही स्थिति बन गई है।

राजनीतिक बहस का स्तर इतना छिछलादार, स्तरहीन एवं बेबुनियाद नहीं होना चाहिए। झूठ को जोर-जोर से चिल्लाकर कहने से वह सच नहीं हो जाता। यह अच्छा हुआ कि गृह मंत्री ने अपने बयान पर कोई सफाई देने के बजाय दो टूक यह कहना उचित समझा कि उनके पूरे वक्तव्य को सुना जाए। वैसे यह तय है कि विपक्षी नेता ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि उन्हें यही साबित करना है कि आंबेडकरजी का अपमान हो गया, संविधान खतरे में आ गया इसलिये गृहमंत्री को अपने पद से इस्तिफा दे देना चाहिए। आखिर इसे मूर्खतापूर्ण राजनीति न कहा जाए तो क्या कहा जाए? इस पर हैरानी नहीं कि राहुल गांधी को फिर से यह नजर आने लगा कि मोदी सरकार संविधान बदलने जा रही है। कांग्रेस नेता गृह मंत्री के बयान को लेकर आसमान सिर पर उठाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वे इस सच को नहीं छिपा सकते कि उनके शासनकाल में डा. आंबेडकर की किस तरह उपेक्षा और अनदेखी की गई। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि जहां जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को तो उनके जीवनकाल में ही भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया, लेकिन आंबेडकरजी को यह सम्मान दशकों बाद 1990 में मिल सका। यहां तक संसद के केन्द्रीय कक्ष में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एवं इन्दिरा गांधी की तस्वीरें तभी लग गयी लेकिन आंबेडकर की तस्वीर वी.पी. सिंह ने प्रधानमंत्री रहते लगायी गयी। क्या कांग्रेस बता सकेगी कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों आंबेडकर की लगातार उपेक्षा होती रही?

डा. आंबेडकर ने 25 नवंबर, 1949 के अपने ऐतिहासिक भाषण में यह कहा था कि संविधान कितना अच्छा होगा, यह आगे चलकर उसे चलाने वालें सत्ता नेतृत्व की मानसिकता एवं नीयत पर निर्भर करेगा। 1975-77 में यह शब्दशः सत्य सिद्ध हुआ, जब पद पर बने रहने की लालसा ने संविधान के साथ अत्याचार करते हुए आपातकाल लागू किया गया, जिसे इतिहास भूलेगा नहीं। लेकिन आज जो संविधान बचाने का शोर सुनाई दे रहा है और जिसकी प्रति संसद से संभल तक लहराई जा रही है, वह देश का ध्यान भटकाने की कोशिश मात्र है, जनता को गुमराह करने की कुचेष्टा मात्र है। निश्चित ही यह दयनीय, विडम्बनापूर्ण एवं त्रासद है कि सत्ता पाने के लिए व्याकुल लोगों की व्यग्रता अब घातक उग्रता के रूप में प्रकट हो रही है।

संसद के कार्य संचालन में जैसे व्यवधान डाले जा रहे हैं, वे न तो भारत के संविधान के प्रति कोई आदरभाव प्रकट करते हैं, न ही आंबेडकर के प्रति कोई श्रद्धा प्रकट करते हैं। आज हमारे विपक्ष के पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो इस स्थिति से देश को बाहर निकाल सके, राष्ट्रीय चरित्र को जीवित रखने का भरोसा दिला सके। प्रश्न है कि निराश करने वाला विपक्ष देश को कब तक अंधेरों में धकेलता रहेगा?

आज का राशिफल

जगद्गुरु आदिशंकराचार्य की टीका के अनुसार आज कई विशिष्ट लग्नों को पूरा करेंगे। ध्यान आज यह लक्ष्यता चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे पीड़ाओं होंगे है, जब आपके विरोधी कुचर लोगों और दुष्टों तक, आपके चित्त बातों से लाचारता लगता रहेगा। लग्न से किसी कार्यों के और महीन सूत्रों को खुलकर रखा लक्ष्यकारक ऊर्जा की लाकृष्ट करेंगे, शनिवार कुप्रभावित लग्नों में भी, जहां तक लक्ष्यकारक सही संकेत और कार्यों में लाभ प्रदान करेगा

मेष
किसी के साथ गलतफहमी होने के कारण मनमुटाव हो सकता है। पारिवारिक वातावरण खराब हो सकता है। अत्यधिक धन खर्च होगा। भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ निर्णय के कारण आज आप कोई भी काम त्वरित निर्णय लेकर पूरा करेंगे।

वृष
विरोधियों से विजय प्राप्त करेंगे। दिन के दौरान आकस्मिक घटनाओं में व्यस्त रहेंगे। परिणामस्वरूप मन में नकारात्मक विचार पैदा होंगे। नौकरी-धंधे में उच्च अधिकारी या भागीदार के क्रोध का शिकार बनना पड़ेगा।

मिथुन
शारीरिक अस्वस्थता के साथ-साथ मानसिक चिंता में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव होगा। उग्र वाणी और अहं के टकराव से किसी के साथ झगड़े या विवाद की स्थिति बन सकती है।

कर्क
पिता तथा अभिभावकों का सहयोग प्राप्त होगा। मन आनंदित रहेगा। फिर भी स्वभाव में उग्रता का असर आपकी वाणी पर न पड़े, इसका ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी मामूली शिकायत रहेगी। भाग्य साथ न देता हुआ प्रतीत होगा।

सिंह
व्यवसाय करने वालों को सरकार की तरफ से लाभ मिलने और नौकरीपेशा को उच्च अधिकारियों की कृपादृष्टि मिलेगी। भाई-बंधुओं और पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।

कन्या
गृहस्थ जीवन में आनंद छाया रहेगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी-व्यवसाय में प्रगति होगी। अधिकारी और घर में बड़ों से लाभ मिलेगा। धन लाभ होगा। व्यापारियों को उधार दिया पैसा मिलेगा। संतान की प्रगति से मन खुश रहेगा। लंबे प्रवास का आयोजन संभव होगा।

तुला
आप पूरे दिन शारीरिक और मानसिक थकान महसूस करेंगे। परिश्रम की अपेक्षा कम सफलता मिलने से निराशा रह सकती है। नौकरी और व्यापार के संबंध में थोड़ा चिंतित रहेंगे। काम की भागदौड़ में परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे।

वृश्चिक
गृहस्थ जीवन में सुख-शांति का अनुभव होगा। मित्रों से मुलाकात होगी। आय में वृद्धि होगी। उत्तम वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। अविवाहितों का रिश्ता पक्का होने की संभावना बनी रहेगी। आज आपके हरेक कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे।

धनु
शारीरिक स्वास्थ्य बना रहेगा। मित्रों, स्नेहीजनों से लाभ होगा। शरीर में थकान और बेचैनी रहेगी। स्वास्थ्य नरम-गरम रहेगा। मन चिंता से व्याकुल रहेगा। आज यात्रा स्थगित रखने की सलाह दी जाती है। संतान के विषय में चिंता रहेगी।

मकर
आज यात्रा को टालना हित में होगा। पाचन तंत्र संबंधी कोई तकलीफ हो सकती है। आपके व्यवहार से किसी को हानि न पहुंचे, इसका ध्यान रखें। आज आप सभी काम दृढ़ आत्मविश्वास और मनोबल से पूरा करेंगे।

कुंभ
कोर्ट-कचहरी का कामों को आज टाल देना हितकर है। आज विविध क्षेत्र में लाभ मिलने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रफुल्लित रहेंगे। मित्रों के साथ मुलाकात, रमणीय स्थानों पर प्रवास पर्यटन का आयोजन होगा।

मीन
विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। संतान के अध्ययन या अन्य मामलों के पीछे धन खर्च या पूंजी निवेश होगी। कलाकारों तथा खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का उत्तम समय है। सरकार से लाभ होने की संभावना है। आंख संबंधी शिकायत पैदा होगी।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

नमस्कार साथियों हमारी आज के कॉलम के सुपर स्टार हैं भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉ.अमनदीप सिंह कपूर। डॉक्टरी की हुई है वो भी सर्जरी और मेडिसन में तो जब अपराध रोकने का जिम्मा उठाया तो अपराधी को पहले दवाई देंगे और फिर भी दुरूस्त नहीं हुआ तो ऑपरेशन कर देंगे। भिवाड़ी में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए जैसे ही सरकार ने डॉ.अमनदीप सिंह जी को लगाया आधे से अधिक छुटभैया अपराधी पतली गली से निकल लिए और नामचीन अपराधियों का क्या हर्ष हुआ ये सोशल मीडिया के माध्यम से जगजाहिर है। शानदार जाँबाज और दिलेर अधिकारी के रूप में डॉ.अमनदीप सिंह को जाना जाता है। 24 जनवरी सन 1977 को यमुना नगर में जन्में, अमनदीप जी बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। एमबीबीएस (मेडिसिन एवं सर्जरी) के बाद पुलिस सेवा में आए और आज निदेशक है केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय भारत सरकार। इससे पूर्व ये सहायक निदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली रहें। उपमहानिरीक्षक पुलिस, एटीएस एण्ड एसओजी जयपुर। पुलिस अधीक्षक, भरतपुर। पुलिस अधीक्षक, भिवाडी अलवर। पुलिस उपायुक्त, क्राइम, आयुक्तालय जयपुर। पुलिस अधीक्षक, सीकर। पुलिस उपायुक्त पूर्व पुलिस आयुक्तालय, जोधपुर। पुलिस अधीक्षक, बीकानेर। पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण निरोधक ब्यूरो कोटा। कमाण्डेन्ट, सैकिंट्र बटालियन आरएसी कोटा। पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर कोटा। पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर पूर्व पुलिस आयुक्तालय जयपुर। पुलिस अधीक्षक, करौली। पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा। पुलिस उपायुक्त, अपराध जयपुर कार्यालय पुलिस आयुक्त, जयपुर। पुलिस अधीक्षक, गुप्तचर विभाग जयपुर। सहायक अधीक्षक पुलिस, वृत्त ब्यावर अजमेर। जिला प्रशिक्षण, अजमेर के अंतर्गत रहे। बेहद शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। पूरी फॉस में डॉ.अमनदीप सिंह के जाने(स्थानंतरण) के बाद उनकी सार्थक चर्चा इस बात का गवाह है कि पुलिसकर्मियों के प्रति कितने शानदार रहे हैं। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

डॉ.अमन दीप सिंह कपूर
(भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी)

रूपक शर्मा

आज का इतिहास

20 दिसंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- लार्ड क्लाईव को 1757 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया।
- ब्रिटेन ने 1780 में हालैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
- ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रूस ने 1830 में बेल्जियम को मान्यता प्रदान की।
- महान कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1876 में राष्ट्र गीत 'वंदे मातरम' की रचना की।
- अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा ने 1919 में आव्रजन पर रोक लगाई।
- बेगर फैटरनिटि (संयुक्त राज्य अमेरिका के जेसुइट कॉलेज में स्थापित पहली सामाजिक बिरादरी) की 1923 में 9 लोगों ने स्थापना की जो पोप से ऐसा करने की अनुमति हासिल कर चुके थे।
- जर्मनी में 1924 में एडोल्फ हिटलर की जेल से रिहाई।
- महात्मा गांधी 1946 में श्रीरामपुर में एक महीने तक रूके।
- ओमान और ब्रिटेन के बीच समझौते के बाद 1951 में ओमान स्वतंत्र हुआ।
- भारतीय गोल्फ संघ का 1955 में गठन।
- अमेरिका में 1956 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बसों में होने वाले रंगभेद पर रोक लगाई जानी चाहिए।
- गोरख प्रसाद ने 1957 में पदमुक्त होकर नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा संचोजित 'हिंदी विश्वकोश' का संपादन भार ग्रहण किया।
- भारतीय गेंदबाज जासू पटेल ने 1959 में कानपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 69 रन देकर नौ विकेट लिए।
- जर्मनी में बर्लिन की दीवार को 1963 में पहली बार पश्चिमी बर्लिनवासियों के लिए खोला गया।
- जरनल याह्या खाँ द्वारा 1971 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र, जुल्फिकार अली भुट्टो राष्ट्रपति बने।
- यूरोपीय देश स्पेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री एडमिरल लुईस करेरो ब्लांको की 1973 में मैड्रिड में एक कार बम हमले में मौत।
- इजरायल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यित्जाक राबिन ने 1976 में अपने पद से इस्तीफा दिया।
- तिरूपति बालाजी मंदिर में 1985 में भगवान वैंकटेश्वर को 5.2 करोड रुपये की कीमत वाला हीरा जडित मुकुट चढ़ाया गया।
- संसद ने 1988 में 62वें संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 साल करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी।
- भारत और पाकिस्तान 1990 में एक दूसरे पर परमाणु हमले न करने पर सहमत हुए।
- पॉल कीटिंग 1991 में आस्ट्रेलिया के नये प्रधानमंत्री बने।
- भारत और यूरोपीय संघ के बीच 1993 में ब्रसेल्स में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गये।
- सन 1998 में 13वें एशियाई खेलों का रंगारंग समापन, बिल क्लिंटन एवं कैनेथ स्टार को 'स्टार टाइम पत्रिका' ने 'मैन आफ दी इयर' घोषित किया, चीन द्वारा इंडिडियम आधारित दो संचार उपग्रह छोड़े गये।
- अंतरिक्ष यान 'डिस्कवरी' 1999 में हबल टेलीस्कोप की मरम्मत हेतु रवाना।

विशेष आलेख

भारत में नवाचार और स्टार्टअप का उभरता युग अटल इनोवेशन मिशन

अवनीश कुमार गुप्ता

(एआईएम) भारत में नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो देश को तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने की दिशा में अग्रसर है। 2016 में स्थापित इस मिशन का उद्देश्य न केवल भारत को स्टार्टअप संस्कृति में अग्रणी बनाना है, बल्कि युवाओं के भीतर रचनात्मकता और समस्या-समाधान क्षमता का विकास करना भी है। हाल ही में एआईएम को 2028 तक विस्तारित करने की मंजूरी दी गई, जिससे इसके महत्व और प्रभाव को नई मान्यता मिली। लेकिन इस पहल की सफलता केवल इसकी योजनाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उन चुनौतियों और समाधानों पर भी आधारित है, जिनका सामना यह मिशन कर रहा है। यदि हम भारत के नवाचार इतिहास को देखें, तो पाएंगे कि आर्यभट्ट, चरक और सुश्रुत जैसे विद्वानों ने विज्ञान, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। लेकिन समय के साथ, विशेष रूप से औपनिवेशिक शासन के दौरान, यह नवाचार संस्कृति कमजोर पड़ गई। आज, एआईएम जैसे कार्यक्रम उसी सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस मिशन ने अटल टिंकरिंग लैब्स और अटल इनक्यूबेशन सेंटर जैसी पहलों के माध्यम से छात्रों और उद्यमियों को वैश्विक स्तर की तकनीकों से जोड़ने का कार्य किया है। अब तक देशभर में 10,000 से अधिक टिंकरिंग लैब्स स्थापित की गई हैं, जो छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और 3डी प्रिंटिंग जैसी उन्नत तकनीकों से अवगत कराती हैं। लेकिन एआईएम की इस सफलता के बावजूद इसकी राह में कई चुनौतियाँ हैं। सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक इसकी पहुँच सुनिश्चित करना है। नवाचार की जो सुविधाएँ शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध हैं, वे ग्रामीण बच्चों और युवाओं के लिए एक सपना भर हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कई प्रतिभाशाली छात्र हैं, लेकिन संसाधनों और मार्गदर्शन के अभाव में उनकी क्षमता व्यर्थ हो जाती है। इसके अलावा, भारतीय शिक्षा प्रणाली का अभी भी आँकों और रटंत पर केंद्रित होना भी एक समस्या है। नवाचार और समस्या-समाधान कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। इसके साथ ही, वित्तीय संसाधनों की कमी भी एक बड़ी बाधा है। एआईएम के तहत कई स्टार्टअप्स को प्रारंभिक सहायता मिली है, लेकिन देशभर में हजारों ऐसे नवोन्मेषक हैं जिन्हें अपने विचारों को साकार करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इसके अलावा, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भागीदारी अभी भी अपेक्षाकृत कम है। जब तक इन समूहों को विशेष रूप से प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, तब तक नवाचार का व्यापक और समावेशी विकास संभव नहीं है। इन समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जानी चाहिए। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है, जहाँ छात्र इंटरनेट और तकनीकी उपकरणों के माध्यम से आधुनिक तकनीकों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही, शिक्षा नीति में डिजाइन थिंकिंग और प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग जैसी विधाओं को शामिल किया जाना चाहिए। यह छात्रों को रचनात्मक सोच और व्यावहारिक कौशल प्रदान करने में मदद करेगा। निजी क्षेत्र की भागीदारी भी इस मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। बड़ी कंपनियों और गैर-सरकारी संगठनों को इस पहल में शामिल किया जाना चाहिए। यह न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, बल्कि तकनीकी संसाधनों को भी सुलभ बनाएगा। महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण और प्रोत्साहन कार्यक्रम भी चलाने चाहिए, ताकि वे नवाचार और उद्यमशीलता में अपनी भागीदारी बढ़ा सकें। स्थानीय संदर्भ में देखें तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहाँ बड़ी संख्या में युवा प्रतिभा उपलब्ध है, वहाँ अटल इनोवेशन मिशन को एक सशक्त मंच के रूप में उभरने की आवश्यकता है। लखनऊ, कानपुर, और वाराणसी जैसे शहरों में इनक्यूबेशन सेंटर और टिंकरिंग लैब्स को और अधिक विस्तार दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों और स्थानीय संगठनों की मदद से इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारत नवाचार सूचकांक में अभी 40वें स्थान पर है। यदि एआईएम जैसे मिशन को सही दिशा में आगे बढ़ाया जाए, तो भारत आने वाले वर्षों में शीर्ष 20 देशों में शामिल हो सकता है। इसके लिए मिशन को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और कृषि जैसे क्षेत्रों में अधिक ध्यान देना होगा। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। अटल इनोवेशन मिशन की मौजूदा उपलब्धियाँ यह साबित करती हैं कि भारत में नवाचार और उद्यमशीलता का भविष्य उज्वल है। लेकिन इसकी सफलता के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि यह पहल केवल योजनाओं तक सीमित न रहे, बल्कि इसे व्यावहारिक और समावेशी बनाया जाए। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों के साथ तालमेल बनाकर एआईएम को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। नवाचार केवल तकनीकी विकास का माध्यम नहीं है, यह एक सांस्कृतिक परिवर्तन है। यह समाज को उस दिशा में ले जाता है, जहाँ समस्याओं का समाधान नए दृष्टिकोण और रचनात्मकता के माध्यम से किया जाता है। अटल इनोवेशन मिशन इस दिशा में एक सशक्त प्रयास है, लेकिन इसे पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत, और समाज सभी को अपने-अपने स्तर पर योगदान देना होगा।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हमीरपुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतीक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान"। प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीसीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार